

Vol. I
No. 10



*Monday,
8th March, 1954*

HYDERABAD LEGISLATIVE ASSEMBLY DEBATES Official Report

PART II—PROCEEDINGS OTHER THAN QUESTIONS AND ANSWERS

CONTENTS

	PAGES
Budget—General Discussion	475-485
Business of the House	495 -
Budget—General Discussion—not concluded	495-527

10

11

12

13

THE HYDERABAD LEGISLATIVE ASSEMBLY

MONDAY, THE 8TH MARCH, 1954

The House met at Half Past Two of the Clock.

[MR. SPEAKER IN THE CHAIR]

Questions & Answers

(See Part I)

Budget—General Discussion

مسٹر اسپیکر .. اب سالات کا وقت ختم ہو چکا ہے ۔ اب بجٹ پر جنرل ڈسکشن شروع ہوگا .. ڈسکشن شروع ہونے سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ۸۔۹ اور ۱۔ مارچ ان تین دنوں میں ڈسکشن ختم ہو جانا چاہئے ۔ تیسرے دن میں مسجنتا ہوں کہ آنریبل فنانس منسٹر کو جواب کے لئے دیڑھ گنہ لگیگا ۔

مینسٹر فائر فائنانس، سٹینڈیٹس، کسٹمز، کامرس اँڈ انڈسٹریز (آئی. بی. کے)

کو رڈ کر) :—بیک ڈھکھا تو کافی ہو جائیگا ।

مسٹر اسپیکر ۔ ایک دوسری چیز میں عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ بجٹ پر ڈسکشن کے دوران میں جبکہ ڈپارٹمنٹس پر تنقید، دھوکے اسلئے گورنمنٹ کا کم سے کم ایک ممبر یہاں حاضر رہے ۔ تاکہ حکمران ڈسکشن پر توجہ کر سکے ۔ اس لئے کہ ڈسکشن کا مشا ہ ہی یہ ہوتا ہے کہ حکمران کے علم میں یہ باتیں لائی جائیں ۔ میں یہ نہیں مسجنتا کہ اپوزیشن پارٹی یا کسی اور پارٹی کی جانب سے خرابہ مزاح تو یہ سب باتیں نہیں کہنی جاتیں ۔ لیکن انکے انفرمیشن میں کچھ غلطی ہو لیکن گورنمنٹ کو سب باتوں سے پوری طرح واقف ہونا چاہئے ۔

آئی. رتنلال کوڈے (پاٹوڈا) :—میں بیک انفرمیشن (Information) پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہاں جو ڈسکشن ہوتے ہیں کیا انکے نوڈس کنسرن ڈیپارٹمنٹ کے پاس ہوتے ہیں ؟

مسٹر اسپیکر .. یہاں جو اسپیکر ہوتی ہیں انکا ہر لفظ لکھا جاتا ہے اسکی کاپیاں چھپی ہیں اور ہر ممبر کو اسکی کاپیاں ملتی ہیں ۔

آئی. رتنلال کوڈے :—میرا یہ سوچا ہے کہ یہاں جو ڈسکشن ہوتے ہیں انکے نوڈس کنسرن ڈیپارٹمنٹ کے پاس ہونے چاہئیں ۔

श्री. वि. के. कोरटकर :—डिस्कशन के नोट्स उसी वक्त कनसन्ड मिनिस्टर्स लेते हैं और उसके ऊपर जरूरी अक्शन (Action) लिया जाता है। हर डिपार्टमेंट को भेजने का तरीका नहीं है।

منسٹر فار میڈیکل پبلک ہیلتھ اینڈ رورل ری کنٹر کیشن (شری مہدی نواز جنگ)
اسکے علاوہ چیف منسٹر کا ایک سرکیورلر ہے کہ ہر ڈیپارٹمنٹ کے نمائندے یہاں موجود
ہیں اور متعلقہ باتوں کا نوٹ لیکر منسٹر کو اسکی اطلاع دیں ..

श्री. व्ही. डी. देशपांडे (अप्पागुडा) :—अध्यक्ष महोदय, असेंबली के पांच सालों में से तीसरे साल का बजट हमारे सामने आया है। इस वक्त पिछले सालों के बजट हमारे सामने किस तरह से आते रहे इसको देखें, तो वह नामुनासिब न होगा।

Mr. Speaker : Shall I fix time-limit? I generally wish to leave the matter to the discretion of the hon. Members.

श्री. व्ही. डी. देशपांडे :—वक्त का ख्याल रखा जायगा।

राजप्रमुख के अड्रेस (Address) के वक्त मैंने इस चीज को रखा था कि हिंदुस्तान में आज दो सोशल आर्डरों में एक कश्मकश जारी है, वह एक पुराना ढांचा और निजाम है जो हिंदुस्तान की बदतर हालत को जारी रखना चाहता है, उसी तरह से जो जमीनदारी ढांचा है उसको बरकरार रखना चाहता है, और हुकूमत जिन शक्तियों को अपने फायदे के लिये अस्तेमाल करना चाहती है।

(MR. DEPUTY SPEAKER IN THE CHAIR)

दूसरी वह बढ़ती हुआ कुव्वत है जो चाहती है कि जमीनदारी सिस्टम को खतम करें, सनयतों को बढ़ायें, बैरूनी सरमायेदारों के जरिये जो मुल्क में लूट-खसोट होती है उसको बंद करे, और यहां पर एक जैसी हुकूमत का ढांचा तैयार करें जो सस्ता हो, एफिशियंट (Efficient) हो, और अब्बाम के मसायल को बहुत जल्दी से और अच्छी तरह से हल कर सके। इस तरह से आज हिंदुस्तान में एक टग ऑफ वार (Tug of war) एक रस्ती खेंच, दो समाज रचनाओं में जारी है और जिसमें आज की हुकूमत दरमियान में खड़ी होकर क्या अब्बाम की स्वाहिशात को पूरा कर रही है, या जो चीजें दिन ब दिन खतम होती जानी चाहिये, कमजोर होती जानी चाहिये, उन्हें ब्रिमदाद कर रही है या नहीं इस लिहाज से आज की हुकूमत के कारनामों और जिस बजट की तरफ देखना पड़ेगा। पिछले साल से हम महसूस कर रहे हैं कि अब्बाम की जो मांगें हैं उनको पूरा करने के बारे में दिखावे के तौर पर हुकूमत की तरफ से वादे तो किये जाते हैं लेकिन उसके साथ साथ हुकूमत का दूसरा भी मूव (Move) है जो जिस स्टेटस को (Status quo) की तरफ, जिस फ्यूडल सिस्टम (Feudal system) की तरफ मुड़ा हुआ है, और उनका नुकसान कम से कम हो, और उनके स्वाहिशात और फायदे जहां तक होसके कायम रखसके जिसलिये हुकूमत भरसक कोशिश करती रहती है। अगर मैं यह कहूं तो गलत न होगा कि हुकूमत के दो मुंह, टू फेसेस (Two faces) हैं एक अब्बाम की तरफ है और दूसरा जागीरदारों, बड़े बड़े कारखानदारों और विदेशी सरमायेदारों की तरफ है। मुझे जिसमें शक नहीं कि जिस रस्तीखेंच में आखिर अब्बाम की कुव्वतें कामयाब होंगे ..

वाली है, लेकिन सवाल सिर्फ यह है कि हिंदुस्तान के अंदर जो एक नया समाज, एक नया स्टेट, पीपल्स डेमोक्रेटिक स्टेट (People's Democratic State) कायम करना है, क्या वह जिस पुराने ढांचे के अंदर आसानी से होगा या उसके लिये आपरेशन करना होगा। जिस लिहाज से हुकूमत के कारनामों और जिस बजट की तरफ देखता हूं। अब्बाम की कुव्वतों ने अब तक कुछ थोड़ी सी कामयाबी हासिल की है, यह मैं हाबुस के सामने रखना चाहता हूं। पिछले दो साल से हम जिस चीज की मांग कर रहे थे कि सफ़ाई का जो ५० हजार रुपये का मुआवजा है जोकि आय. जी. में करीब करीब ४२ लाख होता है उसको खतम करना चाहिये। अब्बाम की जिस मुसलसिल मांग की वजह से हम जिस वक्त जिस बजट में देख रहे हैं कि जिस साल हुकूमत ने मजबूर हो कर आल्ट्र हजरत-जो राजप्रमुख का अर्द्ध में तर्जुमा है-वह कैसे बनाया गया है मालूम नहीं-लेकिन उसमें करीब करीब २१ लाख रूपयों की कमी की गयी है। दूसरी बात कैश ग्रांट्स (Cash grants) और मनसब के तौर पर हर साल जो रकम दी जाती है उनको भी खतम करना चाहिये यह भी अब्बाम की पुरजोर मांग रही है। जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया फ्यूडल ओलीमेंट्स (Feudal elements) को जिस हद तक हो सके डिफेंड (Defend) करने का जिस हुकूमत का एक पेशा-सा हो गया है। उसके लिहाज से हालांकि हुकूमत की तरफ से हाबुस के सामने वादे किये जाते हैं लेकिन वे पूरे नहीं होते। पिछले साल बजट के वक्त बताया गया था कि ये १३ लाख रुपये देना बंद किया जायगा लेकिन सप्लीमेंटरी बजट के वक्त यह कहा गया कि बहुत सी कानूनी पेचीदगियों की वजह से हम जिस वादे को पूरा नहीं कर सके और यह वायदा किया गया कि आयंदा साल हम जिसको खतम करेंगे। जिस तरह से मैं हाबुस के सामने यह रख रहा था कि किस तरह की कम्पकश दो समाजरचनाओं के बीच आज चल रही है। अब्बाम की कुव्वतें फ्यूडल सिस्टम को खतम करना चाहती हैं, और आज की हुकूमत के लोग जिसको डिफेंड (Defend) करना चाहते हैं। अपरी तौर पर कहा जाता है कि हम जिसको खतम करना चाहते हैं लेकिन अमलन जिसको सेबोटेज (Sabotage) किया जाता है। पिछले दो साल का हमारा अनुभव यही रहा है और अब तीसरा बजट हमारे सामने आया है। जिस साल में क्या बात होनेवाली है जिसका आज हमें पता नहीं है। शायद फायनान्स मिनिस्टर साहब यह कह दें कि जिस वक्त भी यह कानून न बन सका जिसलिये जिसको हम खतम नहीं कर सके। जिसके बाद जमीनदारी सिस्टम को खतम करने के बारे में जो वादा किया गया था उसकी तरफ भी मैं हाबुस की तवज्जह दिलाना चाहता हूं। वतनदारी सिस्टम पुराने ढांचे से बरसा के तौर पर हमारे पास आयी है। देहातों में जुल्म और सितम ढानेवाली अगर कोअी सिस्टम है तो वह यही सिस्टम है। जिस सिलसिले में कहा गया था कि जिसके लिये जरूरी कानून हाबुस के सामने लाया जायेगा। यह भी बताया गया कि वेलेडो हुकूमत के जमाने में ही जिसके कानून का ड्राफ्ट (Draft) बन चुका था। तब मेरी समझ में नहीं आता कि पिछले दो सालों से यह चीज हमारे सामने क्यों नहीं आ रही है? और जिस पुराने ढांचे को क्यों जिस तरह से कायम रखने की कोशिश की जा रही है? देहातों के अंदर बड़े बड़े जमीनदारों की तरफ से किसानों की जो लूटखसोट होती है उसके सिलसिले में एक कानून हाबुस के सामने लाया गया, और उसका नाम यह वादा किया जा रहा है कि उससे किसानों का फायदा होगा, उनकी हालत अच्छी होगी, उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी लेकिन दो साल से हम देख रहे हैं कि किसान की परचेसिंग पावर (Purchasing power) में कोअी अिजाफा नहीं हुआ। फायनान्स मिनिस्टर साहब ने अपनी बजट स्पीच में हाबुस के सामने

यह जरूर रखा कि जिराअतके अगराज में कुछ अजिाफा हुआ है लेकिन उसके साथ साथ अन्होंने यह भी बताया कि कैश क्रॉप्स (Cash crops) में और टोटल प्रोडक्शन (Total Production) में कमी हुअी है। जिस साल के लिये कहा जा रहा है कि उसमें कुछ अजिाफा होगा, लेकिन मुल्क की अगराज के लिहाज से जो पैदावार होनी चाहिये वह हो रही है या नहीं इसके बारे में मुझे शक है। आयदा साल हम देखेंगे कि सचमुच किसान ज्यादा पैदा कर रहे हैं या नहीं और उसकी कुव्वत खरीद बढी है या नहीं। लेकिन अब तक के आदाद देख कर मुझे यह महसूस होता है कि जिस नुमायां तौर पर हमारी जिराअत की पैदावार बढनी चाहिये वह आज के हालात में नहीं बढ रही है। और जब तक पैदावार नहीं बढती, मैं नहीं समझता कि हमारे डेफेसिट (Deficit) बजट का सवाल हल हो सकता है। फायनान्स मिनिस्टर साहब ने बताया कि हमारी अेक्साइज (Excise) की आमदनी कम हुअी। अेक्साइज की जो आमदनी होती है उसका ताल्लुक किसान की कुव्वत खरीद से होता है क्योंकि वे ही नशीली चीजोंको ज्यादातर अिस्तेमाल करते हैं। मैं जिस सवाल में नहीं जाअूंगा कि शराब का अिस्तेमाल करना अच्छा है या नहीं। अगर वह बुरा होता तो हुकूमत और फायनान्स मिनिस्टर साहब, सेंदी के झाड कैसे बढाये जायें, अुनसे ज्यादा शराब कैसे पैदा हो, अिस फिकर से उसके लिये ज्यादा रक्कमा मुहैया करने की तरफ नहीं जाते। अिसीलिये मैं यह नहीं कहूंगा कि प्रोहीबीशन (Prohibition) अच्छा है या नहीं, लेकिन हमें यह जरूर महसूस हो रहा है कि अगर किसान की कुव्वत खरीद बढ जाती तो अेक्साइज की आमदनी में कमी न होती, और अिसीलिये यह जो कहा जा रहा है कि किसान की हालत अच्छी हो रही है, उसका सुबुत हमारे सामने नहीं है। फायनान्स मिनिस्टर साहब ने कहा कि अनअेम्प्लायमेंट (Unemployment) अुतना अेक्यूट (Accute) नहीं है, जितना कि समझा जाता है। अिसीलिये मेरे दोस्त ने कहा “ जितना होना चाहिये ” मैं नहीं समझता कि हुकूमत चाहती है कि अनअेम्प्लायमेंट होना चाहिये लेकिन अनअेम्प्लायमेंट के सिलसिले में हुकूमत की जो काम्प्लीसंट अेटीट्यूड (Compeasant Attitude) है उससे बेरोजगारी का सवाल हल नहीं होगा। दिन ब दिन बेरोजगारी बढ रही है और कारखाने बंद हो रहे हैं, यह वाक्या है। अेक या दो कारखानेही बंद हुअे हैं और जो बेरोजगारी हो रही है उसमें डरने की कोअी बात नहीं है अैसा समझना हुकूमत के लिये ठीक नहीं होगा। मैं दावे के साथ कहूंगा कि जिस मअाशी बोहरान के संकट के बारे में हम बहुत दिनों से सोच रहे थे वह आज शुरू हो गया है और वह अलग अलग तरीके से हमारे सामने आ रहा है। अनाज की कीमतों के बारे में सोचा जा रहा था कि ये कीमतें कायम रहेंगी, या कम होंगी। पिछले अेक दो महीने के हालात से मालूम होता है कि अनाज की कीमतें कअी मुकामात पर ५० फीसद तक भी कम हो रहीं हैं। अूँकि यहां के व्यापारियों ने मध्य प्रदेश से अनाज मंगवाया है अिसीलिये यह आरजी तौर पर कमी हुअी है या यह अेक दायमी चीज है जिसके बारे में कुछ कहना मैं मुनासिब नहीं समझता। लेकिन अखबारों से और दीगर मालूमात से अैसा मालूम होता है कि बाकी प्रांतों में भी ये कीमतें गिर रही हैं। अगर यह सही है तो हिंदुस्तान में स्लम्प (Slump) आ रहा है, और उसका मुकाबला करने का सवाल हमारे सामने आ जाता है। अिन कीमतों के साथ हमारे किसानों का संबंध है, और किसानों की हालत से हमारे रेव्हिन्यू का संबंध है, अिसलिये अिसका ख्याल करना जरूरी है।

हमारी आमदनी और खर्च की हालत की तरफ हम देखें तो मैं हाजूम को बताऊंगा कि किसी भी मुक्त का मवाजना स्टेबल (stable) और ग्रॉइंग (growing) होता चाहिये। पिछले तीन साल के मवाजने की तरफ हम देखें तो जो आदाद हमारे सामने है उनसे पता चलता है कि हमारा बर्च ६३ करोड़ ७६ लाख है, और हमारे रिजर्व्ह ५२ करोड़ ८४ लाख के बताये जाने हैं। जिसमें माफ जाहिर होता है कि हमारे रिजर्व्ह और खर्च में काफी तफावत है तकरीबन ११ करोड़ का फर्क है। कॅश बॅलेंस ५ करोड़ ३३ लाख के बताये गये हैं। इसके पहले हर साल जो ओपनिंग कॅश बॅलेंस (Opening cash balances) हमारे सामने बजट के जरिये आये हैं उनकी तरफ मैं हाजूम को नजर न देना चाहता हूँ। उनमें पता चलता है कि हमारे हुकूमत के आज के कारखाने की हालत क्या है। १९५२-५३ में ओपनिंग बॅलेंस १४ करोड़ का था १९५३-५४ में १२ करोड़ का था, और रिवाइज्ड बजेट में वह ११ करोड़ था, लेकिन जिस साल वह ५ करोड़ ३३ लाख का रह गया है। इसके माने यह है कि हमारे पास १ अप्रैल से जो कारोबार शुरू होने वाला है उन लिये सिर्फ ५ करोड़ ३३ लाख की रक्कम है। जिसमें फायनान्स मिनिस्टर साहब ने बताया है कि यह रक्कम कुछ बरायेनाम है। जिससे लंदन में १ करोड़ ९७ लाख रुपये पड़े हुए हैं। जिस रक्कम को भी जिसमें से निकाल दिया जाय तो हमारा कॅश बॅलेंस सिर्फ ३ करोड़ ३६ लाख का रह जाता है। और नोट में यह भी बताया गया है कि सब्बा तीन करोड़ का जो कर्जा हुकूमतने हाल ही में हासिल किया है वह इसीमें शामिल है। यानी यह रक्कम भी जिसमें से निकाल दी जाय तो हुकूमत के पास आज कॅश बॅलेंस के तौर पर करीब कुछ भी नहीं रहता। ऐसी हालत में आयदा अप्रैल से हमारी हुकूमत का कारखाना किस तरह से चलनेवाला है यह सवाल हमारे समने आ जाता है। सालहा साल हमारे कॅश बॅलेंस की हालत बदतर होती जा रही है। १४ करोड़ से ११ करोड़ और ११ करोड़ से ५ करोड़ तक हम पहुंच गये हैं। कॅश बॅलेंस की यह हालत है। कर्जों के लिहाज से देखें तो हमारी हुकूमत पर ५५ करोड़ ६१ लाख रुपये का कर्जा है। जिस साल वह ६३ करोड़ से भी ज्यादा हो गया है, और आयदा के लिये हुकूमत की तरफ से बताया गया है कि हुकूमते हिंद की तरफ से ५ करोड़ से ज्यादा कर्जा वह हासिल करनेवाली है। यानी आयदा साल के बजट में ६८ करोड़ का कर्जा हमारे ऊपर होगा। दरमियान में कोजी मैच्यूर (Mature) खर्च हो जाय तो अंकाध करोड़ की कमी हो जायगी। लेकिन आम तौर से यह अंदाजा किया जा सकता है कि ६३ करोड़ से ७० करोड़ तक हमारा कर्जा बढ़नेवाला है। दरमियान में जिसमें और भी अजाफा नहीं होगा ऐसी भी बात नहीं है। हमारे जो रिजर्व्ह हैं वे भी किस तरह के हैं वह मैं बताना चाहता हूँ। २५ करोड़ सिक्युरिटीज (Securities) के तौर पर, और २२ करोड़ शेअर्स के तौर पर कारखानों में लगाये गये हैं। जिसमें से चंद तो ऐसे हैं जिनको व्यापारी लिहाज से अच्छा इनव्हेस्टमेंट नहीं समझा जायगा। सिविल सप्लाय को ६ करोड़ ४६ लाख की रक्कम दी गयी है। उसमें से कितनी रक्कम वापस आ सकती है इसके बारे में फायनान्स मिनिस्टर एक्स्प्लीकरण कर दें तो मुनासिब होगा। लोकल विडस्ट्रीज को लोन के तौर पर ४ करोड़ ८४ लाख रुपये दिये गये हैं। जिसमें से कितनी विडस्ट्रीज ठीक तरीके पर काम कर रही हैं। और कितनी ओवर कपिटलाइज्ड (Over-Capitalized) हैं कितनी लिक्विडेशन (Liquidation) में जाने के अमकानात हैं, कितनी को लिक्विडेशन में निकालने के बारे में सोचा जा रहा है, और अगर वह सचमुच लिक्विडेशन में चली जायें तो हुकूमत पर बुरा क्या असर होगा, ये सारी बातें फायनान्स मिनिस्टर बाजे कर दें तो जो कॅश बॅलेंस बताये जा रहे हैं, उनमें से कितने असल में हासिल

होने के अमकानात हैं अमका हमे कुछ अंदाजा लग सकता है। कैश बैलन्स के तौर पर कराची में २ करोड ३५ लाख रुपये पड़े हैं, अमका बनाया जा रहा है। लंदन में जो रुपये पड़े हैं वे और कराची में पड़े हुअे अंक ही हैं या अलग अलग हैं? और अगर अलग अलग हैं तो कराची में पड़े हुअे यहा सिर्फ हिमात्र के लिये बताये गये हैं, या सचमुच वे हासिल होनेवाले हैं? यह मालूम करने में हाअुस को सचमुच दिलचस्पी होगी। अिन तमाम चीजों को देखा जाय तो मैंने जैसे किसी मुल्क का सवाजना टेस्ट पर लगाने के बारे में कहा था कि वह स्टेबल और प्रोजिग होना चाहिये, अुस टेस्ट पर हमरा आज का बजट नहीं अुतरता। पिछले साल का बजट पेश करते हुअे अुस वक्त के फायनान्स मिनिस्टर साहब ने बताया था कि हैंड टु माअुथ (Hand to Mouth) हमारा बजट है। आज अमका मालूम हो रहा है कि अिस साल का बजट दिवालिया है, और आयंदा दो साल के बाद जब अिस हुकूमत की बागडोर अिलेक्शन के जरिये बदलवाने का शायद मौका आ जाय तो न मालूम कितना बड़ा कर्जा अक्वाम के सर पर रख कर यह हुकूमत चली जायगी। यह खौफ हमारे दिल में पैदा हुआ क्योकि गये तीन साल के हुकूमत के कारनामे हमारे सामने हैं, और मालूम नहीं आयंदा दो साल में क्या होनेवाला है। अिस तरफ मैं हाअुस का खास तौर से ध्यान दिलाना चाहूंगा। बजट में रिसीट्स के मदों को देखने की कोशिश की तो मालूम हुआ कि रिव्हाअिज्ड अेस्टीमेट १९५२-५३ में २७ करोड ९१ लाख रुपये जमा हो सके। आम तौर पर समझा जाता है कि रिव्हाअिज्ड बजट सेशन के आखरी महीने में आ जाता है। पिछले साल रिव्हाअिज्ड बजट हमारे सामने मार्च के आखिर में रखा गया था। और हम समझते थे कि स्टेट का खर्च कितना होता है, और आमदनी कितनी होती है, अिसके बारे में हुकूमत का अंदाजा ठीक ठीक होगा। हम यह अुम्मीद नहीं करते थे कि अिसमें अेक करोड की कमी हो जायेगी। लेकिन हमारे सामने कुछ अेक्चुअल्स २८ करोड २७ लाख के बताये जा रहे हैं, यानी अिसमें अेक करोड से भी ज्यादा कमी वाकये हो रही है। अैसी हालत में जो रिव्हाअिज्ड अेस्टीमेट्स (Revised estimates) के आदाद हमारे रखे जाते हैं अुन पर हम किस हद तक भरोसा करें यह भी सवाल है। मैं समझता हूं कि हमारा फायनान्स डिपार्टमेंट तजुबेंकार है। अगर अुसके अंदाज में अिस तरह से करोडों का फर्क पड सकता है तो शायद अुसे वही समझ सकेगा, लेकिन मामूली आदमी अुसको नहीं समझ सकता कि हुकूमत की हालत किस तरह की है, और यह कमी और ज्यादाती क्यों हो रही है। अिसके लिये हमारे सामने जो वजूहात पेश किये गये हैं अुनमें कहा गया है कि हमारे लैंड रेव्यू में तकरीबन ५७ लाख की कमी वाकये हुअी है। अेक्साअिज में ८५ लाख की कमी हुअी है। कस्टम्स में कुछ हजार की कमी हुअी है। अिस तरह से जो करोडों की कमी या ज्यादाती होती है वह किस वजह से हुअी? अिसके लिये अगर यह माना जाय कि यहां से जो चीजे बाहर जाती हैं अुसमें स्मगलिंग (Smuggling) हो रहा है तो अिसके लिये कौन जिम्मेदार है? और वह स्मगलिंग कितना है, अिससे कि हमारी आमदनी में कमी हुअी है? अिसके लिये हुकूमत की तरफ से क्या स्टेप्स लिये गये हैं? अिन चीजोंको भी फायनान्स मिनिस्टर को हाअुस के सामने रखना चाहिये, क्योकि यह लाखों रुपयों का मामला है। आमदनी कम होने की अेक वजह यह बताअी गअी है कि लोगों की हालत अच्छी नहीं है। मेरी समझ में नहीं आता कि अेक वक्त में हम दो चीजें कैसे कह सकते हैं? या तो हमें कहना पड़ेगा कि लोगों की हालत खराब है अिसलिये आमदनी कम हो रही है, या यह कहना पड़ेगा कि लोगों की हालत अच्छी है। लेकिन हमारे अेडमिनिस्ट्रेशन में कुछ कुसूर है, अिसलिये आमदनी कम हो रही है। अेक ~~दूसरी वजह~~ कि लोगों की हालत अच्छी है और दूसरी दफा यह कहना कि खराब है, यह दोनों

कैसे मही हो सकते हैं ? जिस साल अक्साजिज में ३४ लाख रुपये ज्यादा आने के अंशमानान बताये गये हैं और गये साल में ८५ लाख की कमी बतायी गयी है । जो साल चल रहा है उसकी क्या हालत है ? अंस्टीमेटस् में बताया गया था कि ५८ करोड़ की आमदनी शामिल होगी । लेकिन अब बताया जा रहा है कि रिक्वाजिज्ड अंस्टीमेटस् में ५५ करोड़ ९२ लाख वसूल होनेवाले हैं । जिसके माने यह है कि दो करोड़ से ज्यादा रुपये कम वसूल होनेवाले हैं, और जिसमें बताया गया कि अक्साजिज के तहत ९३ लाख रुपये जिस साल कम होंगे । यह हमारा सब से बड़ा रेविन्यू का आयटम (Item) है। जिसमें १९५२-५३ में ९५ लाख और जिस साल ९३ लाख की कमी हुई, और आयेंद यह अंशमान की जा रही है कि जिस मद में ३८ लाख रुपये बढ़ेंगे । यह अंशमान किस बिना पर की जा रही है यह समझ में नहीं आता । आयेंदा साल रिक्वाजिज्ड बजट आयेंगा तो उसमें अक्साजिज की आमदनी में कमी या ज्यादानी कितनी होगी है उसका पता चलेगा । लेकिन कागज के हिसाब से हुकूमत गलत अंदाजा करेगी तो जो अंदाजा रखा गया है उसमें से किस तरह से डेवलपमेंटस् स्कीम्स और दीगर नेशन बिल्डिंग के काम पूरे होंगे और उन पर क्या असर होगा जिसका पता नहीं लग सकता । दो साल से हमने देखा कि जो अंस्टीमेटेड बजट होता है उसमें कमी वाक्ये हुई है । जिसका असर आखीर कहां पड़ता है ? वह सिक्कुरिटी सर्विसेस पर या डेडमिनिस्ट्रेटिव्ह सर्विसेस पर नहीं पड़ता बल्कि नेशन बिल्डिंग डिपार्टमेंट्स पर पड़ता है । उसके अंस्टीमेटस् में कटौती होती है । सिविल वर्क्स के काम ठीक समय में नहीं हुआ तो उसके लिये बड़े अच्छे अल्फाज हमारे मिनिस्टर साहब को मिल गये हैं । ड्यू टू स्लो प्रोग्रेस ऑफ वर्क (Due to slow progress of work) के माने क्या हैं ? जिस स्लो प्रोग्रेस के लिये कौन जिम्मेदार है, कौन गुन्हागार है, किसने स्लो प्रोग्रेस किया है, किसीके वक्त पर हुक्म न देने की वजह से यह स्लो प्रोग्रेस हुआ है या और किसी वजह से हुआ है जिसका हमें अंदाजा नहीं लग सकता । इसीलिये हुकूमत पर मेरा यह चार्ज है कि यह स्लो प्रोग्रेस सिर्फ बताने के लिये है । पहले गलत अंदाजा किया जाता है, दूसरे डिपार्टमेंट्स का खर्च ज्यादा हो जाता है, उसको पूरा करने के लिये बादमें डेवलपमेंट और नेशन बिल्डिंग के कामों का पैसा लिया जाता है, और आखीर में ये काम अधूरे छोड़ दिये जाते हैं ।

दूसरे जो आमदनी के जरिये हैं उसमें भी हुकूमत की तरफ से जो तवज्जेह होनी चाहिये, वह नहीं हो रही है । मैंने पिछले बार कहा था कि अग्रिकल्चरल इनकम टैक्स उन तमाम लोगों पर लगाता चाहिये जिनके पास सीलिंग (Ceiling) से ज्यादा जमीन है । ऑनरेबल फायनान्स मिनिस्टर, जो उस वक्त थे, उन्होंने वादा किया था कि जिस बारे में हुकूमत सोच रही है और बाद में कुछ फैसला करेगी । आयेंदा दो साल में हुकूमत कौनसे कदम उठायेगी जिसपर यह बात मुनहसर रहेगी कि मैं अपनी सुझाव जाहिर करूँ या अफसोस जाहिर करूँ ।

हुकूमत ने यह लायुन किया है कि ३६०० रुपये से ज्यादा आमदनी की जमीन जिनके पास है उनसे वह ज्यादा जमीन हुकूमत वापस अपने कब्जे में ले सकती है, अपने मॅनेजमेंट में ले सकती है । तो मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसी हालत में हुकूमत अग्रिकल्चरल इनकम टैक्स (Agricultural Income Tax) जैसी जमीन से क्यों नहीं ले सकती ? यह कहा जाता है कि अज्वाब को टैक्स देने के लिये तैयार करना चाहिये । अगर हमारा बजेट डिफिसिट है तो जरूर टैक्स लेना चाहिये । लेकिन मैं हुकूमत से यह पूछना चाहता हूँ कि वापस अग्रिकल्चरल इनकम टैक्स, जिसकी आमदनी १० हजार रुपये से ज्यादा है जैसी लोगों पर रखा है, उसे पांच हजार आमदनी वाले लोगों

पर क्यों नहीं लगाया जाता ? सिर्फ ५ लाख रुपये ऑफिकलचरल इनकम टैक्स से वसूल हुये हैं। हमारे यहाँ लाखों ऐकड़ जमीन के मालिक हैं, और उनसे जो ऑफिकलचरल इनकम टैक्स वसूल हुआ बताया जा रहा है वह सिर्फ ५ लाख रुपये का है। अगर अतनाही वसूल किया जा रहा है तो जिसमें ज्यादा क्यों नहीं वसूल किया जाता ? मैं हुकूमत से यह अपील करना चाहता हूँ कि हमारा रेवेन्यू बढ़ाने के लिये जो जिस तरह से सरप्लस इनकम (Surplus income) रखनेवाले लोग हैं उनसे ज्यादा टैक्स वसूल किया जाना चाहिये, जिससे कि हमारी आमदनी में अजिजाफा हो सके।

दूसरी चीज जो मैं रखना चाहता हूँ वह इनकम टैक्स के सिलसिले में है। मैंने पहले ही बताया है कि आज कल स्लप (Slump) आ रहा है, और हमें हमारे डेवेलपमेंट प्लान्स (Development Plans) पूरे करने हैं, तो हमें यह देखना होगा कि कौन लोग ज्यादा टैक्स दे सकते हैं। मैं यह जानता हूँ कि इनकम टैक्स का महकमा हुकूमत हिंद में तालुक रखता है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि हुकूमते हिंद के अिमादाद से हमारे जो पंचसाला प्लान्स हैं वह पूरे नहीं होनेवाले हैं। जरूरत जिस बात की है कि हम ज्यादा रकम मोहिया करें। जिस-लिये आज का जो इनकम टैक्स है वह हमारे अखराजात पूरे नहीं कर सकता जिस लिये जरूरत जिस बात की है कि हमारी गवर्नमेंट को हुकूमते हिंद के पास यह माग करनी चाहिये कि इनकम टैक्स के रेट में अजिजाफा होना चाहिये। अगर ऐसा न किया गया तो मैं बताना चाहता हूँ कि दिन ब दिन हमारे रेवेन्यू के सोर्स (Sources) कम होंगे, और हमें हर साल खसारे का बजेट रखना नामुमकिन होगा।

अब चीज मैं हाउस के सामने रखना चाहता हूँ कि आज की जो हमारी टैक्स पॉलिसी है उसमें तरमीम करने की जरूरत है। हुकूमते हिंद ने हाल ही में एक टैक्स अिनक्वायरी कमीटी (Tax Enquiry Committee) बिठायी है। उस टैक्स अिनक्वायरी कमीटी की जो सिफारिस होगी वह तो हमारे सामने आयेगी। हुकूमते हिंद का बजेट हम देखते हैं तो मालूम होता है कि अब्बाम की जरूरियात की चीजों पर भी अन्होंने अपने बजेट में टैक्स आयद किये हैं। हुकूमते हिंद ने इनकम टैक्स अिनक्वायरी के सिफारिसात तक रुकने की जरूरत नहीं समझी। ऐसे हालात में हमें भी यहाँ पर ऑफिकलचरल इनकम टैक्स बढ़ाने के लिये रोकने की जरूरत नहीं है।

दुनिया के जिन जिन देशोंमें डेवेलपमेंट प्लान अमल में लाये जा रहे हैं, वहाँ पर पब्लिक सेक्टर (Public sector) से ज्यादा पैसा हासिल करने की कोशिश की जाती है। मिसाल के तौर पर मैं चीन का बजेट संक्षिप्त में आपके सामने रखना चाहता हूँ। चीन के अंदर जो टैक्स वसूल होता है वह किस तरह से किया जाता है वह मैं आपको बताना चाहता हूँ। यह जो बजेट है चीन का उसमें टैक्स से जो आमदनी बतायी गयी है वह करीब ५० फीसद की है। जिसमें स्टेट मॅनेज्ड जो अिडस्ट्रीज हैं उनसे ३० परसेंट, ऑफिकलचरल इनकम टैक्स से १० परसेंट, अिड-रेस्ट से ५ परसेंट, रिसर्व्स से १६ परसेंट से और बाकी दूसरे टैक्ससे आते हैं।

पिछले तीन सालोंसे वहाँ के पब्लिक सेक्टर से जो आमदनी हो रही है उसमें अजिजाफा होता जा रहा है। चीन का जो बजेट मेरे पास है उसे हाउस के सामने रखकर मैं यह बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से पब्लिक सेक्टर की आमदनी बढ़ायी जा रही है।

Percentage of State Revenue derived from tax payment and profits made from State enterprise, and tax payment of State Co-operatives.

पब्लिक सेक्टर में जो आमदनी बढ़ रही है उसमें आंकड़े इस तरह से हैं। १९५० में ३० परसेंट, १९५१ में ४९ परसेंट, १९५२ में ५० परसेंट और १९५३ में ६० परसेंट।

जिसमें देखें तो मालूम होता है कि ३४ करोड़ से ६० करोड़ तक की आमदनी पब्लिक सेक्टर से बढ़ी है।

Percentage of State Revenue derived from taxes paid by peasants.

किसानों की तरफ से जो टैक्स लिया जा रहा है उसमें इस प्रकार कमी की जा रही है। १९५० में २५ करोड़, १९५१ में १८ करोड़, १९५२ में १७ करोड़ और १९५३ में १४ करोड़, जिस तरह से कमी जा रही है।

Percentage of State Revenue derived from taxation paid by private industrial and commercial enterprise.

१९५० में ३२.९२ करोड़, १९५१ में २८.६६ करोड़, १९५२ में २४ करोड़, और १९५३ में २२ करोड़। यह मैंने इस लिये रखा कि इस तरह किसानों पर टैक्स बढ़ाने से आप वेल फेअर स्टेट (Welfare state) कायम नहीं कर सकते। इस तरह वेल फेअर स्टेट कायम करने का आपका तमबूर गलत है।

हुकूमत जो मनअते चला सकती है वह उसे जरूर चालानी चाहिये। मैं ऐसा नहीं कहता कि सभी मनअतें हुकूमत को चालानी ही चाहिये। अगर कुछ मनअतों को हुकूमत नहीं चला सकती है तो उसे न चलाये। जो मनअतें हुकूमत की तरफ से चलायी जायेंगी वह बराबर चल सकती हैं या नहीं यह देखना चाहिये। मैं मजबूर नहीं करता कि सरकार की जानिबसे सभी मनअतें चलायी जायें। हैदराबाद ट्रेड यूनियन कॉंग्रेस की तरफ से यह कहा गया था कि हमारे स्टेट में जो ओवर कैपिटलाजिज्ड इंडस्ट्रीज (Over-capitalised Industries) हैं उन्हें लिक्विड करना चाहिये।

अब सेल्स टैक्स के मिलसिलेमें में कुछ कहना चाहता हूं। हमारे यहां मल्टी पॉइंट सेल्स टैक्स (Multi-point Sales Tax) रखा गया है। मैंने तो पहले ही अर्ज किया है कि जिससे हमारी आमदनी बढ़नेवाली नहीं है। इस तरह सेल्स टैक्स कभी जगहों पर जमा किया जाता है। इसलिये उसके जमा करने में ज्यादा खर्चा आता है और टैक्स कम जमा होता है। हमारा सन ५४-५५ वर्ष का जो बजेट है उसमें सेल्स टैक्स की आमदनी ४ करोड़ की बतायी है। मेर. ब्याक है कि अगर यह सेल्स टैक्स सिंगल पॉइंट (Single Point) कर दिया जाय तो हमारी आमदनी कम नहीं होगी बल्कि बढ़ेगी। बंबई में जो तरीका है उस तरीके से सेल्स टैक्स रखा जाय तो आमदनी बढ़ेगी। मल्टि पॉइंट सेल्स टैक्स सिस्टम (Multi point Sales Tax system) में ज्यादा लूप होल्स (Loop holes) रहने का डर है। ऑनरेबल फायनान्स मिनिस्टर जो इस समय बने उन्होंने वादा किया था कि हम सेल्स टैक्स सिस्टम ऐसी रखेंगे जो कि आसान हो। हमारी आमदनी के लिहाज से आज सेल्स टैक्स को बढ़ाने की जरूरत है तो

आज के सेल्स टैक्स अँकट में तरमीम करनी चाहिये और मल्टि पॉइंट के बजाय सिंगल पॉइंट टैक्स वसूल किया जाना चाहिये। इस बारे में मैंने अपने ख्यालात पिछली मर्तबा हाउस में रखे थे और इसकी जो टेस्ट मैंने पिछले बजेट के वक्त रखी थीं उसे लगते हुअे यदि हमें रेविन्यू बढ़ाना है तो इसके लिये जो ज्यादा टैक्स दे सकते हैं उनके टैक्स बढ़ाने की जरूरत है। यह कैसे हो सकता है यह सोचना चाहिये। अमीरों पर सेल्स टैक्स बढ़ा कर गरीबों का टैक्स कम करना चाहिये, अनी सुरतमें हम वेल फेयर स्टेट (Welfare state) का नारा पूरा कर सकेंगे। अगर ऐसा नहीं किया जाना है तो अिमका मतलब यह होगा कि चंद लोगों के लिये तो वेल फेयर स्टेट होजायेगा लेकिन अिमसे हम आम आवाम का सवाल हल नहीं कर सकेंगे।

और अँक चीज मैं हाउस के सामने रखना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने शुरू में अर्ज किया कि हमें हमारी सनअतें बढ़ानी चाहिये, तो यह पूछा जाता है कि अिसके लिये पैसा कहां से लाया जाय। मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे पास पैसा काफी है लेकिन उसे सनअतों में लाने की कोशिश नहीं की जा रही है, और कहते हैं कि सनअतों को अुठाने के लिये कॅपिटल (Capital) कहाँ से खड़ा करेंगे ? मैं यह सुझाना चाहता हूँ कि जो बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास अँक लाख से ज्यादा रक्कम है अुन्हे कंपलसरीली अिडस्ट्रीज में कॅपिटल अिनव्हेस्ट करना चाहिये। अिस तरह का कानून बनाया जाय तो जो पैसा आज पड़ा हुवा है वह काम में आयेगा। अिस तरह यदि कोशिश करनी है तो अुसके लिये जो पैसा हैदराबाद स्टेट के अंदर अनयुज्ड (Unused) है अुसे टैप (Tap) करने की जरूरत है। मेरा कहना यह नहीं है कि बड़े लोगों का पैसा कॉन्फिस्केट (Confiscate) किया जाय लेकिन अुनसे कंपलसरी तौर पर जो रक्कम ली जायेगी अुसके लिये अुन्हे ढाअी परसेंट अिटरेस्ट दिया जा सकता है। तुगभंद्रा प्राँजेक्ट के लिये आप निजाम से ४० लाख रुपया लेसकते हैं तो सनअतों के लिये भी दूसरे लोगों से कानून बनाकर भी क्यों न हो, पैसा क्यों नहीं ले सकतें। आपको शायद अिस तरह बार बार निजाम साहब का नाम दोहराया जाना ठीक नहीं मालूम हो रहा होगा। दूसरा रास्ता क्या है, मेरी नजर में तो नहीं आ रहा है। किसी भी तरीके से हमें हमारी सनअतों को तो फरोग देना होगा। अुसके बिना हमारा सवाल हल नहीं हो सकता। हमारा यह जो अँक सरमायेदारों का और जागोरदारों का चौखट है अुसे हमें तोडनाही पडेगा तभी हमारा यह सवाल हल होगा। यह काम हुकूमते हिंद और हैदराबाद सरकार दोनों का है, वरना यह डेमाँक्री कैसे चलेगी ? हमारे पास काफी रुपये जेवरात आदि में रखे जाते हैं और अिस लिये मुल्क की सनअतों के लिये कॅपिटल नहीं मिलता। बड़े बड़े लोग अपना पैसा जेवरात में डिपॉजिट कर देते हैं, अुसे जरूर बाहर निकालना चाहिये, और सनअतों के लिये अिस्तेमाल किया जाना चाहिये। मुल्क की तरक्की के लिये अिसे जरूर अिस्तेमाल किया जाना चाहिये। यही हमारा नजरिया है। आप चाहे यह पैसा कॉन्फिस्केट (Confiscate) न करें लेकिन यह पैसा अिस्तेमाल तो जरूर होना चाहिये। चाहे तो आप जिनसे अिस तरह पैसा लेंगे अुन्हे ढाअी परसेंट अिटरेस्ट दे; सनअतों की तरक्की के लिये अिस तरह कुछ न कुछ कदम जरूर अुठाना पडेगा तभी आपकी आमदनी बढ़ सकती है।

अबतक मैंने आमदनी के बारे में कहा, अब खर्च के बारे में कहना चाहता हूँ। आज भी हमारे यहां राजकाज के खर्च का जो तरीका है वह वही अंग्रेजों के तरीके जैसा है। हमारा बजेट भी आज अुसी ढाँचे में ढाला जाता है, जैसा पहले रहा करता था। हमने आज तक भी कोअी नया तरीका

नहीं निकाला। पहले जिस तरह अंग्रेज लोग यहां पांच सात हजार मील से आकर बड़े पगार लेकर राज्य करते थे, और अूम जमाने में चीफ मेक्रेटरीज, सेक्रेटरीज, गवर्नर्स, व्हाइसराय, आदि बड़े बड़े लोगों को जिस तरह तनखाहें दी जाती थी उसी तरह आज भी बड़ी बड़ी तनखाहें ली जाती हैं। जिसके कारण हमारा आज का अडमिनिस्ट्रेशन (Administration) बहुत टॉप हेवी (Top-heavy) हो गया है। जहां पर डेमाॅक्रेटिक हुकूमतें बनी हैं वहां यह टॉप हेवी (Top-heavy) अडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा कम करने के लिये पहले कदम उठाये गये। कल मुझे अंक डिपार्टमेंट के मेक्रेटरी माहव मिले थे, कहते थे कि अगर आप लोग हुकूमत पर आये तो हमारे आज की मॅलरिज है अुमे तो आप कम ही कर देंगे। मैं हुकूमत में अपील करना चाहता हूं मुल्क के फायदे के लिये अगर जरूरी है तो जिस तरह का जो टॉप हेवी अडमिनिस्ट्रेशन आज है अुमे रोकने के लिये बड़ी बड़ी तनखाह पाने वाले लोगों की तनखाह में जरूर कमी की जानी चाहिये, कार्मिग्रेड स्टॉलिन मिर्फ ६०० रुपये पगार लिया करता था। चीन का मॉल्मेतुंग को सिर्फ ६०० या ७०० रुपये पगार ह। वहां आठ या दस गुना से ज्यादा फरक किसी के भी आमदनी में नहीं रहता। यह ख्याल आज किया जाता है कि जिस तरह के जो बड़े बड़े पगार हैं वह अडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिये जरूरी हैं। उसके बिना अडमिनिस्ट्रेशन नहीं चलाया जा सकता, लेकिन हम में यह जो गलत ख्याल है अुमे छोड़ना चाहिये। पहले तो यह ख्याल काॅंग्रेस के लोगों में भी नहीं था, लेकिन आज कल यह ख्याल कहां से आया मालूम नहीं। आज का यह जो टॉप हेवी अडमिनिस्ट्रेशन है अुसे कम करना ही चाहिये। जो बड़े अफसर हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आज देश को आपकी कुरबानी की जरूरत है, आपके जो बड़े बड़े पगार हैं अुसे आपको खुद ही कर कम करना चाहिये, और छोटे छोटे मुलाजमीन के पगार बढ़ाने चाहियें। उसके बिना सच्ची डेमाॅक्रेटिक हुकूमत नहीं बन सकती। जिसके लिये हमें पहले दिमागी तब्दीली की जरूरत है। अगर पहले दिमागी तब्दीली नहीं आती तो यह चौखटा जो हम बदलना चाहते हैं वह नहीं बदल सकते, लेकिन आज जिस बात को मानने के लिये हम लोग नैयार नहीं हैं। आज जिस तरह बड़ी बड़ी तनखाहें देकर जो टॉप हेवी अडमिनिस्ट्रेशन चलाया जा रहा है अुसे कम करने की जरूरत है, और हम यह तनखाहें कम कर सकते हैं। यह कहा जाता है कि हमारे पुराने काॅन्ट्रक्ट्स हैं हमें उनकी तनखाहें तो देनी ही पडेंगे। मैं कहता हूं कि अगर कुछ पुराने आय. सी. अेस. लोग रखने की जरूरत है तो अुन्हे उसी पगार पर रखा जा सकता है। लेकिन अब जो आय. पी. अेस. और आय. अे. अेस. कंडर के लिये जो नये लोग रिक्कूट (Recruit) किये जाते हैं अुन्हे भी वही पगार क्यों दिया जा रहा है? उनके पगार कम क्यों नहीं कर सकते? मुझे जिस बात का बड़ा ताजुब होता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र बाबू जैसे लोग होते हुये भी वह अिसे क्यों नहीं कम कर सकते? उनके भी ख्यालात कैसे बदल गये? मैं आपके सामने जिस बात को रखना चाहता हूं कि यह चीज तो होगी और होकर ही रहेगी। यह टॉप हेवी अडमिनिस्ट्रेशन जरूर कम होना चाहिये। चीन में अडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेस पर बजेट के खर्चे के २० गुना से ज्यादा खर्चा नहीं किया जाता लेकिन हमारे यहां अडमिनिस्ट्रेशन पर बजेट के खर्चे के ३० गुना खर्चा होता है।

अब मैं आपके सामने जिस बजेट का अॅनॅलिसिस (Analysis) रख कर यह बताना चाहता हूं कि जिस बजेट में किस तरह खर्चा रखा गया है।

डायरेक्ट डिमांड रेव्यु के लिये ३ करोड ३१ लाख रुपये रखे हैं।

डेट सर्विसेस के लिये ३ करोड़ २२ लाख रुपये रखे हैं।

अॅडमिनिस्ट्रेटिव्ह सर्विसेस, जनरल अॅडमिनिस्ट्रेशन पुलिस जेल के लिये ५ करोड़ के करीब खर्चा रखे हैं।

सोगल सर्विस, सोगल वर्क्स पर ७ करोड़ ९९ लाख रुपये रखे गये हैं। जिस तरह यदि हम अॅक्मपिंडिचर का अनलेसिस करें तो मालूम होगा कि अॅडमिनिस्ट्रेटिव्ह और सिव्युरिटि सर्विसेस पर १८ परसेंट खर्चा हो रहा है और टॅक्स कलेक्शन पर १२ परसेंट का खर्चा हो रहा है। जिस तरह से अॅडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेस और टॅक्स कलेक्शन पर आमदनी का ३० परसेंट का खर्चा हो रहा है। डेट्स अॅन्ड अिटरेस्ट पर साडेतीन करोड़ से ज्यादा रकम है जो १३ परसेंट होती है। फ्यूडल अॅमिनिटिज पर ६ परसेंट और मिसलेनियस (Miscellaneous) पर ८ परसेंट खर्चा होता है। जिस तरह से आमदनी का ६० परसेंट खर्चा अॅडमिनिस्ट्रेशन के अखराजात में या निजाम के देने के अखराजात में खर्च होता है और बाकी बचा ४० परसेंट का खर्चा नेशन बिल्डिंग अॅक्टिविटीज (Nation building Activities) पर किया जाता है।

चीन के बजेट को हम देखें तो मालूम होगा कि वहां पर अॅडमिनिस्ट्रेशन पर १० परसेंट का खर्चा होता है। रिझर्व्हज ७ परसेंट रखे जाते हैं। चीन में नेशन बिल्डिंग के काम पर ६० परसेंट का खर्चा होता है और बाकी पैसा मुल्क के डिफेन्स पर खर्च किया जाता है। यह करीब करीब २२ परसेंट तक आता है। हमारे देश से चीन कोजी बहुत बड़ा देश नहीं है। हमारी आबादी ३२ करोड़ के करीब है और चीन की आबादी ३५ करोड़ के करीब है। वहां डिफेन्स पर २२ परसेंट से ज्यादा खर्चा नहीं किया जाता है लेकिन हमारे यहां ५० परसेंट खर्चा किया जा रहा है। वहां पर नेशन बिल्डिंग पर ६० परसेंट खर्चा किया जाता है तो हमारे यहां यह खर्चा ३१ से लेकर ४१ परसेंट तक बढ़ा है। आज हम साठेग्यारह करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि नेशन बिल्डिंग अॅक्टिविटीज पर हम बहुत कम खर्चा कर रहे हैं। आपका आज का जो टॉप हेवी अॅडमिनिस्ट्रेशन है उसमें आपको दुरुस्ती करनी होगी। आज पुलिस पर जो खर्चा किया जाता है वह पहले से तो कम हो गया है लेकिन उससे भी ज्यादा कमी जिसमें हो सकती है और वह करनी चाहिये, जिससे हमारा अॅडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा कम होगा। आज आप पुलिस पर सच्चातीन करोड़ रुपयोंसे ज्यादा खर्चा कर रहे हैं। यह बहुत काफी है। जिसमें कमी होनी चाहिये।

आपको जमीनदार और जागीरदार तबके की हिफाजत तो नहीं करनी है। अवाम की भलाजी के जो काम हैं उसमें ज्यादा पैसा खर्च करना चाहिये। अगर हम पिपुल्स मिलिशिया (People's militia) करें तो हमारा डिफेन्स का खर्चा कम हो सकता है।

हुकूमते बर्तानिया हिंदुस्तान पर जब राज करती थी तब उनको ज्यादा खर्च करने की क्यों जरूरत पड़ती थी और हमको खर्च क्यों कम करना चाहिये जिसकी तरफ मैं हाउस की तबज्जह दिलाऊंगा ताकि जो चीज मैं हाउस के सामने रखना चाह रहा हूं वह साफ हो जाय। बर्तानिया का राज एक आक्कूपेशन (Occupation) के तौर पर था जिसलिये उनको मिलीटरी और पुलिस की ज्यादा जरूरत थी, लेकिन आज के हालात में जब कि हम जमहूरो हुकूमत करने का और अव्बाम के मसायल सहल करने का दावा कर के हुकूमत में या जिस असेंबली में आये हैं तो

हमको इन्ट्रास्पेक्टिव्ह (Introspective) हो कर देखना पड़ेगा। जब यहां बेरूनी हुकूमत काम करती थी तो उसका जितना खर्च था अतना ही आज भी हमको सिक्यूरिटी सर्विसेस पर करना पड़ रहा है, जिसलिये यह सोंचना जरूरी हो जाता है कि आखिर हमारी हुकूमत करने के तरीके में कुछ न कुछ नुक्स जरूर है, और अब्बाम के मसायल हल करने के अप्रोच में (Approach) कुछ खामियां हैं, हमारे पास पैसा कम है लेकिन फिर भी सिक्यूरिटी सर्विसेस पर ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है। जिस मुल्क में सिक्यूरिटी सर्विसेस पर कम खर्च किया जाता है उसी के बारे में कहा जाता है कि वह मुल्क अब्बाम की भलाखी और बहवूदी करने की तरफ बढ रहा है, जिसलिये हमको सिक्यूरिटी सर्विसेस का खर्च कम करना चाहिये और आयंदा दो साल में नेशन बिल्डिंग के कामों पर जो ४० परसेंट खर्च किया जा रहा है उसको बढ़ाकर ६० फीसद करना चाहिये और सिक्यूरिटी सर्विसेस का खर्च २० परसेंट से कम करना चाहिये, उसी वक्त हमारे सामने जो बजट के खसारे का सवाल दूर हो सकता है।

दूसरी चीज पंच साला प्रोग्राम के बारे में मैं हाअस के सामने रखना चाहता हूं। जिस तरह से हिंदुस्तान में एक पुनर्रचना करने का सवाल हमारे सामने आया है, उसी तरह से हमारा बिरादर पड़ोसी देश चीन में भी यही सवाल है। जिस तरह से हम पंचसाला प्रोग्राम से हमारे राष्ट्र की पुनर्निर्मिति करना चाहते हैं उसी तरह से चीन भी कोशिश कर रहा है। अूनकी जो तेज रफ्तार से तरक्की हो रही है, उसके मुकाबले में हमारी रफ्तार को देखें तो एक बड़ी चीज जो नुमायां तौर पर हमारे सामने आती है, वह यह है कि वहां अब्बाम का कोआपरेशन हुकूमत को हासिल है बजट स्पीच में कहा गया कि जहां जहां अब्बाम का कोआपरेशन होगा वहां वहां तरक्की पैदा हो सकेगी। कम्युनिटी प्रोजेक्ट (Community Project) आफिसर्स और नेशनल अक्स-टेंशन सर्विसेस (National extension services) के लोगों से बातचीत करने का मौका मुझे मिला है। अुन्होंने जो यहां का किस्सा सुनाया उसको सुनने के बाद अगर चीफ मिनिस्टर साहब यह फरमायें कि अब्बाम की ताबिद हुकूमत को हासिल हो रही है तो मैं उस पर भरोसा नहीं कर सकता। अुन्होंने कहा कि एक गांव में कलेक्टर साहब आकर सफाई का काम शुरू कर दिये। गांव के चंद लोग बाजू में खड़े होकर कहने लगे कि अितना बड़ा अफसर है लेकिन झाड़ मारता है, अच्छा काम किया। फिर कहने लगे कि फलां जगह आपने अच्छी तरह से सफाई नहीं की वहां अच्छी तरह कीजिये। यह किस्सा कहने में मुझे खुशी नहीं होती लेकिन एक आब्जेक्टिव्ह (Objective) तरीके पर मैं हुकूमत से कहना चाहता हूं कि हुकूमत की तरफ देखने का लोगों का यह जो अेटीट्यूड (Attitude) है वह क्यों है? अून लोगों से पूछा गया कि आप जिस तरह बाजू खड़े होकर सिर्फ बातें क्यों करते हैं, तो अुन्होंने कहा कि यह सब दिखावे की चीजें हैं, कलेक्टर साहब आये, अुन्होंने झाड़ लगाया, बाद में कुछ होने जानेवाला तर्ही है, यह हम जानते हैं। कलेक्टर साहब यह जो काम कर रहे हैं वह अूनमें लोगों की खिदमत के जजबात हैं जिसलिये कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। यह आज लोगों की भावना है। अब्बाम में जो जिस तरह का ख्याल है उसको जब तक हम दुरुस्त नहीं करते तब तक यह कहना कि हम पंचसाला प्रोग्राम को पूरा करेंगे बिल्कुल गलत होगा। फायनान्स मिनिस्टर साहब ने कहा कि कैपिटलायजेशन आफ मैन पावर (Capitalization of manpower) होना चाहिये। मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान की तरक्की इसके बगैर नहीं होगी। मैं नहीं मानता कि अमेरिका

से या किसी बाहर। मुक्त से अतिवाद आने से हमारे यह सवाल हल होंगे। हिंदुस्तान के ३५ करोड़ लोगों की मेहनत करने की कृति का अतिमाल करके ही हम पंचसाला प्रोग्राम पूरा कर सकते हैं, यह हमारा विश्वास है, लेकिन मैं हुकूमत से पूछूंगा कि अव्वाम में काम करने का अतिस्पिरेशन (Inspiration) यहां क्यों नहीं पाया जाता, जिसका आपने कभी अंदाजा किया है, और इसके लिये आपने अब तक क्या कदम उठाये हैं? एक ओवर सियर से मिलने का मुझे मौका मिला। उन्होंने बताया कि एक गांव में पी. डब्ल्यू. डी. मिनिस्टर या और कोई मिनिस्टर साहब आनेवाले थे और उनको यह बताना था कि वहां पर एक रोड अव्वाम ने अपनी मेहनत से बनाया। एक दिन लोगों को बुलाया गया। लोग आये, कुछ काम किया और चले गये। फिर लोग नहीं आये। अफसरों ने कहा कि रोड तो पूरा होना चाहिये क्योंकि मिनिस्टर साहब को हमने बताया है कि लोग रोड बनानेवाले हैं, डेवलपमेंट प्लान्स (Development plans) के तहत अव्वाम का रास्त कोआपरेशन हमको मिल रहा है। लोग तो आने के लिये तैयार नहीं थे तब सवाल आया कि अब क्या करना चाहिये? फिर एक कान्ट्रेक्टर को बुलाया गया और उन्होंने अपना लेबर लाकर रास्ता पूरा कर दिया, लेकिन कान्ट्रेक्टर साहब को यह हिदायत दी गयी कि जिस दिन मिनिस्टर साहब आयेगे उस दिन आपको या आपके लोगों को यहां नहीं रहना चाहिये नहीं तो आप बता देंगे कि यह काम अव्वाम ने नहीं किया है बल्कि मैंने किया है। आखिर मिनिस्टर साहब वहां गये, रोड देखा सब कुछ हुआ। उनको बताया गया कि अव्वाम ने रोड बनाया है और उन्होंने भी सौचा होगा कि अव्वाम ने ही बनाया होगा। अगर आप चाहें तो यह रोड कौनसा है कहां का है, सारे तफसीलात मैं दे सकता हूं। अफसोस के साथ मुझे यह सब कहना पड़ रहा है लेकिन मैं इसीलिये बता रहा हूं कि हुकूमत इससे कुछ सीखे, कि आपके पंचसाला प्रोग्राम से लोगों में अतिस्पिरेशन पैदा नहीं हो रहा है। जब तक पुराने चौखटे को बदलने की आप कोशिश नहीं करते तब तक यही होनेवाला है। पुराने चौखटे में यह ताकत नहीं है कि वह मुक्त में मेन पावर (Manpower) कैपिटलाइज (Capitalise) करने का अतिस्पिरेशन (Inspiration) पैदा कर सके। इस तरह के डेफिसिट बजट से और बिना अव्वाम के कोआपरेशन के हम अपना पंचसाला प्रोग्राम पूरा करना चाहें तो वह कभी पूरा नहीं हो सकता फायनान्स मिनिस्टर साहब ने अपनी स्पोच के आखिर में कहा है कि जैसे जैसे हमारा प्रोग्राम बढ़ता जायगा हमारी आमदनी बढ़ती जायगी और आपको ग्लूमी पिक्चर (Gloomy picture) रखने की कोजी जरूरत नहीं है। पिछले साल बजट के वक्त उस वक्त के फायनान्स मिनिस्टर साहब ने भी यही कहा था, लेकिन तमाम स्वाहिशात के बावजूद हम देख रहे हैं कि हमारा रेवीन्यू कम होते जा रहा है और डेफिसिट बढ़ता जा रहा है ऐकनॉमिक स्लम्प (Economic slump) आ रहा है जिसके बारे में हम बहुत दिनों से सोचते थे, पंचसाला प्रोग्राम के तहत हम जो अुम्मीद कर रहे थे कि अव्वाम की मेहनत को कैपिटलाइज करके हम जिन सबालों को हल करेंगे, वह नहीं हो रहा है। यह क्यों नहीं हो रहा है जिसको तय करने के लिये कोजी एक्सपर्ट कमेटी नियुक्त करने से यह सवाल हल होनेवाला नहीं है। यह सब इसीलिये नहीं हो रहा कि पुराने चौखटे को तबदिल किये बगैर ही हम जिन चीजों को हल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब तक चौखटा तबदिल नहीं होता तब तक लोगों में अतिस्पिरेशन पैदा नहीं होता और अतिस्पिरेशन पैदा नहीं होता तो काम नहीं होता। जैसा मैंने पहले अर्ज किया कि यह जो रस्ती खर्च आउट गोजिंग फोर्स (Outgoing forces) और अव्वाम की गोजिंग फोर्स (Growing forces) में चल रही है उसमें पुरानी चौखट टूट के ही रहेगी जिसके बारे में मुझे शक नहीं है।

लेकिन मैं सिर्फ यही जानना चाहता हूँ कि मामूली तरीके से यह चौखट टूटनेवाली है या जिसके लिये अव्वाम को अन्किलाब का अंकदाम करना पड़ेगा यही सवाल हमारे सामने है। मैं और मेरी पार्टी चाहती है कि हुकूमत जिस पर सज्जीदगी से सोचे और हमारे कौमी जिदोजहद के वक्त हमारा जो रवैया था उसको अव्वाम के सामने रखकर उसमें अन्सपिरेशन पैदा करने के लिये कदम अठाये। असा किया गया तो ही मामूली तरीके से हमारे सवाल हल होंगे। असा नहीं हुआ तो चौखट तो टूटेगी ही लेकिन उसमें तकलिफ होगी, अन्किलाब होगा, कभी लोगों को कुर वानियां करती पड़ेगी। अभी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अमेरिका को कारंवाओ के खिलाफ जो आवाज अठाओ तो लोगों में अक तरह की अन्सपिरेशन पैदा हुओ और सारा मुल्क अुनके पीछे आज खडा हुआ है। अुनकी होम पालिसी के बारे में कम्युनिस्ट पार्टी या दीगर पार्टियों में डिफरन्स आफ ओपिनियन (Difference of opinion) जरूर है; लेकिन जब मुल्क की आजादी का सवाल हमारे सामने आ रहा है, मुल्क को घोखा पैदा होने के अिमकानात हैं तो कम्युनिस्ट पार्टी और दीगर पार्टियां अमेरिका की तरफ से जो सोशिये हो रही हैं अुनका मकाबला करने के लिये पंडित नेहरू के कंधे से कंधा लगाकर लडने के लिये तैयार हो गयी हैं। यह क्यों हो रहा है? लेकिन मुल्क के अंदर मामूली मेहनत के काम करने के लिये अव्वाम में यह अन्सपिरेशन क्यों पैदा नहीं हो सकता? कल ही चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि हिंदी के बारे में हम सब अक जगह आ सकते हैं तो दूसरे सवाल के बारे में क्यों नहीं आ सकते? मैं भी यही सवाल कलंग कि दूसरे सवालों के बारे में हम क्यों नहीं अक जगह आ सकते? पंडित नेहरू की आटोबायग्राफी देखिये, फ़ैजपूर और कराची कांग्रेस के रेजोल्यूशन्स देखिये, और निजामाबाद कांग्रेस के रेजोल्यूशन्स को देखिये। अस वक्त क्या हुआ था और आज क्या हो रहा है जिसका अिम्तियाज किजीये अुनमें किये गये वायदों को लेकर आप चलेंगे तो सारी पार्टियों की अिमदाद आप हासिल कर सकते हैं किसानों को रिलीफ (Relief) देने का सवाल आता है तो पब्लिक का कोआपरेशन हासिल हो सकता है; लेकिन कौमी सवालों को बालायेताक रखते हुअे कुछ व्हेस्टेड अिंटरेस्ट (Vested interest) को कायम रखने के लिहाज से आगे बढ़ते हैं तो अिसा से भी अिमदाद हासिल नहीं हो सकती। आप वायदा करते हैं कि अव्वाम से अिमदाद हासिल हो रही है, पांचसाला प्रोग्राम पूरा करेंगे, अव्वाम की परचेजिंग पावर (Purchasing power) बढ़ेगी, रोजगारी बढ़ेगी और मुल्क की तरक्की होगी लेकिन पिछले दो साल के अनुभव के बाद हम महसूस कर रहे हैं कि असा नहीं हो रहा है। आपकी अुम्मीद पूरी नहीं हो रही है और जो पुराना ढांचा बरकरार रखा गया है उसका बोझ दिन ब दिन अव्वाम पर बढ़ता चला जा रहा है। यह जो बोझ बढ़ता जा रहा है अुसी की वजह से कहीं न कहीं यह पुराना चौखट टूट जायगा। त्रावनकोर-कोचीन में हम यही चीज देख रहे हैं। वहां हम कामयाब हुअे हैं य नहीं यह सवाल अलग है, लेकिन पुराना चौखटा वहां टूट रहा है यह साफ बात है। आज वह टूटा, कल हैदराबाद में टूटेगा या आंध्र में टूट जाय लेकिन पुराना चौखटा अब रहनेवाला नहीं है। असलिये दूरदेशी और अकलमंदी की बात होगी कि आज जो पार्टी बरसरे अेक्त्तदार है वह अपना हक वक्त पर ही तबदील करे मैं जानता हूँ कि मेरी अपील अैसे कानों पर पड़े जो जिस तरह की बातें सुनने की आदी हो गयी हैं और अपने रवैये को तबदील न करना चाहे; लेकिन मुझे मालूम है कि चंद अैसे भी कान हैं जो मेरी अपील को सुने सकते हैं और अुन्हीं से मेरी यह अपील है और वे ही अस चौखटे को तबदील कर सकते हैं। मैं कोअी नअी चीज सामने नहीं रख रहा हूँ। हमारी

पुरानी मांगे आज भी मौजूद हैं। अनुको लेकर ही हम अपने मुक्त को बेहतर बना सकते हैं जमाने का जो नकाजा है अनुको सभने रखते हुअे हम आगे बढे तो हम आज का पॉलिसी मे तबदिली कर सकते हैं, डेफिसिट बजट का तरफ जो हमारे कदम जा रहे हैं, अनुको रोक कर सरप्लस बजट की तरफ हम जा सकते हैं।

पंच साला योजना का देखते हुअे हमको इस बात का ख्याल करना पडेगा कि कही हम ओव्हर कैपिटलायजेसन नो नहीं कर रहे हैं ? हमारी चद स्कीमे औसी है कि जिनसे रेवीन्यू वढाने की दृष्टी से फायदा हो सकना है लेकिन अनुकी तरफ ज्यादा तबज्जह नहीं दी जा रही है। अक अक्सपर्ट के तौर पर मैं इनके बारे मे ज्यादा नहीं कह सकता लेकिन कुछ चीजो को देखकर औसा मालूम होता है कि दिन ब दिन ह्पारा खर्च वढता जायगा, आमदनी के जराये कम होते जायेंगे और खर्च और आमदनी के बीच की जो गॅप (Gap) पूरी होनी चाहिये वह पूरी नहीं हांगी। इन प्रोजेक्टस के सिलमिले मे क्या हो रहा है, इसके लिये जो अस्टीमेटेड बजट (Estimated budget) था वह अक या दो करोड मे बढाना पडा है। मसलन तुगभद्रा प्रोजेक्ट या किंसी और के बारे में पिछले अस्टीमेटेड बजट के अक या दो करोड रुपये हमें ज्यादा देने पडे। इसकी क्या वजह है ? क्या हुकूमत की तरफ से यह देखा जाता है कि वहां जितना माल चाहिये अतना ही जा रहा है या अुससे ज्यादा जा रहा है, वहां जो माल पडा है वह सही तौर से डिस्तेमाल किया जा रहा है या नहो ? यह मामूली चीजें हैं लेकिन हमारा करोडो रुपया कैपिटल की तरह इनमें लगाया गया है इसलिये अनुकी तरफ देखना भी जरूरी है।

आखिर में अँटी करप्शन की तरफ में हाअुस को तबज्जह दिलाना चाहता हूं। इसके लिय हुकूमत ने अक लाख की गुजाअिश रखी है। मैंने इस चीज को आज तक कअी बार हाअुस के सामन रखा है, राजप्रमुख के अँड्रेस के वक्त भी मैंने इसको रखा था लेकिन अुस वक्त चीफ मिनिस्टर साहब हाजिर नहीं थे। मैंने कहा था कि 'सीजर्स वाअिफ शुड बी बियांड ससपिशन' (Caesar's wife should be beyond suspicion) अगर करप्शन दूर करना है तो हायेस्टक्वार्टर्ससे इसके बारे में आज ही से शुरू होना जरूरी है। हुकूमतकी जो स्ट्रेटेजिक मशीनरी (Strategic machinery) है वह बियांड डाउट (Beyond doubt) होनी चाहिये। अुपर से यह चीज शुरू होती है तो करप्शन हम दूर कर सकते हैं। आपको मालूम होगा कि पिछले साल जो लोग चायना जाकर आये हैं कम्युनिस्ट ही जाकर आये हैं औसी बात नही नानकम्युनिस्ट और काँग्रेस लोग भी जाकर आये हैं अुन्होंने बताया है कि वहां करप्शन को दूर करने के लिये नेशनल मूव्हमेंटस (National movements) की तरह वहां दो मूव्हमेंटस चलायी जा रही है। लोगों में जो करप्शन और ब्लैक मार्केटिंग होता है अुसको और गव्हर्नमेंट मशीनरी में चलनेवाले करप्शन को दूर करने के लिये और गव्हर्नमेंट के टैक्सेस टालने की जो कोशिश की जाती है अुसके लिये अक इस तरह दो मूव्हमेंटस वहां चलायी गयीं और नतीजतन छः महीने के अदर देखा गया कि अक जमाने से जो अक बहुत बडा करप्शन वहां था वह दूर हो सका है। वहां से आये हुअे लोग बताते हैं कि हाँटेल के किसी वेटर (Waiter) को आप टिप देंगे तो कहता है कि यह गुनाह है, मैं इसको नही लूंगा। हिंदुस्तान में आज हमारे आमदनी के जराये बहुत महदूद हैं और मुक्त की तरक्की करने के कअी सवाल हमारे सामने हैं। औसी हालत में हमको भी अक नेशनल मूव्हमेंट अुसी तरह से चलानी पडेगी जिस तरह से आज चायना में चलायी जा रही है। चायना में

जो अंटी करप्शन मूव्हमेंट चलायी जा रही हैं उसमें पब्लिक का करप्शन दूर करनेवाली मूव्हमेंट को मैनफैन कहा जाता है और गव्हनमेंट के टैक्स को टालना ब्लैकमार्केट करना, गव्हनमेंट के कारखानों में कम पैदावार करने की कोशिश करना अिनको दूर करने के लिये जो मूव्हमेंट चलायी जा रही है उसको अर्टी कहा जाता है। चायना में ये जो अंटी करप्शन और अंटी टैक्स अिव्हेजन मूव्हमेंट्स (Anti-tax evasion movements) चालू की गयी हैं वहीं हमारे यहां भी चालू करना जरूरी है। क्योंकि जो पुराना चौखटा अंप्रेजों ने और यहां के निजाम ने हमको दिया है उसकी खामियां हमको दूर हो। यह जो अेक पुरानी रस्टेड मशीनरी (Rusted machinery) है उसको अच्छा बनाने की कोशिश हमें करनी चाहिये। अंटी करप्शन कमेटी की रिपोर्ट हुकूमत के सामने आयी है। मैं यह नहीं समझ सकता कि हुकूमत अब्बाम को कान्फिडन्स में लेने के लिये जिस रिपोर्ट को सामने क्यों नहीं लाती ताकि अब्बाम यह सोचे कि उसमें क्या मवाद है और किस तरह से उसको करप्शन दूर करने के लिये हुकूमत की मदद करनी चाहिये। कोअी भी गव्हनमेंट अब्बाम के रास्त नाबून के बगैर, उसकी अेक अेखलाखी ताकत अपने पीछे खडी किये बगैर कामयाब नहीं हो सकती। करप्शन की जो मशीनरी आज मुल्क में काम कर रही है उसको तोडना है तो अब्बाम की ताकत हमको हासिल करनी होगी। अब्बाम की ख्वाहिश है कि करप्शन को दूर किया जाय। हाल ही में अूमरगा में कम्युनिस्ट पार्टी के अेक श्री. श्रीनिवासराम अंहकारी नामी कार्यकर्ता ने वहां के लोहारी के अेक सब-अिन्स्पेक्टर के जुल्म और करप्शन के खिलाफ कदम अुठाय़ा और उसकी कार्रवाजियां पब्लिक की जानकारी के लिये अेक बोर्ड पर लिखना शुरू किया। जिस दुकान पर वह बोर्ड लगाया जाता था उस दुकान के मालिक को डी. अेस. पी. की तरफ से धमकाया गया कि अगर फिर से बोर्ड लगाया जायगा तो तुम्हें गिरफ्तार किया जायगा, जेल में डाला जायगा, और मुकदमा चलाया जायगा। श्री अंहकारी को भी धमकाया गया। डी. अेस. पी. ने वह बोर्ड भी जव्त कर लिया है और कहते हैं कि हम श्री अंहकारी पर मुकदमा चलायेंगे। मैंने जिस सवाल को असलिये हाअुस के सामने रखा है कि मैं जानना चाहता हूं कि आया हुकूमत अुस सब-अिन्स्पेक्टर के खिलाफ और वहां के डी. अेस. पी. के खिलाफ क्या कदम अुठाना चाहती है? मैं यह जानना चाहता हूं कि जिस तरह से अब्बाम करप्शन को दूर करने के लिये जो कोशिश कर रही है उसकी हुकूमत ताअीद करती है या अुस सब-अिन्स्पेक्टर या डी. अेस. पी. की ताअीद करती है? अगर हुकूमत अब्बाम की ताअीद करेगी तो सारा करप्शन बगैर कोअी अंटी करप्शन कमेटी कायमकिये और जितना खर्चकिये रोका जा सकता है। चीफ मिनिस्टर साहब और दीगर मिनिस्टर साहब जो यहां बैठे हुअे हैं वे अेक जमाने के बकला हैं। अब्बाम की तहरीकों में काम करनेवाले हैं। देहातों के होनेपर भी शहरों में रहनेवाले हैं और करप्शन कौन और किस तरह से करता है जिसकी सारी जानकारी है। निजाम के जमाने में जब यही लोग कहा करते थे कि फलां डिपार्टमेंट में करप्शन है। वह कैसे होता है वह अुन्हें मालूम नहीं अैसी बात नहीं है। जिसके लिये अंटी करप्शन कमेटी मुकर करके तय करने की जरूरत नहीं है। दो सवाल हमारे सामने हैं। अेक यह कि करप्शन सचमुच दूर करना है या नहीं और दूसरा यह कि अुसके लिये अब्बाम का ताब्वून हमें हासिल करना है या नहीं। चायना में जो मुमकिन हो सका वह हिंदुस्तान में क्यों नहीं हो सकता, लेकिन अुसके लिये पब्लिक को कान्फिडन्स में लेने की जरूरत है। जिसलिये मैं हुकूमत से अर्ज करूंगा कि वह अंटी करप्शन कमेटी की रिपोर्ट शायी करें और अब्बाम का ताब्वून हासिल करने की कोशिश करें, और जहां जहां अब्बाम की तरफ से करप्शन को दूर करने की कोशिश की जाती है वहां वहां अुसको अब्बाम की ताअीद करनी चाहिये। आखिर में जैसा मैंने

کہا کہ 'سیجس' واؤف ہڈ وی بیاؤڈ سامپشن' اؤس لہاؤج سے ہکومت کو سونچنا چاہیے۔
مؤجے اؤمید ہے کہ ہکومت ان چیزوں کی طرف توجہ دے گی۔

اےک اور چیز ہاؤس کے سامنے رکھ کر میں اپنی تکریر ختم کروں گا۔ راجپرموؤ کے اڈریس کے وقت میں نے اور کمونیسٹ پارٹی کے ممبروں نے اس چیز کو ہاؤس کے سامنے رکھا تھا کہ دو سال ہونے کے باوجود سیاسی کدیوں کو رکھا نہیں کیا گیا ہے، شاید آپ اُن کو سیاسی کدی نہیں سمجھتے، لیکن اےک نجزریہ کے تھت جھوجھد جاری تھا۔ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اُنہوں نے کوربانیاں کی ہیں۔ ممکن ہے اُن کے نجزریہ کو آپ نہ مانیں۔ متبہد ہو سکتا ہے، لیکن جنہوں نے اےک سیاسی نجزریہ کے لیے کوربانیاں کی ہیں اور اُن تمام جدوجہد کے بعد آج جو اےک ایلے-کٹڈ مشینری یہاں کامیاب ہوئی ہے تو ہکومت کے لیے جھری ہے کہ تمام سیاسی پارٹیوں کو جیادہ سے جیادہ آجادی اس ڈیموکریٹک سٹاپ میں کام کرنے کا ماکہ دے اور اس لیے اُن تمام سیاسی کادیوں کو ڈوبنا جھری ہو جاتا ہے۔ میں خود اور کمونیسٹ پارٹی کی طرف سے چیف منسٹر سارہب سے کئی مرتبہ ان کے لیے تمارجیدگی کی گئی ہے، ہکومت نے واڈا بھی کیا تھا کہ اس سلسلے میں وہ سونچے گی لیکن اس کے بارے میں جس طرح سے املی جاتا پھرایا جانا چاہیے اُس طرح سے پھرایا نہیں جاتا رہا ہے۔ میں کہوں گا کہ ہکومت اب اس کے بارے میں جلد سے جلد سونچے اور تمام سیاسی کادیوں کو رکھا کرے۔ اُن کے خلیفہ جو کیسے چلائی جا رہی ہے اُن کو وڈڈا (Withdraw) کر لے اور اےک اےسا اٹموسفیر (Atmosphere) پیدا کرے کہ جہاں جو جلم اور سیتام ہو رہے ہیں وہ سب ختم ہو جائیں۔ کئی شکیاتیں اس کے بارے میں اب تک ہاؤس کے سامنے آئی ہیں، میں اُن کی تفصیل میں جاکر اُن کو دھارنا نہیں چاہتا، لیکن کانگریس کو ڈیڈنگر باقی سب سیاسی پارٹیوں میں یہ اےک ام سٹال پیدا ہو گیا ہے کہ ہکومت کی طرف سے تمام پارٹیوں کے کام میں رکاوٹ پیدا کرنے کی پولس کے جریہ سے کوشش کی جاتی ہے اُن کے کارکنوں پر فائل کیسے (False cases) چلائی جاتی ہیں، ڈیڈے مکدمات میں اُن کو فسانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اےسے کئی کیسے ہکومت کے سامنے لائے گئے ہیں اور آہدہ بھی لائے جاتے ہیں۔ ہم اپنی سٹریٹس کے لیے یہ مڈو (Motto) رکھنا چاہتے ہیں کہ ہم ابوام کے خدمتگار ہیں مڈو اٹ یور سٹریٹس (Motto at your service) اگر اُس کو سچمؤچ اممل میں لانا ہے تو کرپشن کو اور رپریسن (Repression) کو دُور کرنا پڈے گا اور ملک کے اندر اےسے حالات پیدا کرنے پڈے گے جس سے ہم تمام لوگ تمام پارٹیاں ملک کی بھبھدی کے لیے آگے کدم اڈا سکیں۔ میں اؤمید کرتا ہوں کہ میں نے جو چیزیں ہاؤس کے سامنے رکھی ہیں اُن کے اُپر ہکومت سنجیدگی سے سونچے گی اور جو ٹاپ ہوی اڈمنسٹریشن سکریٹری سٹریٹس پر ہو رہا ہے اُس کو دُروست کرے گی، نیشن بیلڈنگ کے لیے جو اب ۷۰ فیصد رکھا گیا ہے اُس میں اڈیافا کر کے اُس کو ۶۰ فیصد کرے گی۔ ہکومت کی ڈیکسیشن پالیسی اےسی ہو کہ جس سے اُس کا انٹینڈنس سرمایہدار تہ کے پر جیادہ پڈے چوکے وہ اُس کو بڈاؤ کر سکتے ہیں اور ام لوگوں کو ڈیکسیشن سے ریلیف ملے اور اس کے ساتھ ساتھ پمڈل سٹاپ میں بھی تہذیبی کرنے کی طرف کوشش کی جائے گی۔

شری جی۔ راجہ رام (آرمور) مسٹر اسپیکر سر - پچھلے دو سال کے بیٹس کو اور اب اس تیسرے سال کے بیٹ کو دیکھنے کے بعد عام لوگوں کے دلوں میں نہیں تو کم از کم میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ کانگریس پارٹی کی گورنمنٹ جو اس وقت

اقتدار میں ہے اسکے سامنے کوئی واضح نقشہ آئندہ سماج کو بنانے کے سلسلہ میں قوم اور ملک کو ترقی کے راستہ پر لیجانے کے لئے نہیں ہے۔ کوئی واضح پلان ہے ایسا ہم نے محسوس نہیں کیا۔ ہر ایک بھٹکے ہوئے راہی کی طرح اندھیرے میں ادھر کچھ راہ ملی، پھسلا پھر اودھر نکرا کر واپس آیا ایسا ہی آج کی حکومت کا حال ہے۔ بالکل اندھیرے میں ایک بھٹکے ہوئے راہی کی طرح ہماری آج کی حکومت چل رہی ہے۔ کانگریس نے اقتدار میں آنے سے پہلے جو نقشہ عوام کے سامنے رکھا اور ۶۰ سال کی آزادی کی لڑائی کے دوران میں آئندہ بننے والے ہندوستانی سماج کا جو خاکہ پیش کیا تھا اسکو اس بجٹ کے مختلف پہلوؤں کو سامنے رکھ کر میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کرونگا کہ وہ اوس راستہ پر نہیں جا رہی ہے جو کہ اوسکی منزل ہے۔ وہ ترقی کی منزل کی طرف گامزن نہیں ہے۔

چنانچہ سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ ہمارا اور گورنمنٹ کا یہ آدیش تھا کہ ملک میں ایک ایسی سماج کی رچنا کی جائے جہاں ایکسپلوئیشن (Exploitation) نہ ہو۔ جہاں طبقات نہ ہوں۔ کلاس لس سوسائٹی (Classless society) ہو۔ وہ تفرق ختم کر دیا جائے جو برسہا برس سے پچھڑے ہوئے طبقات پر برتا جاتا یا کسی نہ کسی وجہ سے اقتدار میں آکر پچھلی گورنمنٹ نے روا رکھا تھا اور ان بست طبقات کو غلامانہ حیثیت دی تھی۔ انکی اتنی کر کے ہم فرق مٹانا چاہتے تھے اور کرنا یہ چاہتے تھے کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ آدمی نیچ ہے اور وہ آدمی اونچ ہے اگرچہ کہ معیشت کے اعتبار سے سوسائٹی میں کچھ فرق ہو سکتا ہے۔ انکے رہنے سہنے اور کھانے پینے میں کچھ فرق ضرور ہو سکتا ہے مگر دوسرے لوگوں کو لوٹ کھسوٹ کر کے بلند طبقات جو شوشن کرتے ہیں اسکو ختم کر دیا جائے اور جو طبقہ غلامانہ حالت میں ہے اسکی اتنی (उत्थिति) کی جائے چنانچہ آزادی حاصل ہونے کے بعد الکشن سے پہلے کانگریس نے نظام آباد کے ادھیویشن (अधिवेशन) میں اور پھر اپنے مینیفیسٹو (Manifesto) میں کہہ کر کہا کہ اگر کانگریس پارٹی اقتدار میں آجائے تو اسکے یہ ٹارگٹس (Targets) ہونگے۔

اب اس بجٹ کو دیکھنے کے بعد اور پچھلے دو سال کے بجٹس کو دیکھنے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم اس طرف قدم نہیں بڑھا رہے ہیں۔ کیا ہم اس طرف قدم بڑھا رہے ہیں اور کیا ہم نے جو وعدہ کیا تھا کہ وہ صرف معاشی پستی کو دور کریں گے۔ بلکہ ڈی سنٹرلائزیشن آف اڈمنسٹریشن (Decentralisation of administration) کی طرف قوم کو لیجائینگے یہ بتلانے کی کوشش کریں گے کہ صحیح طور پر جنتا (जनता) کو یہ محسوس ہو کہ جنتا اپنے آپ پر راج کر رہی ہے۔ آج تیسرا سال گزر رہا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ معاشی ڈی سنٹرلائزیشن تو کجا کم سے کم جو پولیٹیکل اتھارٹی (Political authority) ہے اس میں کہاں کہاں ڈی سنٹرلائزیشن کی طرف لے جا رہے ہیں یا بالکل ویسا ہی جیسا کہ فارنرس (Foreigners) انگریز جیسی حکومت کرتے تھے؟ ویسی ہی حکومت آج کر رہے ہیں وہ اپنے اقتدار

اور انہی سان و سؤ نت کو قائم رکھنے جن جن ایجنسیوں کو جیسے شطرنج پر مہروں کو بٹھاتے ہیں ، بٹھائے تھے ویسے ہی بٹھانا چاہتے ہیں ۔ انکو وہاں سے ہٹانے کا ارادہ آج اس تیسرے سال کے بجٹ میں بھی نہیں ہے ۔ چنانچہ میرا یہ کہنا ہے کہ ہماری جو سیاسی طاقت ہے وہ دلی میں اور حیدرآباد میں سمٹ کر رہ جاوے گی ۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ بار بار یہ کنفشنس (Confessions) کرنا کہ عوام کی مدد نہیں ملتی ۔ فائو ابر بلان میں بھی یہ کہا گیا کہ راستہ میں بارٹیاں ایسی حائل ہیں کہ کوآپریشن نہیں ملنا تو ہم کیا کریں ۔ تو میں یہ کہوں گا کہ کسی ایک سیاسی پارٹی یا کچھ سیاسی پارٹیوں کے یہ کہنے سے کہ حکومت کا ساتھ نہ دو عوام سانہ دینے سے باز نہیں رہتے ۔ میں یہ ماننے کے لئے تیار نہیں ہوں ۔ بلکہ اگر یہی حالت رہے تو سیول ڈس او بیڈینس (Civil disobedience) کی طرح پھر ایک مہم کی جائیگی ۔ جو سنیے آپ نے انکو دکھائے تھے اور جو پروگرام انکے سامنے رکھا تھا اگر وہ پورا نہ کریں تو یہ ہوگا ۔ جب تک ایسا نہ ہو کہ ہمارے دیش کی جو سیاسی شکتی ہے اسکو چار کھمبوں پر جسکو کہ میں فور پلر اسٹیٹ (Four Pillar State) کہنا ہوں اسن نقطہ نظر سے ہماری گورنمنٹ یا کوئی بھی گورنمنٹ ہندوستان میں قائم کرنے کے لئے نہ بڑھیگی تو میں سمجھتا ہوں کہ اسکا یہ دعویٰ کہ وہ کلاسلس سوسائٹی (Classless society) یا کاسٹلس سوسائٹی (Casteless Society) یا طاقت کی مساویانہ تقسیم کا دعویٰ صحیح نہیں ہو سکتا ۔

چار کھمبوں والے راج کی طرف میں کہوں گا کہ وہ ڈس ہارٹڈلی آر ہاف ہارٹڈلی (Disheartedly or Halfheartedly) قدم اٹھایا گیا اور پنچائت کے سلسلہ میں اسٹیٹ میں کام شروع ہوا ۔ لوگوں نے دلچسپی لی اور ہمیں یہ معلوم ہوا کہ دیہاتوں میں جہاں جہاں بٹی کمیٹیاں قائم ہوئیں وہ آگے بڑھیں ۔ لیکن ایک سال گزرنے پر حکومت نے سوچا کہ اگر انکو سیاسی طاقت استعمال کرنے کا موقع دینگے تو انکا اندھیرے میں رکھ کر حکومت کرنے کا جو خیال ہے وہ پورا نہوگا ۔ یہ سمجھ کر حکومت نے مالی امداد کو گھٹانا شروع کر دیا اور مالی امداد پندرہ فیصد سے ساڑھے سات فیصد کر دی گئی ۔ ورنہ اس بیٹ میں نئے پنچائت کمیٹیاں بنانے اور جو کچھ بھی کمیٹیاں ہیں انکو زیادہ مالی امداد دینے کے لئے گنجائش ہوتی لیکن گورنمنٹ کا یہ مقصد نہیں ہے تاکہ سیاسی ستہ (ستا) عوام کے ہاتھوں میں منتقل نہ ہو جائے ۔ چنانچہ انکا یہ دانستہ پلان ہے ۔ انہوں نے سوچ سمجھ کر یہ کیا ہے کہ کمیٹیوں کو ناکام بنائیں تاکہ یہ طاقت حیدرآباد کی حکومت اور حیدرآباد کے اڈمنسٹریشن کے ہاتھوں میں سمٹ کر رہ جائے ۔

اسکے علاوہ ڈی سنٹرلائزیشن کے سلسلہ میں حکومت نے ان کمیٹیوں کو الیکٹیڈ (Elected) بنانے کے لئے کونسا قدم اٹھایا میری یہ ہر بات گورنمنٹ پر ایک چارج ہے کہ جو گورنمنٹ حیدرآباد میں ہے اسنے شوشن کرنے والے غیر ذمہ دار سیٹھ ساہوکار لوگوں کو نامینیٹ (Nominate) کیا ہے اور ساڈھے

جو بھی دھرا راج چلا ہے اسکی آڑ لیکر شکار کھیلنے کی کوشش کی ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ پولیس ایکشن سے پہلے یہ تھا اور وہ تھا۔ اسکے بعد ڈویل اڈمنسٹریشن (Dual Administration) تھا تو وہ بھی اب ختم ہو گیا۔ لیکن آج ڈسٹرکٹ بورڈ پر واقعی طور پر کن لوگوں کو کام کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے۔ پہلے جیو لوگ تھے اون ہی کو موقع دیا جا رہا ہے۔ اب اگر پروگریسیو لوگ کچھ کام کرنا چاہتے ہیں تو انہیں کلکٹر جو ڈسٹرکٹ بورڈ کا پریسیڈنٹ ہوتا ہے اسکے پاس جانا پڑتا ہے۔ اگر کلکٹر کی رائے کے خلاف کوئی مسئلہ ہو تو انکو نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔

مسٹر ڈپٹی اسپیکر - اب ہم ۵۔۳۰ تک اڈجرن ہوتے ہیں۔

The House then adjourned for recess till Half Past Five of the Clock.

The House reassembled after recess at Half Past Five of the Clock.

MR. DEPUTY SPEAKER IN THE CHAIR

Business-of the House

مسٹر ڈپٹی اسپیکر - قبل اس کے کہ ہم ڈسکشن شروع کریں میں یہ اناؤنس (Announce) کرنا چاہتا ہوں کہ چیف منسٹر صاحب کے ڈیمانڈس (۱۱ و ۱۲) مارچ سنہ ۱۹۵۴ء کو لئے جائینگے۔ اون پر موشن فار رڈکشن کل یعنی ۹۔ مارچ کو پانچ بجے تک دیدئے جائیں۔

Budget-General Discussion

شری جی۔ راجہ رام - مسٹر اسپیکر - میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آج کی حکومت جس کے ذمہ بجٹ پیش کرنے کا کام ہے وہ کوئی صحیح راستہ پر نہیں جا رہی ہے۔ چنانچہ گورنمنٹ نے ویلیج پنچایتس اور ڈسٹرکٹ لوکل بورڈس کو ڈیموکریٹائز (Democratise) کرنے کے سلسلہ میں بجٹ میں کوئی پروویژن نہیں رکھا ہے۔ بلکہ ان کو ناکام بنانے کے لئے ڈیلیبریٹ اٹمپٹ (Deliberate attempt) حکومت نے کیا ہے۔ کیونکہ اوس نے پنچایت کمیٹیوں کو اپنا کام کرنے کے لئے کوئی سرمایہ یا فینانس پرووائڈ (Provide) نہیں کیا۔ ہمارے پاس ۲۲ ہزار دیہات ہیں۔ گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہر اوس دیہات میں جسکی آبادی ہزار پندرہ سو ہو پنچایت کمیٹی قائم کی جائیگی اور اون کے لئے پندرہ پرسنٹ ریونیو انیشیل اسٹیجس (Initial stages) پر پرووائڈ کریگی لیکن دو سال گزر گئے اب تک اون مواضع میں پنچایت کمیٹیوں کا اعلان نہیں ہوا۔ یہی نہیں بلکہ جن مواضع کو شمار کر لیا گیا تھا اون کو بھی مالی نقطہ نظر سے کمزور کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ دوسری چیز یہ کہ نامزدگیوں کا طریقہ رکھ کر سارے پٹیل پٹواریوں کو جو برسہا برس

سے گاؤں کی تباہی کے ذمہ دار ہیں چور دروازے سے گھسایا۔ اور اس طرح اون کمیٹیوں کو ناکام بنانے کی کوشش کی۔ ہماری بیورو کریٹک مشنری (Bureaucratic)

(machinery) کو جو ورثہ میں چلی آ رہی ہے ہر موقع پر ان کمیٹیوں میں مداخلت

کرنے کا اختیار دیا گیا۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ کس طرح ڈپٹی کلکٹرس اور تحصیلدار

پمچایت کمیٹیوں کے فرائض کی انجام دہی میں حائل ہو رہے ہیں۔ وہ لوگ ہر مرتبہ

ان کمیٹیوں کے ممبروں سے بے عزتی کا سلوک کرتے ہیں۔ جب ان کے ہاتھ میں

کمیٹیاں رہنگی تو صحیح طریقہ پر پرچا تترراج کیسے قائم ہو سکتا ہے۔ ان کو مالی

نقطہ نظر سے کمزور کر کے اور کئی مشکلات پیدا کر کے ان کمیٹیوں کو ناکام بنایا جا رہا

ہے۔ ڈسٹرکٹ لوکل بورڈس میں بھی نامینیشن ہوتا ہے اور کلکٹر کو اس میں دخل

دینے کے اختیارات ہیں۔ فنڈ بھی کمزور ہے اور جو فرائض متعین کئے گئے ہیں وہ

بھی اتنے محدود ہیں کہ ان کا رہنا نہ رہنا برابر ہے۔ کلکٹر دو تین مہینوں میں

ایک مرتبہ یا ان کا من خوش رہا مہینہ میں ایک مرتبہ ممبروں کو اپنے گھر پر

بلاتے ہیں اور چائے وغیرہ پلا کر ان کو واپس کر دیتے ہیں۔ کیا یہی طریقہ ڈیموکریسی

اور ڈی سنٹرلائزیشن آف پولیٹیکل پاورس کی طرف ایک قدم ہے۔ حکومت ایک بھٹکے

ہوئے راہی کی طرح جا رہی ہے۔ کوئی نقشہ گورنمنٹ کے سامنے نہیں ہے۔ حکومت

نے یہ دیکھنے کی کوشش نہیں کی عوام کی کیا ضروریات ہیں ان کو کس طرح پورا کیا

جاسکتا ہے۔ ان کو تکمیل کرنے کے لئے فنڈس اور فینانسس کس طرح جمع کئے جاسکتے

ہیں۔ برسوں سے وہی مددات ہماری آمدنی کے ہیں۔ کبھی کبھی ایک آدھ ٹیکس کا

اضافہ کر کے آمدنی بڑھالی جاتی ہے اور اس کا بٹوارہ اور خرچہ وہی پرانے ڈھنگ سے

کیا جاتا ہے۔ آج کی حکومت عوام کے احساسات اور ان کی ضروریات کا اندازہ نہیں

لگا سکتی۔ ہم یہ کیسے اندازہ کریں کہ آخر حکومت کس سمت جا رہی ہے۔ موجودہ

زمانے کا نقشہ سامنے رکھ کر عوام کی ضروریات کو اس (Assess) کرنے اور

ان کو انالائز (Analyse) کرنے اور کن ضروریات کو پرائیٹی (Priority)

دینی چاہئے اور ان ضروریات کے لئے فنڈ کہاں سے حاصل کرنے چاہئیں

ان تمام امور پر غور کرنا ایک سویلائزڈ (Civilised) گورنمنٹ کا

فرض ہوتا ہے جو ایک ویل فیر اسٹیٹ (Welfare state) قائم کرنا

چاہتی ہے۔ لیکن اس کی بجائے بننے کی طرح سے جو پیسہ چند مددات کے تحت برسوں

سے چلا آ رہا ہے اوسکو پچھلے طریقوں پر ہی خرچ کیا جا رہا ہے۔ کیا آج اس طرح کے

بجٹس بنا کر ہماری حکومت ویل فیر اسٹیٹ بنانے کے راستے پر جاسکتی ہے۔ میں اس

سلسلہ میں ہماری آمدنی کے تھوڑے بہت جو ذرائع ہیں ان کا ذکر کرونگا کہ کس طرح

وہ ساکت ہیں۔ ہماری حکومت کے موازنہ میں لینڈ ریونیو کا درجہ دوسرے نمبر پر

آتا ہے۔ سب سے پہلے تو آبکاری کی آمدنی ہے۔ اس کے بعد لینڈ ریونیو۔ لینڈ ریونیو

کے اسٹیٹسٹکس (Statistics) کو ہم دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ وہ

کبھی پانچ ساڑھے پانچ کروڑ سے آگے نہیں بڑھی۔ اس کی کیا وجہ ہے۔ کیا یہ

کو اسی طرح ساکت رکھنا چاہتے ہیں۔ ہم سوسائٹی میں جو مساوات قائم کرنا چاہتے ہیں سوسائٹی سے طبقات کو ختم کرنا چاہتے ہیں کیا اس کے لئے لینڈ ریونیو کے یہ اسٹیسٹکس کافی ہوسکتے ہیں؟ لینڈ ریونیو کے طریقے میں بنیادی تبدیلی کرنا چاہئے۔ ورنہ یہ آمدنی ایسی ہی ساکت رہیگی اور غریبوں پر اس کا بار پڑتا رہگا۔ بچہلی گورنمنٹ نے پہلے کے زمانے کے حالات کے لحاظ سے اس کو قائم کیا تھا کہ کس طرح عہدہ داروں کو اپنے فرائض کی انجام دہی کے سلسلہ میں زیادہ سے زیادہ ڈسکریشن (Discretion) استعمال کرنے دیا جائے۔ اور کس طرح اون کو اپنے لئے زیادہ سے زیادہ رشوت اور ناجائز آمدنی پیدا کرنے کے مواقع دئے جائیں۔ کیا اس

زمانے کا مطمع نظر اس گورنمنٹ کا بھی ہے۔ اس لحاظ سے اس زمانے کی جو لینڈ ریونیو کے وصول کرنے کا اسٹرکچر (Structure) ہے اسکی ڈوری ڈھیلی چھوڑی گئی ہے۔ لیکن آج کی گورنمنٹ جو ڈیموکریسی کی بنیادوں پر قائم ہوئی ہے اور جو یہ دعویٰ کرتی ہے کہ وہ عوام کی بھلائی کے لئے کام کرتی ہے وہی سسٹم برقرار نہیں رکھ سکتی تلنگانے کی کاشت کا طریقہ ایک پیچیدہ طریقہ ہے۔ پٹیل پٹواریوں کو اسکا موقع دیا جاتا ہے کہ گورنمنٹ کے خزانہ کے خیال رکھے بغیر صرف اپنی جیبوں کو بھرنے کا خیال کریں اور اس کے مواقع انکو فراہم کئے جاتے ہیں۔ جیسا کہ چند معزز ارکان نے اس طرف ہاؤز کی توجہ مبذول کی تھی کہ تلف مال کی رپورٹیں کر کے گورنمنٹ کا لاکھوں روپیہ کا نقصان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اگر تلف مال کی رپورٹیں نہ ہوں جو جھوٹ موٹ لکھی جاتی ہیں تو لاکھوں روپیہ گورنمنٹ کی ٹریژری میں جمع ہوسکتا ہے۔ لیکن جو ڈھانچہ بن گیا ہے اسکی وجہ سے گورنمنٹ کے عہدہ دار اپنے جیب بھرنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ تلف مال کا جو طریقہ ہے اسکو تبدیل کرنا ضروری ہے۔ تاکہ پٹیل پٹواریوں اور گورنمنٹ کے عہدہ داروں کو اپنی جیب بھرنے کا موقع نہ رہے۔ نظام آباد اور دوسرے اضلاع میں لاکھوں روپیہ تاف مال کے سلسلہ میں لکھا جاتا ہے۔ تلف مال کے جھوٹے تختہ جات بنائے جاتے ہیں۔ وہ سارا روپیہ انکی جیبوں میں جاتا ہے۔ جو دھارے قائم کئے گئے ہیں وہ ڈرائی لینڈ کا لحاظ رکھتے ہوئے قائم کئے گئے ہیں۔ عہدہ داروں کے ڈسکریشن پر تلف مال کے عملیات ہوتے ہیں۔ جب تک اس طریقے کو تبدیل نہیں کیا جائیگا یہ بدنظمی باقی رہیگی۔ تہندی میں پٹیل پٹواری سازش کر کے پانی سپلائی کرتے ہیں۔ تہندی کے کاغذات میں اسکا اندراج نہیں ہوتا۔ ہرگاؤں میں جہاں تہندی ہوتی ہے یہ عمل ہوتا ہے۔ جب تک ہم ان امور کی جانب توجہ نہیں کوبینگے کوئی علاج نہیں ہوسکتا۔ گرداور اور پٹیل و پٹواری ان تینوں میں سازش ہوتی ہے اور غلط تختہ جات داخل کرتے ہیں۔ اس سے ہوتا ہے کہ جو مزید پیسہ وصول ہوتا ہے وہ ان لوگوں کی جیب میں جاتا ہے۔ اس سازش کو ختم کرنا چاہئے۔ میرا خیال یہ ہے کہ جب تک واٹر ریٹ سسٹم (Water rate system) نافذ نہ کیا جائے یہ خرابیاں باقی رہیں گی۔ اگر واٹر ریٹ سسٹم جاری کیا جائے تو ہمارے اسٹیٹ کی آمدنی میں اضافہ ہوگا۔ تہندی کا اختیار ولیج پنچایت بنا کر اسکے

تفویض کرنا چاہئے ۔ ان کو اختیار دینا چاہئے کہ وہ اس بارے میں فیصلہ کریں ۔
ایسا انتظام کیا جائے تو لاکھوں روپیہ کا جو نقصان دور رہا ہے وہ بند ہو سکتا ہے ۔
گورنمنٹ کے اکسچجر (Ex-chequer) میں آمدنی آئیگی ۔ لینڈ ریوینیو کا یہ قسودہ
نظام عوام کو اکسپلائیٹ (Exploit) کرنے کیلئے نافذ کیا گیا تھا تاکہ
اوس سے جو آمدنی ہو اپنے عیش و آرام پر صرف کی جاسکے ۔ ہمارے ہاں لینڈ ریوینیو کا
سسٹم ایسا ہے کہ دس ایکڑ زمین رکھنے والے سے بھی اوسی ریٹ سے لیا جاتا ہے
اور سو ایکڑ رکھنے والے سے بھی اوسی ریٹ سے لیا جاتا ہے اور ایک ہزار ایکڑ والے
سے بھی وہی ریٹ لیا جاتا ہے ۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جس کی زمین زیادہ ہے وہ تو
آسانی سے ریوینیو داخل کر سکتا ہے اوس پر کوئی بار نہیں ہوتا ۔ وہ زمین کو اقتادہ
بہنی چھوڑ دیتا ہے کیونکہ تین چار سو روپیہ جو قلیل مالگزاری ہوتی ہے وہ برداشت
کر سکتا ہے ۔ لیکن اس کو گریڈڈ سسٹم (Graded system) () پر
قائم کیا جائے تو اچھا ہوگا ۔ ہمارے لینڈ ریفرمس کا حال یہ ہے کہ جس نوعیت کے
وہ ہونے چاہئیں تھے نہیں ہوئے ۔ اگر گورنمنٹ گریڈڈ سسٹم اختیار کرے تو میں
سمجھتا ہوں کہ ہاری اس وقت جو پانچ کروڑ کی آمدنی ہے اس میں اور اضافہ
ہو سکتا ہے ۔ میرا خیال ہے کہ اس میں کم از کم دو گنا اضافہ ہو سکتا ہے ۔ آج اگر
ہم مینیمر مارجن (Minimum margin) رکھ کر پچاس ایکڑ والوں
کے لئے جو ریٹ ہے اس کو سائنٹیفک (Scientific) بنیادوں پر ۰۰ فیصد اضافہ
کے لحاظ سے تعین کریں اور سو ایکڑ والوں کے لئے اوس سے دو گنا ہو اور ایک ہزار
اور دو ہزار والوں کے لئے ۱۰ اور ۱۰۰ گنا ہو تو ایسی صورت میں وہ مجبور ہو
جائینگے کہ یا تو وہ اپنی زمینات کی سائیز (Sizes) کو گھٹائیں یا اوس زمین پر
محنت کر کے اوس زمین پر جو مالگزاری عائد ہو رہی ہے اوس کو ادا کریں ۔ ان
دونوں طریقوں سے وہ زمین کی طرف مائل ہونے پر مجبور ہونگے ۔ ساتھ ساتھ گورنمنٹ
کی آمدنی میں بھی اضافہ ہوگا ۔ لیکن افسوس کہ ہم نے ایسے طریقے اختیار نہیں کیے
بلکہ ایک ایکڑ والے اور ایک ہزار ایکڑ والے دونوں کو ایک ہی لکڑی سے ہانک
رہے ہیں ۔ اگر یہ طریقہ کار درست نہیں ہے تو پھر ایک طریقہ جو اختیار کیا جاسکتا
ہے وہ اگر یکلچرل انکم ٹکس کا طریقہ ہے اوس سے زیادہ میں اس کو پریفر (Prefer)
کرونگا ۔ اس میں شک نہیں اگر یکلچرل انکم ٹکس سے بچنے کے لئے ہر شخص کوشش
کریگا کہ جھوٹا ریکارڈ فراہم کرے تاکہ وہ آپ کے ضابطہ کے اندر نہ آسکے ۔ اور
اگر ریوینیو گریڈڈ سسٹم پر رکھا جائے تو وہ دینے پر مجبور ہوگا ۔ بجائے کوئی مناسب
طریقے کو اختیار کرنے کے ہم دیکھتے ہیں کہ وہی فیوڈل سسٹم (Feudal system)
کو مینٹین (Maintain) کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ۔ میں اے
ہی اشارے ہمارے بیٹ میں پاتا ہوں ۔ ہمارے لینڈ ریوینیو کی کلکٹنگ ایجنسیز
(Collecting agencies) پر کتنا صرفہ ہورہا ہے ۔ دوسرے مالک کے بیٹ
کو ہم دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ دس فیصدی کلکٹنگ ایجنسی پر خرچ کیا جاتا ہے

چھ روپیہ ٹکس وصول کرتے کیلئے اگر ہم چار روپیہ خرچ کر دیں تو یہ کرنی صحیح طریقہ کار نہ ہوگا۔ یہ بہت بیکار سی بات ہے۔ اتنا ٹاپ ہیوی آدمسٹریسٹس (Top-heavy administration) مناسب نہیں ہے۔ پانچ کروڑ کی آمدنی وصول کرنے کے لئے اگر ہم ریونیو کنگ ایجنسی (Revenue Collecting Agency) پر تین کروڑ روپیہ خرچ کر دیں تو کیا یہ مناسب بات ہوگی۔ ہمیں غور کرنا چاہئے کہ کیا یہ ضروری ہے۔ آخر اس ہیوی ایکسپنڈیچر (Heavy expenditure) کی کیا وجہ ہے۔ وجہ ایک ہی ہے کہ یہی سسٹم پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ پہلے جس طرح عہدوں پر اعلیٰ خاندان کے لوگوں کو لیا جاتا تھا اور وہ سالک کے مفاد کا خیال رکھے بغیر صرف اپنے فائدے کا خیال رکھا کرتے تھے۔ وہی طریقہ اب بھی چلا آ رہا ہے لیکن اس کو عوام اب ہرگز برداشت نہیں کر سکتے۔ عوام کا یہ خیال تھا کہ جب عوامی راج شروع ہوگا تو زیادہ سے زیادہ کوالیفیکیشنس (Qualifications) رکھنے والے اور زیادہ قابل لوگوں کو ملک کی خدمت کے مواقع ملیں گے لیکن آج بھی وہی رنگ ڈھنگ ہے جس کی وجہ سے گورنمنٹ کا کافی روپیہ خرچ ہو رہا ہے۔ اس کے باوجود جو فائدہ حاصل ہونا چاہئے تھا نہیں ہو رہا ہے۔ اس کے بعد میں یہ عرض کرونگا کہ آپکاری جو ہماری آمدنی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے عوام یہ سمجھ رہے تھے کہ کانگریس راج کے آنے ہی ملک سے ساری برائیاں دور ہو جائیں گی لوگ سمجھ رہے تھے کہ عوامی گورنمنٹ ان برائیوں کو دور کرنے کے لئے پہلا قدم اٹھائے گی اور وہ اپنی آمدنی کا خیال نہ کرتے ہوئے اس کو گرائیجیوول (Gradual) طور پر دور کریں گی۔ یہ کوئی پالیسی نہیں ہے کہ کسی کو دس روپیہ تنخواہ دیں اور اوس سے آٹھ روپیہ کسی نہ کسی طرح پھر حاصل کر لیں جائیں۔ اس طرح سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ حیدر آباد کا جو ڈھانچہ ہے اس کو ایک ڈھانچے سے دوسرے ڈھانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرنی چاہئے۔ اگر یہاں کے حالات کو یکسخت ٹھیک نہیں کر سکتے تو آہستہ آہستہ یکے بعد دیگرے ٹھیک کرنا چاہئے۔ مدراس اور سی۔ پی کی گورنمنٹ اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اگر ہم آٹھ منسٹرس اور آٹھ ڈپٹی منسٹرس رکھ کر اپنے اخراجات کو بڑھاتے رہیں تو آمدنی کے مختلف ذرائع اسی طرح تلاش کرنے پڑیں گے اگر ایسا ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ آٹھ تو کیا ایک منسٹر کی تنخواہ نکالنا بھی مشکل ہو جائیگا۔ اس آمدنی پر زیادہ آدھاڑ کرنا ہمارے لئے مناسب نہیں ہے۔ بلکہ ہمیں دوسرے ذرائع تلاش کرنے چاہئیں۔ ہم جاہلوں کی جیب سے کچھ لیکر فخر محسوس کر رہے ہیں۔ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہوگا جب تکھی ہم ٹکس لگاتے ہیں یا کوئی آمدنی کا ذریعہ تلاش کرتے ہیں تو اوس کو کلکٹ (Collect) کرنے کے لئے اتنے لوگوں کو لگاتے ہیں اور اس میں اتنی شان و شوکت کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے کافی روپیہ اس کے وصول میں خرچ ہو جاتا ہے۔ آپکاری کی آمدنی کا پہلے تو گورنمنٹ کے کارڈسے نقصان کر رہے ہیں۔ رشوت خواری کے وجہ سے جو آمدنی اس کی ہونی چاہئے نہیں ہو رہی ہے۔

یہ بات صحیح نہیں ہے کہ جھاڑوں کی کمی کی وجہ سے یا تراشنے والوں کی وجہ سے آمدنی میں کمی واقع ہوتی ہے بلکہ گورنمنٹ کی عدم توجہ اور عہدیداروں کی غفلت کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ جھاڑ تو زیادہ ترانے جارہے ہیں لیکن اس کا فائدہ گورنمنٹ کو نہیں ہو رہا ہے۔ گورنمنٹ ان لوگوں پر تکیہ کئے بیٹھی ہے جن پر اسٹیٹ اور سرکس کی طرف سے نگرانی کا دعویٰ کیا جاتا ہے۔ منسٹر صاحب ایک رات کے لئے دورے پر جاتے ہیں اور دوسرے دن ان کا واپس آنا ضروری ہوتا ہے۔ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں نگرانی کرتا ہوں۔ اگر آج ہمارے ڈسٹرکٹ بورڈس (District Boards) کا کنٹرول ہو تو میں یقین دلاتا ہوں کہ یہ بات بڑی حد تک دور ہو سکتی ہے لیکن افسوس کہ یہاں یہ سسٹم بھی نہیں ہے۔

ٹیکسس کے بارے میں مجھے کچھ کہنا ہے۔ میں پوچھتا ہوں ٹیکسس کن سے لینا چاہیے یہ درست ہے کہ گورنمنٹ ٹیکسس کے بغیر اپنے لائحہ عمل کو عمل میں نہیں لاسکتی۔ ٹیکسس ضروری ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹیکسس کن سے لے جائیں۔ ایک معمولی اکنامکس (Economics) کے پرنسپلس (Principles) بڑھے ہوئے آدمی سے اگر پوچھا جائے تو وہ بھی یہی کہیگا کہ ٹیکسس ان لوگوں پر عائد کئے جائیں جو اس کی ادائیگی کی سکت رکھتے ہیں۔ لیکن ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ ٹیکسس ان لوگوں پر عائد کئے جاتے ہیں جو غریب ہیں جن کا خود اپنا جینا مشکل ہے ان سے ٹیکسس حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آپ مکسڈ اکامی (Mixed economy) کا دعویٰ ایک طرف کرتے ہیں دوسری طرف پرائیویٹ انٹرپرائیز (Private enterprise) اور گورنمنٹ سیکٹر (Government sector) کے درمیان بیانسنڈ اکامی (Balanced economy) کا دعویٰ آج کے ہمارے حالات کے لحاظ سے پروگرامی کو دور کرنے کے لئے کاٹیج انڈسٹریز (Cottage industries) کو فروغ دینا ضروری ہے۔ لیکن دیکھیں کہ عمل کیا ہو رہا ہے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہاری ولیج انڈسٹریز (Village industries) یکے بعد دیگرے ختم ہوتی چلی جارہی ہیں۔ اس کی وجہ محض یہی نہیں ہے کہ انہیں بڑے بڑے انڈسٹریز یا مشینوں کے بنے ہوئے آرٹیکلس (Articles) سے مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے۔ یہی ایک وجہ نہیں ہے۔ اگر یہی ایک وجہ ہوتی تو یہ چھوٹی چھوٹی انڈسٹریز مشینوں کے نکلتے ہی ختم ہو چکی ہوتیں۔ لیکن وہ آج مہرہی ہیں۔ اس کی وجہ کا مپیشن وقت دی مشین پراڈکٹس (Competition with the machine products) ہی نہیں ہے۔ بلکہ ان صنعتوں کے ختم ہونے کی اصل وجہ گورنمنٹ کا وہ رجحان ہے جو ان کے فروغ کی جانب نہیں۔ آج ہمارے دیہاتوں میں ویورس ہیں۔ تیل کے گھانے ہیں۔ ان میں جو ڈپریشن (Depression) آئے تو اس موقع پر لاکھوں لوگوں کی مدد کرنی پڑتی ہے۔ اس کی بجائے ان کے پراڈکٹس پر سبس ٹیکس لگایا جاتا

ہے۔ آج ہمارے ہر دیہات میں کئی تیل کے گھائے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں ان پر سیلس ٹیکس کا سسٹم کیوں ہے۔ کیا وہ کانٹریج انڈسٹری نہیں ہے۔ کیا بمبئی اور مدارس میں ایسی چیزوں پر سیلس ٹیکس ہے؟ نہیں ہے۔ اس بارے میں گورنمنٹ کی کوئی نیتی (پالیسی) ہی نہیں ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتی کہ ان کو کس طرح بچایا جائے۔ کہاں ڈسکریمینیٹ (Discriminate) کیا جائے۔ جیسے ہی سیلس ٹیکس کا قانون بنا ہر دس ہزار سے زیادہ کا بیو پار کرنے والے پر سیلس ٹیکس عائد کر دیا گیا۔ یہ ایک ہی لکڑی آریبل فینانس منسٹر کے ہاتھ میں ہے جس سے وہ سب کو ہانکنا چاہتے ہیں۔ اور یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ کن کو فروغ دینا ہے کن کو بچانا ہے۔ ہم نے بنایا تھا کہ یہ چھوٹے چھوٹے تیل کے گھائے بھی اننا بزنس (Business) کرتے ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں۔ لیکن اب ان پر ایک ایک ہزار دو دو ہزار سیلس ٹیکس عائد کیا جا رہا ہے۔ یہی ہے آپ کی پالیسی کا نامی آج ہمارے پاس ایسی کئی صنعتیں ہیں جنہیں 'کی انڈسٹریز' (Key industries) بنا نا ہے۔ اس سے میرا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں اپنے دیش میں صرف کا ٹیج انڈسٹریز ہی کو رکھ کر بیکورڈ (Backward) بنایا جائے۔ لیکن کا ٹیج انڈسٹریز کے فروغ اور اس کے تحفظ کا سوال آج بہت اہم ہے۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ ان کے سیلس کے لئے کوئی سیلس امپوریم (Sales emporium) نہ بناسکی۔ اس کے لئے آج سیلس آرگنائزیشن (Sales organisation) کی سخت ضرورت ہے۔ ان کا ڈیمانڈ کافی ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بجٹ میں اس کے لئے کوئی براویژن نہیں ہے۔ ساتھ ساتھ چھوٹی چھوٹی صنعتوں کو بچانے کی خاطر انہیں سیلس ٹیکس سے اکزمیشن (Exemption) ملنا ضروری ہے۔ ساتھ ہی سائن کا ٹیج انڈسٹریز کے لئے حکومت کو کچھ ریشنلائیزیشن (Rationalisation) کرنا پڑیگا۔ آج جب اس کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے کہ چپ پارو (Cheap power) اور ہائیڈروالیکٹرک پاور (Hydro-electric power) ضروری ہیں تو بجٹ میں ان کے لئے گنجائش رکھ کر انہیں فروغ دینا چاہیئے اور ہائیڈروالیکٹرک پاور اور چپ پارو اسکیم تیزی کے ساتھ عمل میں لائی جانی چاہیئے اور اس کی سپلائی کا انتظام کیا جانا چاہیئے۔ گورنمنٹ مکسڈ اکانمی (Mixed economy) (Private enterprise) پرائیوٹ انٹرپرائیز (Government enterprise) گورنمنٹ انٹرپرائیز (Government enterprise) کہتی ہے۔ یہ کہتی ہے کہ مکسڈ اکانمی ہماری پالیسی ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ کہاں ہے۔ دو چار دیوالیے کے یا نقصان سے چلنے والی انڈسٹریز کو اپنے ہاتھوں میں لیکر اگر مکسڈ اکانمی کہا جائے تو یہ درست نہیں ہو سکتا۔ جو منافع سے چلنے والے ہیں وہ تو پرائیوٹ ہاتھوں میں دیدئے جاتے ہیں۔ کیا مکسڈ اکانمی کی یہی پالیسی ہے۔ جو کارخانے ملک کی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرتے تھے ان کی پیداوار تو چند لوگوں کی حد تک محدود ہے۔ انہیں پرائیوٹ ہاتھوں میں فروخت کر دیا جاتا ہے۔ ایسی صنعتوں

کو جن کے پیداوار کی سارے جتنا کر ضرورت ہے اور جس پر گورنمنٹ کا کنٹرول ضروری ہے گورنمنٹ ان صنعتوں کو تو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش نہیں کرتی حالانکہ ایسے کارخانے منافعہ میں چل رہے ہیں۔ میں پچھلے تین سال سے برابر اس کی مانگ کرتا چلا آیا ہوں کہ شوگر فیا کٹری کیوں نیشنلائز (Nationalise) نہیں کی جاتی ہے۔ آج مکسڈ اکائی میں چلنے کا دعویٰ تو ہے لیکن ہماری گورنمنٹ میں اتنی بھی صلاحیت نہیں ہے۔ اگر کہا جائے تو کہا جاتا ہے کہ اتنا پیسہ نہیں ہے کہ اس انڈسٹری کو چلا ئیں۔ اس لئے پرائیویٹ ہاتھوں میں دیا جا رہا ہے۔ ان کے مینجنگ ایجنٹس ایسے اسپیشلسٹس (Specialists) ہیں کہ اس کارخانے کو چلا رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ سالانہ ۸-۱۰ لاکھ روپیئے کماتے ہیں۔ اس میں وہ ۱۰-۱۵ ہزار روپیئے لگا کر اتنا منافعہ پاتے ہیں۔ آخر اس کا کیا مطلب ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے گورنمنٹ کا منشا کچھ اور ہے۔ یعنی یہ کہ وہ بھی اس طرح لوٹ کھسوٹ میں برابر کے حصہ دار ہیں۔ اور اسی وجہ سے دانستہ یا نادانستہ طور پر انجان بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک آدمی جو صرف ۱۵-۲۰ ہزار روپیئے لگاتا ہے کروڑوں روپیئے کماتا ہے جس کی نہ تو ٹیکنیکل صلاحیت ہے اور نہ وہ کوالیفائیڈ (Qualified) ہے۔ کس طرح انہیں یہ منافع ملتا ہے۔ پریمر کارپوریشن (Premier Corporation) کو اس طرح اجازت دی جاتی ہے۔ شوگر فیکٹری میں آج اتنا عملہ ہے کیا گورنمنٹ اس کو اپنے ہاتھ میں لیکر اپنے طور پر نہیں چلا سکتی۔ اس میں ٹیکنیکل مینٹس ہیں مینیجرس ہیں۔ اس کو چلانے والے ہیں مزدور ہیں۔ جس طرح ڈمنسٹریشن میں آئی۔ اے۔ یس۔ اور بیچ۔ اے۔ یس ہیں اسی طرح آپ ٹیکنیکل کیڈر۔ کمرشیل کیڈر بناسکتے ہیں اور ان کے ذریعہ چلا سکتے ہیں۔ لیکن نہیں چلاتے۔ اور ان لوگوں کو دانستہ طور پر فائدہ اٹھانے اور لوٹنے کا موقع دیتے ہیں۔ کیونکہ اس لوٹ میں آپ بھی شامل ہونا چاہتے ہیں۔ یہ آج کی گورنمنٹ کی پالیسی ہے۔ آپ کی انٹسٹریز کا یہ حال ہے۔ وہی نظام شاہی یا لائق علی کی پالیسی کہ بس پیسہ لگا دئے اور خانگی لوگوں کے ہاتھ میں دیدئے۔ یہ مکسڈ اکائی یا لیسڈ اکائی کا کوئی اصول نہیں۔ اس میں کوئی پلان نہیں۔ اس میں عوام کی ضروریات پیش نظر نہیں۔ اس کو پورا کرنے کے لئے کوشش نہیں کی جاتی۔ وہی بالکل پرانی شان چلی آرہی ہے۔

آر۔ ٹی۔ ڈی۔ کے بارے میں ہمارے فنانس منسٹر نے کہا کہ آر۔ ٹی۔ ڈی۔ کی آمدنی کم ہونے کی وجہ اسرائیلک ہے۔ غلط ہے۔ میں کہوں گا کہ اس طرح کم ہونے پر اسرائیلک منسٹر نے دانستہ طور پر حقیقت کو چھپایا ہے۔ آر۔ ٹی۔ ڈی۔ کی آمدنی میں کمی کی وجہ صرف اسرائیلک نہیں۔ اور نہ وہاں کے مزدوروں کی اجرتوں میں اضافہ نقصان کی وجہ ہے۔ بلکہ میں کہوں گا کہ نقصان کی اصل وجہ وہاں کے ڈمنسٹریشن کی خرابی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے عوام کا ہمارے سماج کا آج کا ڈپریشن (Depression) ہے۔ عوام کی صلاحیتیں پر چیزنگ پاور اور اسٹانڈرڈ آف لیوننگ کم ہو رہا ہے ان میں صرف کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اس کا تو آپ نے کوئی ذکر نہیں کیا۔ یہ کہتے ہیں کہ عوام کا

معیار زندگی گھٹ رہا ہے۔ عوام کی ہستی کی وجہ سے ٹراولنگ (Travelling) کم ہوا ہے۔ اور بھر جو کچھ بھی ٹراولنگ ہوا ہے اس کا بھی انتظام برابر نہیں ہو سکا۔ اسٹیٹ اکرڈیکٹیو اتھارٹی (State Executive authority) سول ایجنٹ آف اڈمنسٹریشن (Sole agent of administration) بن کر کام نہیں کر سکتی اس لئے ہم نے بار بار کہا ہے کہ ڈی سنٹرلائزیشن (Decentralisation) کرنا پڑیگا۔ میں پوچھتا ہوں آر۔ ٹی۔ ڈی۔ بسس کا ایک ایک کنڈکٹر کتنی رشوت لیتا ہے۔ کیا اس کو معلوم کرنے کی کوشش حکومت نے کبھی برقعہ اوڑھ کر بھیس بدل کر کی ہے۔ آپ کسی ڈسٹرکٹ پر نائٹ اوٹ (Night out) چلے جائیے ٹراول (Travel) کر کے دیکھئے آپ کو معلوم ہوگا کہ آخر کس وجہ سے نقصان ہوتا ہے۔ لیکن آپ اس کو بھی درست کرنے کی ہمت نہیں کرتے اس کو تو تسلیم نہیں کیا جانا لیکن کہا جاتا ہے کہ مزدوروں نے ۲۰ دن ہڑتال کی تھی جس کی وجہ سے آمدنی میں گھٹا آگیا۔ ایک طرف تو ریٹس (Rates) وہی ہیں جو حیدرآباد میں ناکہ بندی کے زمانے میں قائم کئے گئے تھے جبکہ آئیل کی سپلائی مشکل تھی۔ ایک گیلن کے لئے ۶۔۰۰ روپے صرف کرنا پڑا تھا یہ ان دنوں کے قائم کئے ہوئے ریٹس ہیں۔ انہیں اب تک برقرار رکھ کر عوام کو لوٹا جا رہا ہے میں کہوں گا کہ ریٹس کو روائز (Revise) کرنے کی ضرورت ہے۔ میں کہوں گا کہ اگر اڈمنسٹریشن اچھا ہو جائے تو ریٹس کم کرنے کے باوجود بھی آپ کو بہت زیادہ آمدنی ہوگی۔ آپ اس پر تو غور نہیں کرتے۔

[SHRI B. D. DESHMUKH (CHAIRMAN) IN THE CHAIR]

یہ آمدنی کے چند مددات تھے جن کے بارے میں میں نے تو جہ دلائی۔ اب میں خرچ کے مددات کے بارے میں کچھ کہوں گا۔ ہمارے پاس جو ڈیولپمنٹ پلان ہیں۔ نیشن بلڈنگ (Nation-building) کے لئے انہیں تیزی سے فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ یہاں پھر سوال کھڑا ہوتا ہے کہ اس کے لئے پیسہ ہونا چاہیے۔ مجھے کبھی کبھی افسوس ہوتا ہے جب ہماری گورنمنٹ فارن کیپیٹل (Foreign capital) کے بارے میں یہ کہتی ہے کہ اس کے پیچھے سیاسی اسٹریٹجی (Strings) نہیں ہیں۔ اس لئے اس کے فلو (Flow) ہونے کی اجازت دیتی ہے۔ اور یہ کنسیشن دیکھتے ہیں کہ اس کا جو منافع ہوگا وہ لیا جاسکتا ہے۔ لیکن ہماری گورنمنٹ یہ کوشش نہیں کرتی کہ جن کے پاس پیسہ پڑا ہوا ہے اور جنہیں اسٹیٹ بجٹ میں سے آج بھی کروڑوں روپیہ دیا جا رہا ہے ان سے اپیل کی جائے کہ دیش کو اس وقت پیسہ کی ضرورت ہے دیش کی ترقی کے لئے پیسہ کی ضرورت ہے پیرو کاری دور کرنے کے لئے ضرورت ہے ہوگا یہ کہ اس ملک میں وہ پیسہ رہیگا۔ یہیں کے لوگوں کا ہوگا۔ سود کی شکل میں ہو یا منافع کی شکل میں ہم انہی کو دینگے۔ اس سے لوگوں کی خریدنے کی صلاحیت بڑھے گی۔ لیکن یہ نہیں کریں گے بلکہ فارن کیپیٹل (Foreign Capital) کی طرف بھاگینگے۔ یہاں تو فارن کیپیٹل کی ضرورت ہے۔ آئیے دیش خالی پڑا ہوا ہے۔

یہ کہہ رہے تھے کہ جتنا پیسہ آپ لاسکے ہیں لائیں اس کو انوسٹ (Invest) کرنے کے لئے ایسے لوگوں کو رکھیں جو ان کے اپنے ہیں۔ اور پھر سود اور منافع کا پیسہ آپ ہی لئے لیجئے۔ اس کے لئے کیا ہم پر کوئی اسٹرانگ پرشر (Strong pressure) ہے۔ کوئی دباؤ ہے؟

ہمارے پاس جو جاگیردار خاندان ہیں ان سے ربط رکھنے والے کہتے ہیں کہ جاگیرداروں کے پاس کوئی دوسو کروڑ روپیہ کے زیورات کی شکل میں ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ان کے کھانے کے لئے ہی نہیں ہے اس لئے ہم معاوضہ دیتے ہیں نظام صاحب ہیں کیوں نہیں ان کو مجبور کیا جاتا؟ اگر ہمیں فائیدو ایر پلان پورا کرنا ہے تو کیا ان سے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ جو منافع ہم باہر کے ممالک کو دے رہے ہیں وہ ان ہی کو دینگے۔ یہ کیوں نہیں کیا جاتا۔ اگر ہمیں ہمارا فائیدو ایر پلان کمپلیٹ (Complete) کرنا ہے تو یہاں کے پبلک کو آپریشن (Public Co-operation) جیسا کہ شکل میں ہی نہیں بلکہ جو سیونگس کی شکل میں سرمایہ بند پڑا ہوا ہے اس کو ڈھونڈ کر نکالنا پڑیگا۔ اس وقت اور صرف اسی وقت ہمارا فائیدو ایر پلان کا ٹارگٹ پورا ہوگا۔ صرف یہ کہنے سے کہ دیڑھ دولا کہ ایک زمین زیر کاشت لائی جائیگی اور کارخانے کھولے جائیں گے کام نہیں ہو سکتا۔ نئی نئی انڈسٹریز کھولنا تو کجا جو کارخانے تھے وہ آج بند ہو رہے ہیں۔ گورنمنٹ آف انڈیا سے لڑکر جیسا کہ دوسرے پرانت کر رہے ہیں نئے انڈسٹریز قائم کرنیکی صلاحیت نہیں ہے۔ اگر گورنمنٹ آف انڈیا سے دو ایک انڈسٹریز قائم کی جائیں تو ہم بھی گورنمنٹ کا ساتھ دیتے جیسا کہ فنانشیل سبوشن (Financial subvention) کے مسئلہ میں ہم نے آپ کا ساتھ دیا تھا۔ چنانچہ ریلوے سنٹرل گورنمنٹ کے تحت جاتے وقت ۶-۷ کروڑ کا سرمایہ تھا۔ اس وقت ہمارے پاس کے کچھ لائینس ڈالنے کے لئے سروے کیا گیا تھا لیکن انٹرگیشن (Integration) ہو کر ۱۰ سال ہو گئے اور اب تک ایک بھی لائن ڈالنے کی کوشش گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے نہیں کی گئی تو اس خاموشی کے کیا معنی ہیں۔ کیا ہمیں اپنی آمدنی بڑھانا نہیں ہے۔ کیا یہاں کے لوگوں کو روزگاری پروائیڈ (Provide) کرنا نہیں ہے۔ کیا ہمارے پاس جو ڈولپمنٹ پلاننس (Development plans) ہیں ان کو پورا کرنے کا مقصد نہیں ہے۔ ہر بات کے لئے یہ ہمارے سامنے کہا جاتا ہے کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے۔ پیسہ نہیں ہے۔ بس یہ ہی رٹ لگائی جاتی ہے۔ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے۔ تو گورنمنٹ کی بددیانتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو یہ نہیں کہنا چاہئے۔ جب بھی ولیج پنچایت کا مطالبہ کیا گیا تو یہ کہا جاتا ہے کہ لوگوں میں ابھی صلاحیت نہیں ہے۔ ان کو اتنے زیادہ حقوق اور اختیار دینا بالکل بے معنی سی بات ہے پھر ہم جب کہتے تھے کہ وہ لوگ نادانی اور جہالت سے آپ لوگوں کو ووٹ دے تھے۔ آپ کو یعنی کانگریس کو ووٹ دے تھے تو اس وقت بھی یہی کہنا تھا کہ ہمارے عوام ان پڑھ ہیں جاہل ہیں اس وجہ سے آپ بیل اور ناگر رکھ کر الکشن جیتے ہیں۔ آج واقعی جتنا ہی یہ حالت ہے کہ وہ محض ایک عقیدہ ہونے کی وجہ سے "بیل"

کو ووٹ دے ہیں اگر آپ یہ نہیں مانتے تو ایک بار کوشش تو کیجئے کہ بائی الکشن میں اس علامت کو نکالیں۔ اس سے آپ پر کیا اثر پڑنے والا ہے اور کیا فرق ہونے والا ہے وہ آپ کو معلوم ہو جائیگا۔ اس لئے اب یہ کہنا کہ کوآپریشن نہیں ملتا مناسب نہیں ہے۔ یہ دونوں باتیں ایک ساتھ کیسے ہو سکتی ہیں۔ اگر ہمیں ملک کو ترقی دینا ہے تو ہمارے جو ڈولمنٹ پلانیں ہیں یا ترقی کی اسکیمیں ہیں ان پر زیادہ توجہ دینا ضروری ہے۔

آخر میں میں صرف ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں اور اسے دیکھ کر مجھے بڑا تعجب ہوا۔ آج تقریباً ۳۰-۳۵ فیصد پست طبقات ہیں جنکو ہم ہریجن یا کسی اور نام سے پکارتے ہیں۔ انکی بھلائی۔ سماجی اور معاشی بھلائی کے لئے صرف ۲۰ لاکھ روپیے رکھے گئے ہیں۔ یہ ۴۰-۵۰ لاکھ لوگوں کے لئے رکھے گئے ہیں نو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہماری نیکی (نیکی) پوری نہیں ہوتی۔ ہم سماج سے نیچے اور ان ٹیچ ایبلٹی (Untouchability) کو دور کرنا چاہتے ہیں۔ انکو بہتر پوزیشن دینا چاہتے ہیں تو اس مد میں ہمیں اور کچھ اضافہ کرنا پڑیگا۔ اس طرف ہمیں تیزی سے قدم اٹھانے کی ضرورت ہے اسلئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ رقم ناکافی ہے اور اس میں اضافہ ضروری ہے۔

اسکے ساتھ ساتھ مجھے یہ کہنا ہے کہ جو دو ڈپارٹمنٹس قوم کے معیار سمجھے جاتے ہیں۔ سنٹر میں بھی اور یہاں بھی۔ وہ تعلیمات اور قوم کی صحت برقرار رکھنے والا مڈیکل ڈپارٹمنٹ ہے۔ لیکن پچھلے سالوں میں اور آج بھی ان میں کوئی غیر معمولی اضافہ نہیں پاتا ہم نے یہ قانون پاس کیا تھا کہ حیدرآباد میں کمپلٹری ایجوکیشن ہو۔ یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ تین چار سال میں ہم اسکو نافذ کریں گے لیکن رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ دیر ۲ سال میں ۲ کمپلٹری ایجوکیشن سنٹرس قائم کر سکے ہیں۔ اگر یہی رفتار ہو تو میں کہتا ہوں کہ اسکو نافذ کر کے سارے لوگوں کو لٹریٹ (Literate) بنانے کے لئے کتنے سال درکار ہوں گے اور کتنی صدیاں گزریں گی ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔

مڈیکل ڈپارٹمنٹ کے سلسلہ میں پچھلے سالوں کا تجربہ ہونے کے باوجود بھی ہمارے حیدرآباد میں کچھ ایسی حالت ہے کہ جنکی پناہ پر کئی ایک امراض پھوٹ پڑتے ہیں۔ ہماری ریاست کے لوگوں کو اس سے بچانا ضروری ہے تو امراض کا حملہ ہونے کے بعد انکو بچانے کی کوشش کریں اور یہ بتلانے کی کوشش کی جائے کہ ہم نے یہ کیا اور وہ کیا۔ اتنا پیسہ صرف کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک بات نہ ہوگی۔ اس کے لئے تو ہمیں پہلے سے زیادہ سے زیادہ پریونٹیو میژرس (Preventive measures) لینا پڑیگا۔ اسکے علاوہ حیدرآباد میں انٹیریورس (Interiors) میں مہلک امراض کے دواخانے ایسی جگہ کھولے گئے ہیں جہاں نہ بس سویس ہے اور نہ اچھے پکے روٹن ہیں۔ اسی طرح ایوویڈک دوا خانے کھولنے کے لئے کوئی خاص انتظام نہیں ہے تو یہ کام کس طرح چل سکتا ہے۔

آخر میں میں ایک اور چیز کی طرف حکومت کو توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ مجھے افسوس ہے کہ گورنمنٹ اور خاص کر چیف منسٹر صاحب نے یہ کہا تھا کہ پچھلی گورنمنٹ نے یہ تصفیہ کر لیا تھا کہ پٹیل پٹواریوں کے سسٹم کو ختم کیا جائیگا۔ انکی جگہ گروپنگ کی جائیگی اور اسٹیپنڈری پٹواریز (Stipendiary patwaries) رکھے جائیں گے۔ لیکن ایسا یقین دلانے کے باوجود بھی آج کے بجٹ میں اس کے لئے کوئی پروویژن نہیں ہے۔

میں ایک بار بھر گورنمنٹ سے یہ کہہ چکا تھا کہ دھندلکے میں بھٹکے بھٹکے اپنے سامنے کوئی واضح پلان نہ رکھتے ہوئے آگے بڑھنے اور ترقی کرنے کی کوشش کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے دیش اور قوم کی ترقی کے لئے کوئی صحیح راستہ نہیں ہو سکتا۔ ہمیں سوچ سمجھ کر اور ایک واضح پلان بنا کر.. کیا ضروریات ہیں انکو اچھی طرح جاننے کے بعد انکو میٹ (Meet) کرنے کے لئے کیا ذرائع ہو سکتے ہیں۔ موجودہ حالات میں ہماری آمدنی بڑھانے کے لئے اور خرچہ کم کرنے کے لئے کیا طریقے ہو سکتے ہیں ان پر غور کرنا چاہئے۔ مجھے امید ہے کہ گورنمنٹ اس پر کافی دھیان دیگی۔

شری کے۔ وینکٹ رام راؤ۔ (چنا کونڈور) اسپیکر سر۔ جو بجٹ ہمارے سامنے پیش ہوا ہے وہ تیسرا بجٹ ہے۔

مسٹر چیئرمین۔ وقت کا خیال رکھا جائے۔۔۔

شری کے۔ وینکٹ رام راؤ۔ بجٹ کا یہ مفہوم لیا جاتا ہے اور اسکا یہ تصور ہوتا ہے کہ بجٹ ایک پلان ہے مندرجہ ذیل۔ عوام اپنے جیب سے اپنی کٹائی سے بچا کر زبردستی ہی سہی یا والنٹیری طور پر جو پیسہ دیتے ہیں وہ ایک ٹرسٹ کے طور پر دیتے ہیں۔ اب اس میں سے کس طرح اکسپنڈیچر ہو۔ اسکر کس طرح خرچ کیا جائے۔ آیا اسکر عوام کی فلاح و بہبود کے لئے خرچ کیا جائے یا من مانے طور پر حکومت خرچ کرے ان تمام پرنسپلس (Principles) اور اصولوں کا ایک مجموعہ ہوا کرتا ہے۔ گوکہ بجٹ مین ہند سے رہتے ہیں لیکن ان ہندسوں کے پیچھے حکمت کی پالیسیز اور پلانز مضمر رہتے ہیں۔ آئندہ کیا پلانز کرنے والے ہیں اس کا اظہار ہوتا ہے۔ اس نقطہ نظر سے ہم اس بجٹ پر غور کریں تو یہ معلوم ہوگا کہ پہلے ہمارے سامنے سنہ ۱۹۴۹ء سے لیکر آج تک کے بجٹس کی ایک تصویر ہمارے سامنے آتی ہے۔ جیب سے یہ اسمبلی بنی ہے اس وقت سے لیکر آج تین سال تک ڈیفیسیٹ بجٹس (Deficit budgets) گھائے کے بجٹس ہمارے ہاتھ میں دئے جاتے ہیں۔ پولیس ایکشن سے پہلے جو بجٹ ہوا کرتے تھے اس میں ریونیو اکاؤنٹ سے بچا کر کیونکہ ہمیشہ سربلس بجٹ ہوا کرتے تھے اور وہ کیپٹل اکسپنڈیچر کے لئے استعمال کیا کرتے تھے۔ لیکن پولیس ایکشن کے بعد سے ایک پرمینٹ فیچر (Permanent feature) کے طور پر ڈیفیسیٹ بجٹس ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ فنانس منسٹر صاحب نے خود

اپنی اسپینج میں اسکا اقبال کیا ہے۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سے کیا اثرات مترتب ہونے والے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ اس ڈیفیسٹ فینانسنگ کے بارے میں مختلف آرا ہیں۔ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ڈیفیسٹ فینانسنگ ہوسکتی ہے کیونکہ آج کے حالات کا جو تقاضہ ہے اسکو پورا کیا جائے۔ لیکن دوسرے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہم خسارے کی پالیسی اڈاپٹ (Adopt) نہیں کرسکتے۔ آج حیدرآباد ہی میں نہیں بلکہ ہندوستان بھر میں یہ رویہ ہے۔ بہ استثنائے بمبئی جہاں چند لاکھ کا سرپلس بجٹ بنا ہے۔ کہ بجٹ میں خسارہ ہے۔ سنٹر میں تو ۲۰۰ کروڑ روپیہ کی کمی ہے۔ معاشی زندگی میں افراط زر انفلیشن (Inflation) کے جو اثرات ہیں اسکی نسبت ریزرو بینک آف انڈیا کے جو اعداد ہمارے سامنے ہیں وہ یہ ہیں کہ ڈسمبر سنہ ۱۹۵۳ء تک جو کرنسی نوٹس جاری کئے گئے اس میں ۳۸ کروڑ کا گھاٹا ہوا اور ۱۵۔ جنوری سنہ ۱۹۵۴ء میں مزید ۳۸ کروڑ کا اضافہ کیا گیا ہے۔

اس طریقہ سے اگر ہم افراط زر کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ ۱۸۔ ڈسمبر سنہ ۵۳ء تک (۱۱۳۰,۲۱) روپیہ کے نوٹس کی شکل میں جاری کئے گئے۔ اگر ۱۵۔ جنوری سنہ ۵۴ء کے اعداد دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ (۱۱۵۸,۴۴) کروڑ روپے کے نوٹس جاری کئے گئے ہیں۔ فینانس منسٹر صاحب نے گو بجٹ اسپینج میں فرمایا ہے کہ ہمارے فینانس ساؤنڈ (Sound) ہیں لیکن یہ محض ادھر اودھر کے الفاظ ہیں۔ مسلمہ طور پر تو یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ ہم افراط زر کے حالات سے دو چار ہیں۔ ایسی صورت میں ہماری معاشی پالیسی کیا رہنی چاہیئے۔ عموماً ماہرین معاشیات کی یہ رائے اور اصول رہا ہے کہ جہاں کہیں افراط زر کے حالات ہوں سرپلس بجٹ بنانا چاہیئے ڈیفیسٹ بجٹ نہیں بنا یا جاسکتا میں ادھر اودھر کا کوٹیشن دینے کی بجائے گوروالا کمیٹی کا انٹرا ڈکٹری چیپٹر (Introductory Chapter) فینانشیل سچویشن (Financial situation) کے سلسلہ میں ہے اسکو میں ایوان کے ملاحظہ میں لانا چاہتا ہوں۔ اس سے واضح ہوگا کہ جہاں کہیں افراط زر کے حالات ہوتے ہیں سرپلس بجٹ بنانا چاہیئے۔ لیکن یہاں تو گنگا لٹی ہے سنہ ۵۲۔۵۳ء کا بجٹ اکسیڈنٹلی (Accidentally) سرپلس بجٹ رہا۔ اوس میں ریلوے کے کچھ ایک کروڑ روپیہ ہمارے اکاؤنٹ (Account) میں آگئے تھے۔ اور اسی لئے وہ خسارہ کا بجٹ نہ بن سکا۔ لیکن سنہ ۵۳۔۵۴ء اور آئندہ بننے والے بجٹ کو دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ اوس میں (۲,۴۷) کا گھاٹا ہو رہا ہے۔ آج ہندوستان کی ہر ریاست کا بجٹ گھٹائے کا بجٹ ہے۔ اور خود سنٹر کا بجٹ گھٹائے کا ہے۔ ان گھٹائے کے بجٹس کو کس طرح میٹ آؤٹ (Meet out) کیا جائیگا۔ گو حیدرآباد کی حکومت کے ہاتھ میں کچھ نہیں قسط ہاتھ کی لکیریں ہیں میں اس کے اعداد بھی بعد میں دوں گا۔ سنٹرل گورنمنٹ کے پاس منٹ ہے وہاں سے نوٹ بنتے جاتے ہیں۔ کب تک اس طرح کی منی منٹنگ (Money minting) جاری رہیگی؟ یہ ایک صاف اصول ہے کہ اس طرح جب زیادہ روپیہ بازار میں آجاتا ہے

تو اشیاء کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ اور اشیاء کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں تو سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کی تہیوری اپلائی ہو جاتی ہے۔ اس طرح

حکومت ڈیفیسٹ فنانشیل پالیسی (Deficit financial policy) اور انفلیشنری پالیسی (Inflationary policy) کو اڈاپٹ کر کے عوام کی زندگی پر حملہ کر رہی ہے

کیونکہ ڈیفیسٹ فنانشیل پالیسی کے برے اثرات ہونے والے ہیں۔ میں یہ چیز بھی ایوان کے سامنے لاؤں گا کہ آئندہ کیا ڈیفیسٹ بجٹ بنانا ضروری ہے یا اس کو اس طرح اڈجسٹ (Adjust) کیا جاسکتا ہے کہ وہ سرپلس بجٹ بن سکے۔

ہمارے جو سورسز آف انکم ہیں وہ ٹیپ کئے گئے ہیں یا نہیں۔ ہماری آمدنی کے جو ذرائع ہیں کیا وہ برابر استفادہ میں آ رہے ہیں یا نہیں۔ ڈیفیسٹ فنانشیل پالیسی کے سلسلہ میں یہ ڈفنس (Defence) کیا جاتا ہے کہ ہم تو ڈولپمنٹ پر زیادہ خرچ کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے ڈیفیسٹ بجٹ بنا نا ضروری ہے۔ یہ ایک بے اصولی چیز ہے۔

جہاں کہیں کنٹریل اکسپنڈیچر پر خرچ کرنا ضروری ہے وہاں ریونیوز سے بچا کر اس طرح کے پلان بنا نا چاہیئے۔ اس اصول کو ہماری حکومت نے ترک کیا ہے۔ اس کے جو نتائج

ہوں گے وہ میں عرض کر چکا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی عرض کرنا کہ ڈیفیسٹ فنانشیل پالیسی جہاں کہیں بھی اختیار کی جاتی ہے وہ عموماً جنگ کے حالات میں اڈاپٹ

کی جاتی ہے۔ لیکن یہاں ڈولپمنٹ کے نام اکسپنڈیچر (Expenditure) کئے گئے ہیں۔ چنانچہ میں اس کو ایوان کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ اگر ہم اس کا مقابلہ کریں

تو معلوم ہوگا ہم آئندہ سال کے لئے (۲۹) کروڑ کا اسٹیمٹ (Estimate) پیش کر رہے ہیں۔ اس میں سے ۱۸ کروڑ سے زائد محض اڈمنسٹریشن پر خرچ ہو رہا ہے۔

میرے ہاتھ میں فنانس سکریٹری کا میمورنڈم ہے۔ اس کو دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ (۵۹) پرسنٹ اڈمنسٹریشن پر خرچ ہو رہا ہے اور (۴۱) پرسنٹ نیشن بلڈنگ یرپزس کے

لئے خرچ ہو رہے ہیں۔ میں یہ مانتا ہوں کہ تھوڑا بہت ضرور صرف کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میڈیکل اور ایجوکیشن پر صرف ہو رہا ہے لیکن جو خرچ ہو رہا ہے

اس کو جائز طور پر ایک پلان کے تحت اچھی طریقہ سے خرچ کیا جا رہا ہے یا نہیں یہ دوسری بات ہے۔ اس سے بھی زیادہ خرچ کرنے کا امکان اور گنجائش ہے یا نہیں

اس کا بھی سوال ہو سکتا ہے۔ ہمارے نیشن بلڈنگ ڈیپارٹمنٹ (Nation-building Department) کے جو اکسپنڈیچرس ہیں اس کو فی کس تقسیم کریں یعنی

ایک کروڑ (۸۰) لاکھ کی آبادی پر ہم تقسیم کریں تو فی کس دو روپیہ پڑے ہیں۔ اس میں پرائمری ایجوکیشن۔ سکندری ایجوکیشن اور یونیورسٹی ایجوکیشن بھی شامل ہے۔ اس طرح

میڈیکل اور پبلک ہیلتھ پر فی کس ایک روپیہ خرچ ہو رہا ہے۔ کیا یہ کافی ہو سکتے ہیں۔ یہ تو بہت کم خرچ کئے جا رہے ہیں۔ اگر ہر شخص پر اس کو تقسیم کر کے دیکھا جائے

تو معلوم ہوگا کہ ہم جو کچھ خرچ کر رہے ہیں وہ ہمارے لئے کوئی فخر کی بات نہیں۔ اس کے لئے ہم اپنے مونچھوں پر تاؤ نہیں دے سکتے۔

اسی طرح اگریکلچر اور اریگیشن (Irrigation) پر جو خرچ ہو رہا ہے وہ بھی بہت کم ہے۔ ہمارے پاس ایک کروڑ ۷۷ لاکھ کسان ہیں اون پر اگر آپ کی رقم تقسیم کی جائے تو فی کسان ایک ایک روپیہ بڑتا ہے اس میں آپ کا پیڈی مکسچر ”پیٹر“ اور ”کرلوسکر“ وغیرہ کے آئیل انجنوں کا خرچہ بھی شامل ہے۔ اس کسان کے لئے آپ ایک روپیہ خرچ کر رہے ہیں جو لینڈ ریوینیو اور آبکاری کے سلسلہ میں آپ کو سات روپیہ دیتا ہے۔

ڈاکٹر چناریڈی - اگریکلچر ڈپارٹمنٹ سے متعلق پیڈی مکسچر اور تقاوی وغیرہ کے فیکرس جو آپ بیان کر رہے ہیں وہ کہاں سے لئے گئے ہیں۔
شری کے - وینکٹ رام راؤ - یہ فینانس سکریٹری کے میمورنڈم میں ہیں۔ میں اگریکلچر اور اریگیشن دونوں کے فیکرس کو ملا کر کہہ رہا ہوں۔ میمورنڈم میں اس سے متعلق ایک چارٹ دیا گیا ہے۔

ڈاکٹر چناریڈی - آپ اس کو اچھی طرح پڑھ لیں۔ اس میں تقاوی وغیرہ شامل نہیں ہے۔
شری کے - وینکٹ رام راؤ - اگریکلچر کے مد کے تحت (۷۵) لاکھ (۴۲) ہزار ہیں اور اریگیشن پر جو خرچ ہو رہا ہے وہ ایک کروڑ چھ لاکھ چھیا نوے ہزار ہیں۔ ان دونوں کو میں نے جمع کیا۔

ڈاکٹر چناریڈی - میں معافی چاہتا ہوں۔ اس میں تقاوی - فرٹلائزریڈی مکسچر اور پیٹر اور کرلوسکر (جیسا کہ آپ نے کہا) کے آئیل انجنس کی رقم شریک نہیں ہے۔

شری کے - وینکٹ رام راؤ - مجھے اس پر خاص طور پر انسٹ کرنا نہیں ہے لینڈ ریوینیو اور آبکاری کے نام پر جو کسان آپ کو سات روپیہ دیتا ہے اس میں صرف چار روپیہ آپ کے لئے خرچ کریں تو بھی اس کی ضروریات کے لئے کم ہیں۔ اس طرح اگر حالات کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ نیشن بلڈنگ ڈپارٹمنٹ جو خرچ کر رہا ہے وہ بہت کم اور ناقابل لحاظ ہے۔ ایک اور چیز بھی مجھے عرض کرنا ہے۔ اس وقت ساڑھے چھ کروڑ ایکڑ زمین ایسی موجود ہے جس کو دوسرے ذرائع سے سیراب کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے یہ اسٹیٹسٹکس (Statistics) فینانس ڈپارٹمنٹ کے ”اکنامک افریلیٹن“ سے لئے ہیں کہیں اور سے کلکٹ نہیں کئے ہیں۔ اس سے معلوم ہوگا کہ نان پراڈکٹیو (Non-productive) پر ایکسپنڈیچر زیادہ کیا جا رہا ہے۔ میں نے راج پرمکھ کے آڈریس (Address) کے وقت اس سلسلہ میں کہا تھا کہ دو میل پر ایک پولیس کا جوان رکھا گیا ہے۔ ہر موضع میں ایک سیندھی اور شراب کی دوکان رکھی جاسکتی ہے۔ لیکن ہر موضع میں ایک مدرس کیوں نہیں رکھا جاسکتا۔ ایجوکیشن منسٹر صاحب نلگنڈہ کی تقریر میں فرمایا کہ ہردو گاؤں کے لئے ایک مدرس کا تقرر کیا گیا ہے۔ ان اعداد کو ویریفائی (Verify) کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ایسا ہو رہا ہے تو خوشی کی

ہاتھ - ایجوکیشن کے سلسلہ میں بجٹ اسپینج میں اور راج پرمکھ کے اڈریس میں بیسک ایجوکیشن کو اڈاپٹ کرنے کا بھی ذکر کیا گیا ہے لیکن اس پر ایجوکیشن کے اکسپرٹس (Experts) کی کیا رائے ہے غور کرنے کی ضرورت ہے محض فیائیکلی (Fanatically) بیسک ایجوکیشن (Basic education) کو انٹراڈیوس (Introduce) نہیں کیا جاسکتا۔ یہ ایک کنٹروورشیل (Controversial) مسئلہ ہے بیسک ایجوکیشن کو انٹراڈیوس کرنے کے سلسلہ میں بہت سی رائے ہیں۔ ہندوستان کے اکسپرٹس اس کے خلاف ہیں۔ لیکن چونکہ کانگریسی حکومت پر سراقدار ہے فینیٹسزم (Fanaticism) کے طور پر اس کو انٹراڈیوس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ چیز قابل برداشت نہیں ہے عوام اس کی مخالفت کریں گے۔ بیسک ایجوکیشن کیا چیز ہے۔ اس کے سلسلہ میں سی۔ آر۔ ریڈی نے کہا ہے۔ بیسک ایجوکیشن واردہ اسکیم کے تحت ہوگی۔ جسے راجہ جی اسکیم یا موڈیفائیڈ الیمینٹری ایجوکیشن اسکیم (Modified elementary education scheme) کا نام دیا گیا ہے۔ اس بیسک ایجوکیشن کے اصول یہ ہیں کہ ہر طالب علم صبح کے دو تین گھنٹے تعلیم حاصل کرے اور پھر اوس کے بعد اپنے ماتا پتا کو کاروبار میں مدد دے۔ اگر کوئی ہریجن چپل سیتا ہے تو وہ چپل سیا کرے۔ کوئی دھوبی ہے تو دھوبی کا کام کرے کوئی بڑھئی ہے تو وہ بڑھئی کا کام کرے۔ اسی طرح حجام لوہار وغیرہ اپنے اپنے کام کریں۔ بیسک ایجوکیشن کے یہ پرنسپلس ہیں۔ حیدرآباد کی حکومت کے بیسک ایجوکیشن کے پرنسپلس کیا ہیں وہ میرے سامنے نہیں ہیں۔ لیکن بیسک ایجوکیشن کے معنی پورے ہندوستان میں یہی لئے جا رہے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیسک ایجوکیشن کا اسٹانڈرڈ دن بہ دن گرتا جا رہا ہے۔ یہ شکایت اوس طرف اور اس طرف دونوں طرف سے بھی ہے۔ صبح سے شام تک رگڑ رگڑ کر کام لیا جاتا ہے لیکن تعلیم کا اسٹینڈرڈ تو دن بہ دن گرتا جا رہا ہے۔ صبح میں اگر کوئی پڑھا کرے اور دن بھر چپل سیتا رہے تو وہ کیا تعلیم حاصل کرے گا۔ ہمارا جو معاشی ڈھانچہ ہے سامراج کے ہندوستان میں آنے سے ایک دھکے کے ساتھ زمین پر آ رہا تھا لیکن اس پرانے ڈھانچے کی جگہ نئے ڈھانچہ نے نہیں لی ہمارے پرانے دن چلے گئے۔ لیکن ان دنوں بھی کیا ہو رہا ہے بیسک ایجوکیشن کے سلسلہ میں اگر صبح کے وقت کوئی ہریجن بڑھے اور دن بھر چپل مٹھے۔ بڑھئی بڑھئی کا کام کرے حجام حجام کا کام کرے تو پھر آپ سیکولر اسٹیٹ (Secular state) کا جو نعرہ لگاتے ہیں وہ بیکار ہو جاتا ہے۔ کاسٹ ازم (Casteism) کو فرقہ واریت کو جڑ سے اکھاڑنے کی ضرورت ہے لیکن اس کو آپ چور دروازے سے انٹراڈیوس کر رہے ہیں۔ بیسک ایجوکیشن کے جو اثرات ہاری معاشی۔ معاشرتی زندگی پر اور سماج پر بہت برے اثرات پڑنے والے ہیں۔ اس سلسلہ میں یہ بحث کی جاسکتی ہے کہ بہت سے لوگ بی۔ اے۔ ہیں۔ ایم۔ اے۔ ہیں ان کو بھی روزگار نہیں ملتا اعلیٰ تعلیم کو صنعتی بنیادوں پر نرمان کرنا ہے لیکن جتنے بھی بنکر اور دستی صنعتوں کے کام کرنے والے لوگ ہیں جتنے بھی مزدور ہیں ان کی حالت کیا ہے۔ ان کی حالت بگڑی ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ

مارکٹ نہیں ہے۔ جو کچھ بھی اسٹاک ہے وہ ڈسپوز آف (Dispose of) نہیں ہوتا۔ اب آپ جو مزید بینکروں - حجاموں اور بڑھائیوں کو پیدا کرنے والے ہیں اس سے دیہی نظام کا ڈھانچہ بننے والا ہے یا بگڑنے والا ہے۔ اس سے کوئی پرابلم (Problem) سالو (Solve) نہیں ہو سکتا۔ اس سلسلہ میں اور بھی چیزیں ہیں جن کو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پر بحث کرتے وقت تفصیل سے کہوں گا۔ لیکن اس وقت یسک ایجوکیشن کے سلسلہ میں جو فینٹک آئیڈیا (Fanatic idea) ہے اس کے متعلق حکومت سے یہ اپیل کروں گا کہ وہ اس پر مکرر غور کرے۔

سرویسز کے سلسلہ میں بھی مجھے ایک چیز کہنا ہے۔ پورے حیدرآباد اسٹیٹ میں جہاں کہیں مختلف پارٹیوں کی جانب سے کوئی شکایت پیش کی جاتی ہے تو پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اون کے سر پر کونسی ٹوپی ہے۔ شکایت کیا ہے۔ وہ غلط ہے یا صحیح یہ نہیں دیکھا جاتا۔ اس قسم کا جو تصور اور ذہنیت پیدا ہو رہی ہے بجا طور پر حکومت کو ہی میں ذمہ دار گردانتا ہوں۔ آئے دن میری کانسی ٹیونس (Constituency) میں ہمارے ضلع میں ہمارے تعلقہ میں اس قسم کی شکایتیں آرہی ہیں۔ مجھے انکے گنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سرویسز (Services) کی یہ حالت ہے۔ ان حالات کا بدلنا ضروری ہے جب پولیس کے بارے میں شکایت کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ تو پی۔ ڈی۔ ایف کی جانب سے شکایت ہے سمجھکر اسکو بیس لس (Baseless) قرار دیا جاتا ہے۔ میں اب دوسرے موضوع پر آؤں گا۔ وہ یہ کہ حکومت کی جانب سے چلائے جانے والے کمرشیل کنسرنس (Commercial concerns) جو ہیں انکے بارے میں سنہ ۱۹۵۲ء سے جو فینانشیل پالیسی ہم دیکھتے آرہے ہیں اور ہمیں جو سابقہ تجربہ ہوا ہے اسکی روشنی میں اس مسئلہ پر غور کرنا چاہئے۔ ہمارا سابقہ تجربہ یہ ہے کہ ہمارے سابقہ اندازے غلط ثابت ہوئے۔ ایک خاص بات ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کی آمدنی کے جو ذرائع ہیں ان میں برابر کمی ہوتی آرہی ہے۔ لینڈ ریوینیو میں کمی ہو رہی ہے اکسائیز میں کمی ہو رہی ہے۔ سیل ٹیکس کے بارے میں ہمارا خیال تھا کہ یہ کسٹم کی جگہ لے گا اوسکی بھی آمدنی گر رہی ہے۔ آبکاری کے بارے میں جواب یہ دینے کی کوشش کی گئی کہ سیندھی اور تاڑی کے جھاڑ چوری سے تراشے جا رہے ہیں اسکی وجہ سے آمدنی میں کمی ہوئی ہے۔ لیکن اصلی وجوہات کو ہم جواب میں مقتود پا رہے ہیں۔ اصل وجہ یہ ہے کہ عوام کی قوت خرید گر گئی ہے۔ اسلئے آمدنی کے مددات گھٹ رہے ہیں۔

اسکے بعد گورنمنٹ پر یس اور اسٹیشنری ڈپو کی طرف توجہ دلاؤں گا۔ اسکی آمدنی ۳۲ لاکھ ۹۸ ہزار ہے اور خرچ ۳۳ لاکھ سات ہزار ہے۔ اس طرح اس میں بھی گھٹا ہے۔ یہی نہیں بلکہ حکومت کے ہاتھ میں جو بھی کنسرنس (Concerns) ہیں اسی طرح گھائے سے چلائے جا رہے ہیں۔ ان کنسرنس کو نفع بخش طریقے پر چلانے کی کوشش کیوں نہیں کی جاتی۔ اسکے ساتھ ساتھ الیکٹرک ڈپارٹمنٹ کو بھی

دیکھیں تو پتہ چلیگا کہ وہ بھی نقصان سے چل رہا ہے بجٹ کے صفحہ ۱۶ پر تین کنسرنس ہیں۔ حیدرآباد سکندرآباد اور کھم۔ کھم میں گزشتہ سال گھاٹا آیا ہے۔ اس سال دو ہزار روپیہ کی آمدنی ہوگی۔ یہ اعداد دئے گئے ہیں۔ لیکن معلوم نہیں کہ یہ اندازہ صحیح ہوگا یا نہیں یا وہ بھی پانی کی لکیر ثابت ہوگا۔ یہی نہیں بلکہ اورنگ آباد رائیچور اور نارائن پیٹھ وغیرہ کے بارے میں غور کریں کہ گزشتہ سال کے مقابلہ میں اس سال نقصان ہو رہا ہے۔ اگر حکومت الیکٹرک سٹی کا کسی کو کنٹراکٹ (Contract) دیدیتی تو میں سمجھتا ہوں کہ دو دو ہزار روپیہ آسکتے تھے۔ اس طرح ان امور پر کیوں توجہ نہیں کی جاتی۔

اوسی طرح آر۔ ٹی۔ ڈی کے بارے میں میں کہوں گا کہ خوش قسمتی سے یہاں کافی روڈس ہیں جہاں ہم آر۔ ٹی۔ ڈی کی بسس چلا سکتے ہیں۔ آر۔ ٹی۔ ڈی کے بجٹ کو سنٹرل گورنمنٹ کے ریلوے بجٹ کا درجہ حاصل ہے۔ ہمارے سامنے سورس موجود ہیں آر۔ ٹی۔ ڈی کے بسس کے جال کو وسیع کیا جاسکتا ہے۔ اس بارے میں فینانس منسٹر صاحب نے اپنی اسپیچ میں کوئی ذکر نہیں کیا۔ اسلئے ہم اس بارے میں مایوس ہیں۔ اسی طرح جتنے کمرشیل کنسرنس ہیں وہ گھانے پر چل رہے ہیں۔ اگر نفع بخش طریقے پر کاروبار کئے جائیں تو دو کروڑ کا جو گھاٹا بجٹ میں آیا ہے وہ نہ آتا۔ اور ہم حالات کا مقابلہ کر سکتے۔

اسکے بعد ایک رنگین تصویر یہ پیش کی گئی ہے کہ اگر ریکلچر کے حالات اچھے ہیں۔ انڈسٹریز کے حالات اچھے ہیں۔ لیکن حالات دراصل اسکے خلاف ہیں۔ اگر ریکلچر کی حالت دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ کسانوں کی آمدنی کا ذریعہ کیش کراپس (Cash crops) ہے۔ مثال کے طور پر کیش سیدس (Castor seeds) کی پیداوار ہورے ہندوستان کی پیداوار کا حیدرآباد کی پیداوار ۱۵ فیصد سے کچھ زیادہ ہے اور میجر اکسپورٹنگ (Major exporting) کی چیز ہے۔ گزشتہ سال ۱۴ روپیہ فی پلہ اسکی قیمت تھی لیکن آج ۴ روپیہ تک اسکا بھاؤ گر گیا ہے۔ وہی حالت ولایتی مونگ کی ہے۔ اسی طرح چاول جوار اور دھان کی قیمتوں کا حال ہے انکی قیمتیں بھی گر رہی ہیں۔ آج کسانوں کا مطالبہ ہے کہ فکسڈ پرائس (Fixed price) کی گیارنٹی حکومت دے۔ آج جو رنگین تصویر دکھائی جا رہی ہے اور جو خواب ہم دیکھ رہے ہیں وہ سچے خواب نہیں نظر آتے۔ انڈسٹریز کے سلسلہ میں جیسا کہ کارپوریشن قائم کیا گیا ہے اسی طرح اگر ریکلچر کے لئے بھی اگر ریکلچرل فینانس کارپوریشن قائم کرنا چاہئے۔ لیکن اگر ریکلچرل فینانس کارپوریشن اب تک قائم نہیں کیا گیا ہے۔ معلوم نہیں کہ اس سلسلہ میں حکومت کیا سوچ رہی ہے۔

پبلک ڈبٹس (Public debts) کے جو قرضہ جات ہیں وہ بڑھتے جارہے ہیں۔ گورنوالا کمیٹی نے ۲۲ کروڑ کے لگ بھگ ان قرضہ جات کی مقدار بتائی تھی لیکن اب وہ ۶۳ کروڑ تک پہنچ گئے ہیں۔ حیدرآباد کمرشیل کارپوریشن کو جو قرضہ دیا گیا

तथा इसका भी حساب کتاب नहीं हुआ है - ठाकाज और हیدराबाद कमिशन कारपोरेशन का नाट्य है - वह खुद भी ठोकेगा और दूसरों को भी लूँगे - वह रकम आने वाली है या डूब जाने वाली है معلوم नहीं - नाम के लिये कृतियाँ बेचकर रकम में कोठी मिलावट नहीं पाता - हम देख रहे हैं कि आमदनी के तमाम मदतगर्त जा रहे हैं -

सन् १९०२-०१ से बराबर भी हाल है ख़सारे बूढ़ता जा रहा है - रज़रु (Reserves) ख़त्म होते जा रहे हैं - अब जो सूरसुरसि बच गये हैं वे लाक़बल अस्तल हैं बस बस लक़री का आरंभ है - इसका ज़वाब ओसुतर्फ़ के आरिबल म्बरस दीन - आम फ़हम आदी भी नहीं कम सकता कि हारी फ़िनांशियल पोज़िशन (Financial position) साउंड (Sound) है - फ़ाईव यीर प्लान (Five Year Plan) - पब्लिक फ़िनांस जो लूज़री बन्जिस के बारे में में आसुतर्फ़ में क्हेनगा कि क्हेनगा - पब्लिक फ़िनांस आप के हात में म्फुपु न्हीं है - हक़ूमत असुके म्फुपु के लिये क्हेनगा कि क्हेनगा - अन्ना क्हेनगा -

श्री. रतनलाल कोटेशा:—अध्यक्ष महोदय, बजेट के जनरल डिस्काशन में अभी तक जिसके पहले तीन वक्ताओं ने अपने विचार हावस के सामने रखे हैं। यू. पी. पी. के नेता श्री जी. राजाराम ने अपने भाषण में कहा कि बजेट फार्म करते वक्त गव्हर्नमेंट के सामने कोजी खास नक़शा नहीं था। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि जिस तरह कैसे बोला जा सकता है। जब यहां पर एक पार्टी की हुकूमत कायम है, उसी तरह तमाम रियासतों में और सेंटर में भी एक ही पार्टी की हुकूमत कायम है। वह पार्टी जब बजेट पेश करती है तब अघांधुंद बजेट कैसे पेश कर सकती है। हमारा एक पंच वर्षिय प्लन है और प्लन को पूरा करने के लिये बजेट बनाया जा रहा है। हमारी संस्था की तरफ़ से भी हमें पूछनेवाले लोग होते हैं। उनकी एक कमिटी है, जिस पार्टी का पार्लमेंट्री बोर्ड भी है। वह सभी बातों पर निशानी रखता है और पार्टी के आदेशानुसार स्टेट की सरकारें काम कर रही हैं या नहीं सब देखा जाता है, और अन्ही की सलाह व मसवरे से सारी चीजों की जाती हैं। मुझे जिस बजेट में कोजी मायूसी नजर नहीं आ रही है। मैं जिसके बारे में बाद विचार रखूंगा।

दूसरे जो वक्ता लिडर ऑफ़ दी अपोजिशन हैं, अन्हीने भी अपना भाषण दिया जिसके पहले बजेट पर उनके तीन भाषण हुये। उन भाषणों को सुनने के बाद मुझे ऐसा मालूम हुवा कि वे तमाम भाषण काफी फायरी (Fiery) थे, लेकिन आज के उनके भाषण में मैं काफी माजिल्ड-नेस (Mildness) पाता हूँ। मालूम नहीं ऐसा क्यों हुवा। क्या यह कोजी स्टेटेजी (Strategy) तो नहीं है? पिछले दो सालों में जैसे लब्ज बिस्तेमाल किये गये कि यह जागिरदाराना बजेट है जमीनदाराना और फ्युडल बजेट है और भी बहुत कुछ कहा जाता रहा था। पहले जो एपिथेट्स (Epithets) दिये जाते थे वह आज के उनके भाषण में कहीं नजर नहीं आते हैं। यह कैसे हुवा क्या यह कोजी स्टेटेजी (Strategy) है कि आज हिंद पर संकट आ रहा है जिस लिये उसको मदद करना चाहते हैं, और चाहते हैं कि जैसे संकट के समय सेंट्रल और स्टेट गव्हर्नमेंट को कोजी तकलीफ़ न हो। जैसी तो कोजी स्टेटेजी (Strategy) जिसमें नहीं है? उनके जिस साल के स्पीच में काफी रियलिज़म (Realism) भी आया है।

निजाम साहब के २५ लाख रुपये का जो कट किया गया उसका क्रेडिट (Credit) वे खुद को लेना चाहते हैं। अन्होंने कहा की हमारी ही वजह से यह २५ लाख रुपये की कमी होगी है, लेकिन जिसका क्रेडिट आप लेना चाहे तो लें, लेकिन यह कोई आपका क्रेडिट नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि काँग्रेस यह एक प्रोग्रेसिव पार्टी (Progressive Party) है, और उसके नेता पंडित नेहरू भी प्रोग्रेसिव हैं। उन ही की वजह से निजाम साहब ने २५ लाख रुपये छोड़े हैं। आपको उसका क्रेडिट नहीं है। यदि आप क्रेडिट लेना चाहते हैं तो भलेही लीजिये।

अब मैं जिस बजेट पर आता हूं। मेरे दोस्तों को जिस बजेट में निराशा मालूम हुई, लेकिन मुझे तो यह बजेट प्रोग्रेसिव (Progressive) ही मालूम होता है। मैं यह नहीं कहना चाहता कि यह बजेट बहुत ही प्रोग्रेसिव है, लेकिन फिर भी बजेट निराशाजनक तो नहीं है जितना मैं कह सकता हूं।

बजेट पर चर्चा करते हुवे मैं दो तीन चीजों को पहले हाथ के सामने रखना चाहता हूं। हमारा यह जो बजेट है वह एक स्टेट बजेट है और कांस्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिहाज से हमारे पास जो आमदनी के रिसोर्सेस (Resources) दिये गये हैं, उससे हमें ज्यादा आमदनी नहीं हो सकती। जो ज्यादा आमदनी के जरिये हैं वे सेंट्रल ने अपने पास रखे हैं। यह बात हमें ख्याल में रखनी चाहिये। अभी एक टैंक्स इनक्वायरी कमिशन बैठा है। उसके सामने हमें जिस चीज को रखना चाहिये कि आजकल डेव्हलपमेंट स्कीमस्पर स्टेट को बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ता है, लेकिन उनके आमदनी के रिसोर्सेस बहुत कम हैं। उनके पास जो मद रखे गये हैं, उनसे आमदनी बहुत कम होती है। जिस लिये स्टेट के पास ज्यादा आमदनी के मद को भी रखा जाना चाहिये।

हमारा देश एक गरीब देश है। और जो देश गरीब होता है उसकी सरकार भी गरीब होती है। सरकार अमीर रहे और देश गरीब रहे ऐसा नहीं हो सकता। सरकार यह तो जनता का या देश का एक पिक्चर है। सरकार यह तो मिरर (Mirror) यानी अना है। जैसी जनता होती है वैसे ही उसकी सरकार भी। जहां जनता गरीब है वहां उसकी सरकार के पास भी ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा। हमारे स्टेट का बजेट ३० करोड़ का है और हमारी जनता दो करोड़ की है, यानी हर आदमी जो जिस स्टेट में रहता है वह सिर्फ १५ रुपये सरकार के खजाने में डालता है। जिससे जाहिर है कि हमारा देश कितना गरीब है। तब हमारा बजेट भी कमी का ही रहेगा। ऐसा होना लाजमी है। जब हम जिसकी पॉवर्टी (Poverty) कम करेंगे तो जिसकी टैंक्स पेयिंग कपासिटी (Tax paying capacity) बढ़ सकती है और हमारे स्टेट बजेट में ज्यादा पैसा आ सकता है। हमारे दोस्त यदि जिस साल के तमाम स्टेटों का बजेट देखें तो अन्हें मालूम होगा कि ज्यादा तर रियासतों का डिफिसियट (Deficit) बजेट है। आंध्र स्टेट के बजेट में साठेतीन चार करोड़ का डिफिसियट है, तो मद्रास के बजेट में ४ करोड़ का डिफिसियट है। डिफिसियट बजेट आता है जिस लिये घबराने की जरूरत नहीं है। आप यदि गये ५ सालों में देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि हमारा कारोबार बढ़ा है। हमारे रेव्यू में तथा खर्चों में ज्यादा बढ़ाई दिखेगी। हम यदि सन ५०-५१ के फिगर्स देखें तो मालूम होगा कि रेव्यू अक्सपेंडिचर २६ करोड़ का और कैपिटल अक्सपेंडिचर ५ करोड़ का है, जिस तरह ३१ करोड़ का खर्चा था। सन ५१-५२ में कैपिटल अक्सपेंडिचर ६ करोड़ और रेव्यू अक्सपेंडिचर २९ करोड़ सन ५२-५३ में ३२ करोड़

५३-५४ में २५ करोड़ ५८-५५ में ३७ करोड़। जिस को देखें तो आपको मालूम होगा कि हमारे स्टेट के खर्चने ५ करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। उसकी वजुहात दो तीन हैं। एक तो यह है कि हमारे यहां मंगल वेल् फेयर स्टेट का ध्येय रहा है। जिस लिये यह खर्चा बढ़ता जायेगा। दूसरे जो पंच माला प्लन है उसको भी इम्प्लिमेंट (Implement) करने की जिम्मेदारी स्टेट पर ही आती है। जिस लिये यह ५ करोड़ रुपये का बढ़ावा हुआ है।

फायनान्स मिनिस्टर साहब ने जिस बजेटका ब्याकग्राउंड (Background) बताते हुए एक अच्छा पिक्चर हमारे सामने लाया है। जिस साल हमारा अग्रिकल्चरल प्रोडक्शन (Agricultural production) बढ़ा है। हम अन एम्प्लायमेंट (Unemployment) को पूरी तरह से चेक तो नहीं कर सकें हैं, लेकिन फिर भी उसे कम करने की हमने पूरी कोशिश की है। प्राइमरी भी अब ठीक हो रहे हैं, और उनका रूझान कम होने की तरफ है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन (Industrial production) में भी वृद्धि हुई है।

यह जो बजेट हमारे सामने आया है उसमें सिर्फ १ करोड़ का डिफिशियट नहीं है। १ करोड़ का ही डिफिशियट है यह कहना सही न होगा। रेविन्यू का १ करोड़ ५ लाख और कैपिटल का एक करोड़ कुछ लाख जिस तरह करीब करीब २ करोड़ ७९ लाख का डिफिशियट है। मैंने तो पहले ही कहा कि हमारा बजेट डिफिशियट है, जिस लिये खर्चाने की जरूरत नहीं है। अब हमारे प्लेनस पूरे होने के लिये दो साल बाकी हैं और उनको पूरा करने के लिये ज्यादा खर्चा आ रहा है जिस लिये घाटा नजर आ रहा है। यह घाटा कैसे मिलायेंगे ? यह घाटे को कम करने के लिये फायनान्स मिनिस्टर साहब सिर्फ दो टैंक्स बिठानेवाले हैं। उनमें से एक मोटर विहिकल्स टैंक्स है और दूसरा शुगरकेन टैंक्स है। मैं कहना चाहता हूं कि गव्हर्नमेंट को और भी टैंक्स के जरिये टैप (Tap) करने की जरूरत है, ताकि ज्यादा पैसा मिल सके। पेट्रोल का जो टैंक्स है उसे बढ़ाने की जरूरत है। बॉम्बे में यह टैंक्स ६ आना है हमारे पास यह टैंक्स कम है। उसमें बढ़ाने की गुंजायश है। जिस टैंक्स को भी टैप करना चाहिये। स्कूल व कालेज फीस भी हमारे यहां दूसरे स्टेट के मुकाबले में कम है। उसे भी हम बढ़ा सकते हैं। प्रेशस स्टोन्स (Precious stones) और सोने चांदी के गहनों पर ज्यादा सेल्स टैंक्स लगाया जा सकता है। हम रेविन्यू और एक्सपेंडिचर को देखें तो मालूम होगा कि हमारा खर्चा अब नेशन बिलडिंग पर ज्यादा हो रहा है। हम यदि जिस बजेट में देखेंगे तो मालूम होगा कि पहले जो ३८.९ परसेंट खर्चा नेशनल डेव्हलपमेंट पर किया जाता था वह आज ४१.३७ तक बढ़ा है, रेविन्यू और कैपिटल अकाउंट में २० करोड़ तक खर्चा बढ़ा है। जैसे इरिगेशन बढ़ा है। अज्युकेशन, पब्लिक हेल्थ, मेडिकल, अग्रिकल्चर, व्हेटरनरी, कोऑपरेशन, इंडस्ट्रीज, सिविल सप्लायज जिस तरह से करीब २० करोड़ रुपये नेशन बिलडिंग पर खर्च किये जा रहे हैं।

कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पर गव्हर्नमेंट फर्र करती है। अज्युकेशन का बजेट देखेंगे तो आपको मालूम होगा, और फायनान्स मिनिस्टर ने भी अपने बजेट स्पीच में कहा है कि ४७-४८ में २९२ लाख खर्चा अज्युकेशन पर किया जाता था, और आज अज्युकेशन पर ५१० लाख रुपया खर्च किया जा रहा है। बजेट का १७.४७% अज्युकेशन पर खर्च किया जा रहा है। पहले पुलिस पर ज्यादा खर्चा किया जाता था लेकिन आज यह खर्चा अज्युकेशन पर ज्यादा हो रहा है। बेसिक अज्युकेशन के बारे में बहुत कुछ कहा गया। मैं अब जिस वक्त अस डिटेल (Detail) में नहीं जात

हूँ लेकिन बेसिक अज्युकेशन यह हमारी अक पॉलिसी है। काँग्रेस गव्हर्नमेंट अउसको मानती है और अउसको देहातों मे चलाना चाहती हैं। देहातों में सही अज्युकेशन का तरीका यही है। खाली दीमागी शिक्षा से काम नही चलता। विद्यार्थियों को हाथ से भी काम करना चाहिये। आप कहते हैं कि आपके कहने के मुताबिक सरकार नही चलती है लेकिन अस बारें में हमारा अक कनविकशन (Conviction) है अउसे आप फॅड (Fad) कहे या कुछ भी कहे लेकिन हम तो बेसिक अज्युकेशन चलानेवाले हैं। हमारे पॉलिसी के लिहाज से गव्हर्नमेंट अपनी अस बेसिक अज्युकेशन की पॉलिसी को नही छोडेगी।

कहा गया कि कंवलसरी अज्युकेशन पर हमारी गव्हर्नमेंट कम खर्च कर रही है। कहा गया कि कंवलसरी अज्युकेशन पूरे स्टेट में नही है। अक भी जिले में स्कूल नही खोले गये और यही कहा गया कि जिले में २० स्कूल खोले गये हैं।

श्री. बि. के. कोरटकर :—यह कहा गया कि पूरे स्टेट में २० स्कूल खोले गये हैं।

श्री. रतनलाल कोटेचा :—अभी मुझे यह कहा गया कि अउस तरफ से यह कहा गया कि सारे स्टेट में २० स्कूल खोले गये हैं, लेकिन मैं यह कह सकता हूँ कि प्रॉजेक्ट अेरियामे ५०, ६० देहातों मे खोले गये हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में २० स्कूल हैं। हमारे स्टेट में प्रायमरि अज्युकेशन मे जो प्रगति की गयी है वह दिगर बी. पार्ट स्टेटोंमे नही की गयी है। गव्हर्नमेंट आज प्रायमरी अज्युकेशन के बारें में जो काम कर रही है वह काफी है, अभीमानास्पद है।

मेडीकल और हेल्थ के बारे में भी गव्हर्नमेंट कुछ खर्च कर रही है। फाइव अिअर प्लान (Five-Year Plan) का प्रोग्रेस भी कुछ निराशाजनक नही है। अउसमें भी कसी चीजें हैं। हरिजन वेलफेअर के बारे में १० लाख रुपये शेड्यूलडकास्ट ट्रस्ट फंड में गव्हर्नमेंट डाल रही है। ६ लाख रुपये हरिजन वेलफेअर स्कीम्स के लिये अस साल खर्च किये गये हैं। मेरे मित्र ने कहा कि हमारे स्टेट में हरिजनों की आबादी ३०-३२ लाख है, अउमें अगर यह रकम बांटी जाय तो हर अक के लिये आठ आने आ जायेंगे। अस तरह से अगर रुपया हम बांटते फिरेंगे तो यह सवाल हल होनेवाला नही है और न अस तरह से कभी हिसाब लगाया जा सकता है। असमें और भी रुपया खर्च किया जाय तो भी पूरे स्टेट के हरिजनों की दिक्कतें अकदम से दूर नही की जा सकतीं। सिर्फ रुपये बांटनेसे या अउको डिवाइड (Divide) करने से यह मसला हल नही होगा। कम्युनिटी प्रोजेक्ट (Community Project) के तहत लोकल डेव्हलपमेंट स्कीम्स में भी गव्हर्नमेंट ने काफी प्रोग्रेस किया है। साथ साथ अस साल में—

مسٹر چیرمن :- آنریبل ممبر ذرا وقت کا خیال رکھیں۔

श्री रतनलाल कोटेचा :—दूसरे वक्ताओं को मैं समझता हूँ कि अक या डेढ घंटे तक का समय दिया गया है। मैं असका स्टडी (Study) करके आया हूँ मुझे ज्यादा वक्त मिलना चाहिये, नही तो मुझे बैठना पडेगा।—

Chairman: Order, order. Five minutes more.

श्री. रतनलाल कोटेचा :—अस बजेट में आप देखेंगे किपुलिस का खर्चा भी बहुत कम हुआ है। पहले १७ या २० परसेंट तक था असको घटाते घटाते अब ११ परसेंट तक लाया गया है। असके लिये

मे होम मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूं, लेकिन मैं उनसे यह भी कहना चाहूंगा कि वे काम्प्लेसंट (Complacent) न रहे क्योंकि अभी कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी पालिसी में बदल नहीं किया है। अभी उनकी जो मदुराजी में कान्फरन्स हुआ उसके रेजोल्यूशन्स को वह देखें। साथ साथ कलकत्ते में जो चीजें हुई हैं उनको भी हमें देखना चाहिये। हमारा धोका अभी पूरी तरह से दूर नहीं हुआ है। जिस लिहाज से हमको ज्यादा सोंचकर चलना चाहिये। कॉंग्रेस गव्हर्न-मेंट को हमारे एक मित्र ने उपदेश दिया है कि आप जिस खर्च को घटाविये। कॉंग्रेस गव्हर्नमेंट को जिस तरह के उपदेश की जरूरत नहीं है क्यों कि हमारे नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू शांतता की पालिसी को चाहनेवाले हैं और पाकिस्तान का जो संकट हमारे सामने है वह होते हुए भी जहां सेंट्रल गव्हर्नमेंट ने अपनी मिलिटरी का खर्चा नहीं बढ़ाया तब हम यहां कैसे बढ़ायेंगे। लेकिन यह खर्चा न बढ़े जिसकी ज्यादा जिम्मेदारी हमारे दोस्तों पर है। हमारे कैश बैलन्सेस (Cash balances) के बारे में हमारे दोस्त ने जो बातें कही उनमें बहुत सी सत्यता है जिसको हमें मानना पड़ेगा जिसके बारे में हमारी गव्हर्नमेंट को संजीदगी से सोचना पड़ेगा कि यह रक्कम दिन प्रति दिन घटती जा रही है। कैश बैलन्सेस एक तरह से हमारी गव्हर्नमेंट मशीनरीका ब्लड (Blood) है। व्यापारी के पास कैश-बैलन्स न हो और दूसरे तरीके से कितना ही ज्यादादा हो उसका कुछ फायदा नहीं। उसी तरीके से हुकूमत के पास कैश-बैलन्सेस काफी मेकदार में न हों तो फायदा नहीं होगा क्योंकि कैश-बैलन्सेस हमारे पास हों तो ही हम कुछ काम कर सकते हैं। जिसमें मैंने एक बात और देखी कि १० करोड़ में से ५ करोड़ रुपये स्टेट बैंक को विधान सभा की बिना अनुमति दिये गये हैं। यह कान्स्टीट्यूशन (Constitution) के खिलाफ बात है। स्टेट बैंक को यह रक्कम बिना व्याज के दी गयी है या व्याज से दी गयी है और कितने व्याज से दी गयी है जिसके बारे में फायनान्स मिनिस्टर को जवाब देना पड़ेगा। इसी तरह से जैसा कि अपोजीशन के लीडर साहबने बताया हमारे रिजर्व्स भी कैसी जगहों पर लगाये गये हैं जो जल्द लिक्विडेट तो नहीं होंगे। जिसका भी हमको ख्याल करना पड़ेगा।

जिसके बाद दो तीन बातों की तरफ मैं हाउस का ध्यान दिलाना चाहता हूं। अगर मैं पांच दस मिनट और लूं तो मुझे आशा है स्पीकर साहब माफ करेंगे। सेल्स टैक्स का एक बड़ा आयटम है। गये साल भी बजट के वक्त मैंने सूचना दी थी लेकिन गव्हर्नमेंट ने उस पर जितना सोंचना चाहिये था उतना नहीं सोंचा। यह एक बड़ा आयटम है जिसके जरिये से हम अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। बंबजी में १८ करोड़ और मद्रास में १६ या १७ करोड़ की आमदनी सेल्स टैक्स से होती है। हमारे यहां सिर्फ दो करोड़ की आमदनी होती है। दूसरे प्रांतों में यह आमदनी बढ़ती है लेकिन हमारे यहां यह नहीं बढ़ती। जिसकी वजह यह है कि कस्टम्स की वजह से हमारी गव्हर्नमेंट जिसकी तरफ ध्यान नहीं देती। आज का सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट का अॅडमिनिस्ट्रेशन जिन लोगों के हाथ में है मुझे माफ किया जाय वे ऐफिशियंट (Efficient) नहीं हैं ऐसा मालूम होता है, क्योंकि बाकी रियासतों में जिसका जिनकम बढ़ता जा रहा है लेकिन हमारे यहां वह नहीं बढ़ता ऐसा क्यों होता है? यह जिनकम हमारे यहां ५-६ करोड़ तक बढ़ना चाहिये। अग्रीकल्चरल जिनकमटैक्स (Agricultural Income Tax) के बारे में हमारे एक दोस्त ने कहा उससे मैं सहमत हूं। जिस साल आर. टी. डी. (R.T.D.) का भी बजट हमारे सामने आया है यह खुशी की बात है, लेकिन जिसमें भी हमें कम अत्युत्पन्न होता है। मुझे मालूम नहीं हो सकता कि

हमारे यहां ही जिसका भी अत्युन्नत कम क्यों है। बंबई में गुडस सर्विसेस का दिन व दिन एक्सटेंशन (Extension) होता जा रहा है और हमारे यहां वह कम होता जा रहा है। पहले जो गुडस सर्विसेस से ९ लाख का अत्युन्नत होता था वह आज ४ लाख तक आ गया है। जिसका मतलब यह है कि आर. टी. डी. का अडमिनिस्ट्रेशन ठीक नहीं है। बीड जिले में मैंने देखा कि वहां का बसेस का अडमिनिस्ट्रेशन बहुत लूज (Loose) है और जिसकी वजह से गव्हर्नमेंट को नुकसान होता है। फूड सबसिडी के तौर पर जिस बस डिपार्टमेंट के मुलाजमीन को ६ लाख रुपये दिये जाते हैं, लेकिन अब कंट्रोल निकाल देने के बाद यह देने की जरूरत नहीं है ऐसा मैं समझता हूं। साथ साथ जिस बस डिपार्टमेंट के बजट में पैसेजरो की सुविधाओं का कोई ख्याल नहीं किया गया है। यह कोई पैसा कमाने का कन्सर्न नहीं है। यह एक तरह से नेशनल कन्सर्न (National concern) है बंबई में चार साल कबल बस डिपार्टमेंट कायम हुआ है और अब तक पैसेजरो को कभी तरह की अमेनिटीज (Amenities) मिली हैं, लेकिन हमारे यहां पुराना ही तरीका चल रहा है। बस में घुसना हो तो अभी भी धक्के खाने पड़ते हैं। जिसलिये मैं होम मिनिस्टर साहब से विनंती करूंगा कि वे जिस पर सोचें। यह एक मामूली सी चीज है लेकिन उस पर भी नहीं सोचा जाता।

जिसके बाद फायनान्स मिनिस्टर के नजर में मैं एक चीज दुख के साथ लाना चाहता हूं। वह यह है कि मराठवाड़े के डेव्हलपमेंट के बारे में जिस बजट में कोई खास प्रोविजन (Provision) नहीं किया गया है। चीफ मिनिस्टर साहब ने हम लोगों को एक नोट दिया था जिसमें बताया गया था कि तीन करोड़ में से दो तिहाई रुपया मराठवाड़े के लिये रिजर्व्ड रखेंगे, लेकिन अब दुःख के साथ कहना पड़ता है कि जिसमें फीगर्स देखें तो एक करोड़ से ज्यादा रकम नहीं रखी गयी है। ८० लाख रुपये इरिगेशन के लिये और २५ या २६ लाख रुपये बंडिंग के लिये रखे गये हैं। यह रकम भी तीन साल के लिये प्रोवाइड (Provide) की गयी है। मैं गव्हर्नमेंट को वार्न (Warn) करना चाहता हूं कि मराठवाड़े के कॉंग्रेस अेम. अेल. अेज. जिसके बारे में काफी बेचैन हैं। यह सवाल सिर्फ मेरा ही नहीं है, यह सवाल कोटेचा का गोपालशास्त्री देव का या मोरे का नहीं है बल्कि यह मराठवाड़े के लाखों लोगों का जो भूखे और नंगे हैं उनका सवाल है। उनके जीवन का यह सवाल है। वहां की हालत खराब हो गयी है। मैंने खुद अपनी कान्स्टीट्यूअन्सी (Constituency) पाटोदा में देखा कि तकरीबन २०-२५ हजार लोग छः छः महीने अपना घरबार छोड़ कर पैसे कमाने के लिये बाहर जाते हैं पैदावार बढ़ाने के कोजी सोर्सेस (Sources) ही वहां नहीं हैं, कोजी अनीकट (Anicut) नहीं हैं, कोजी डैम्स (Dams) नहीं हैं।

श्री. रतनलाल कोटेचा :—पेटभरने के लिये वही मतलब है। मराठवाड़े की तरफ से दो तीन मांगें हैं। वहां इरिगेशन सोर्सेस का अब तक इन्वेस्टीगेशन (Investigation) तक नहीं हुआ है। मैंने अपने दौरे में देखा कि कभी ऐसी जगहों पर मराठवाड़े में हैं जहां अनीकट्स और डैम्स हो सकते हैं लेकिन अभी तक वहां कोई सबे पार्टी तक नहीं आयी है। जिस सिलसिले में मैं पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के मिनिस्टर से भी मिला था। उन्होंने वायदा किया था कि बजट में सर्वे के लिये गुंजायिश रखी जायगी, लेकिन जिस बजट में हम देखते हैं कि वह भी नहीं रखी गयी है।

आयदा दो साल मे अरिगेशन रिमोमेंस का सर्वे नही हुआ तो अगली पंच वार्षिक योजना मे अतिको शामिल नही किया जायगा और आज हम जिस तरह नगे है वैसे ही बाद में भी रहेंगे। मराठवाडे के लिये तीन चीजें करनी चाहिये। पहली यह की पूर्ण प्रोजेक्ट को पंचवार्षिक योजना में शामिल करना पडेगा। मराठवाडे के लिहाज से अरिगेशन रीसोर्सेस (Irrigation resources) का सर्वे किया जाना चाहिये और मायनर अरिगेशन (Minor irrigation) के लिये जो तीन करोड रुपया सेंट्रल गव्हर्नमेंट से आया है और जो ब्रीचड टैंक्स (Breached Tanks) के लिये तकरीबन खर्च किया जाता है उसमें से कुछ हिस्सा मराठवाडे के मायनर अरिगेशन के लिये खर्च किया जाना चाहिये। यह हम काँग्रेस अेम. अेल. अेज. की तरफ से माग है और गव्हर्नमेंट को असके बारे में संजीदगीसे सोचना चाहिये।

अिन बजट को पढने से मुझे अेक और मायूसी हुआ। अस ३२ करोड के बजट में देहातों की मेडीकल अेड (Medical aid) के लिये सिर्फ डेड लाख रुपया रखा गया है, जो आयुर्वेदिक डिस्पेन्सरीज पर खर्च होनेवाला है। यह कोअी ठीक बात नही है। बंबअी प्रांतमें हर पंधरा बीस गावों के लिये अेक आयुर्वेदिक डिस्पेन्सरी होती है। हमारे तालुके में क्या है? पाटोदा तालुके में तो अेक भी डिस्पेन्सरी नही है। बंबअी के हर तालुके में तकरीबन ६-७ आयुर्वेदिक डिस्पेन्सरीज हैं। असके लिये ज्यादा खर्च भी नही लगता। हर तालुके में तीन चार डिस्पेन्सरीज रखी जायें तो ज्यादा खर्च नही होनेवाला है। बंबअी में असका हिसाब देखें तो ८ लाख का खर्च आता है। हमारे देहातों के लोग अल्पसंतुष्ट है। शहरों के लोग अितने अल्पसंतुष्ट नही हैं। असलिये मैं कहूंगा कि हुकूमत को रूरल अेरियाज के लिये टाप प्रयॉरिटी देनी पडेगी और हैदराबाद जैसे शहरों में जो लोग रहते हैं अुनकी तरफ कम ध्यान देकर देहातों की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिये। काँग्रेस देहातियों को ख्याल करने के लिये ही बनी है और अुनकी तरक्की करना ही काँग्रेस का पहला ध्येय है। महात्मा गांधी ने भी हमें यही सिखाया है कि हमें देहातियों की तरफ सब से पहले ध्यान देना चाहिये क्यों कि वे ही भूखे हैं और नगे हैं। मैं आशा करता हूं कि हुकूमत अिन चीजों की तरफ ध्यान देगी।

श्री. नागोराब विश्वनाथराब पाठक (सिल्लोड):—अध्यक्ष महाराज, आज १९५४-५५ सालचे बजेट असेंब्ली समोर आहे. या बाबत बऱ्याच ऑनरेबल सेंबर्सनी निरनिराळ्या प्रकारे टीका प्रतिटीका केली. मला अेवढेंच सांगावयाचे आहे की मागच्या दोन वर्षांच्या बजेट पेक्षा हे बजेट ठीक आहे. कारण या मध्ये शिक्षणा करिता आणि अितर लोकोपयोगी कामा करिता बराचसा खर्च गव्हर्नमेंट करणार आहे.

आतांच अेका माननीय सभासदाने सांगितले की जरी हें बजेट, चांगलें आहे, यांत सरकारने कांहीं कामें चांगलीं केलीं आहेत तरी यांत अेक गोष्ट मात्र निश्चित आहे की मराठवाड्याकडे यांत दुर्लक्ष केलें आहे. रजाकरांच्या काळांत किंवा निजामाच्या काळांत मराठवाड्याची जशी अवहेलना होत असे, त्यांत याही सरकारच्या काळांत कमीपणा नाहीं. मला या सरकारला विचारावयाचें आहे की तुम्ही मराठवाड्याची अशा प्रकारे अवहेलना किती दिवस करणार आहांत आणि मराठवाड्यांतील लोक व त्यांचे प्रतिनिधी किती दिवस चूप बसून राहणार आहेत? ज्यावेळेस आम्हाला लोकांनी निवडून दिले, आपले प्रतिनिधी म्हणून आम्हाला येथें पाठविले, तेव्हां पासून लोकांचे म्हणणे काय आहे, हें सरकारपुढे मांडण्याचा आमचा अधिकार आहे, आणि तें आमचें कर्तव्यहि आहे. अुदा-हरणादाखल मला अेक गोष्ट सांगावयाची आहे. मार्गे मुख्य मंत्र्यांनी अेक स्टेटमेंट दिलें होतें

नाकीं, मराठवाड्यामध्ये मोठमोठ्या धरण योजना होऊ शकत नाहीत, कारण तेथील परिस्थिति तशी नाही, तरीहि आम्हीं तेथे नव्या योजना घेतल्या आहेत. परंतु मला मोठ्या खेदाने म्हणावें लागते कीं औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये पांच योजना असून त्या पैकीं अजून अेकहि सुरू झाली नाहीं.

वर्षा दीड वर्षांपूर्वी श्री. राममूर्ती, आणि माननीय फायनान्स मिनिस्टर यांनी औरंगाबाद आणि बीड जिल्ह्याचा दौरा केला होता, व त्यांनी सांगितलें होतें कीं मराठवाड्यामध्ये मोठ्या योजना जरी निघूं शकल्या नाहीत तरी लहानलहान योजना निघूं शकतात, व या भागाची परिस्थिती सुधळू शकते. तेव्हां कुठे आमचे मंत्री मराठवाड्यामध्ये लहान योजना होऊ शकतात हे कबूल करावयास लागले.

आपण म्हणाल कीं मराठवाड्याच्या लोकांत प्रांतियवाद वाढला आहे. मला त्यांना सांगावयाचे आहे कीं हा प्रांतीयवाद नव्हे. आतां पर्यंत मराठवाड्याकडे सरकारने दुर्लक्ष केलें त्यामुळें आम्हाला असें बोलावें लागते. मराठवाड्यामध्ये लहानलहान योजना सुद्धा केल्या जात नाहीत. मला सरकारला असें सुचवावयाचे आहे कीं आपण जसा ग्रो मोअर फुड (Grow More Food) वगैरे सारख्या अितर चांगल्या गोष्टीवर खर्च करता, तसाच मराठवाड्यांतील लहान लहान योजनांवरही करा. तुम्ही जर मराठवाड्यांतील परिस्थिती पाहिली, आणि तिचे सरकारी रिपोर्टवरून व तज्ञांच्या मतावरून अवलोकन केलें तर, आपणास असें दिसून येतील कीं बहुतेक वर्षी तिथे दुष्काळ पडतो. तेथे पिण्याचें पाणी पूरेसे नाही. म्हणून माझी फायनान्स मिनिस्टरना अशी विनंती आहे कीं कमीतकमी पूर्णा प्राजेक्ट तरी या पंचवार्षिक योजनेमध्ये पूर्ण करा, आणि नंतर ज्या कांहीं लहान लहान योजना आहेत त्यांना सुरवात करा.

आतांच अेका सन्माननीय सभासदाने सांगितले कीं मराठवाड्याची प्रगती झाली पाहिजे, आणि त्या करितां सरकारने सर्व प्रयत्न केले पाहिजेत. त्याखेरीज आम्ही अितर प्रांतांच्या बरोबर येऊ शकणार नाहीत. मला कोणाचे हेवेदावे करावयाचे नाहीत. पण मराठवाड्याची प्रगति व्हावी, हीच आमची जिच्छा आहे. मला आशा आहे कीं फायनान्स, मिनिस्टर मी केलेल्या सूचनांकडे काळजी पूर्वक लक्ष देतील अेवढे बोलून मी आपले भाषण संपवितों.

श्री. गोपिडी गंगारेड्डी :— में तो और दो चार विषयों पर बोलना चाहता हूं । मुझको यदि कल मौका दिया जायेगा तो में कल शुरू में बोलूंगा ।

శ్రీ గోపిడి గంగారెడ్డి : (నిర్భయ-జనంత్)

అధ్యక్ష మహాశయ !

ఇప్పుడు బడ్జెటుమీద చాతా చర్చ జరుగుచున్నది. ఇది రెండు సంవత్సరములు గడిచి మూడు సంవత్సరము ప్రారంభమైనది. ప్రధమ సంవత్సరము మేమునుకొన్నదేమంటే ఈ ప్రభుత్వము యింకా బాత్యాసన్నలో వున్నది, యింకాక సంవత్సరము పోతే తెలివికలిగి వుండవచ్చును అనుకున్నాము. కాని నయస్సు వచ్చినంతనే ముసలితనము కూడా ప్రారంభమవుతుంది.

[Shri Rami Reddi (Chairman) in the Chair]

యంతనరకు మూడు సంవత్సరములలో ఏమిచేయకేం ; యింకా ముందు రెండు సంవత్సరములలో పని

ఏమిచేయగలుగుతుంది అని నాకు అనుమానముగా వున్నది. నాకు ఒక్కనికేకాదు. పెందరాబాదు స్టేటులోని జమలందరికి చాలా విచిత్రకరంగా వున్నది. ఇక్కడ లోకశాయి ప్రభుత్వమేర్పడిన తరువాత ఏ విధముగా బడ్జెటు తయారు చేయబడుతోంది. దానిలో ఖర్చు ఏ విధముగా వున్నది? ఇక్కడమేము చూస్తున్నదేమంటే యింతకు పూర్వమున్న ప్రభుత్వములో ఏ రీతిగా, జరిగినా అదే విధముగా యీ లోకశాయీ ప్రభుత్వములోను జరుగు చున్నది. చిల్లిబడ్డ కుండ, చీకి పోయిన త్రాడుతో నీరుసింపేవని చేసిన ఎన్నటికీ ఆ కుండ నిండదు. ఎటువంటి పుణ్యాత్ములుగాని, ఎంతటి మహాత్ములుగాని ఎవరైనాగాని ఆ కుండను ఎప్పటికీ నింపలేరు. అందుచేత ప్రభుత్వము మారినా, లోపలవున్న గుణము మారనిదే ప్రయోజనములేదు. మేము గాంధీగారి శిష్యులము, శుద్ధ ఖద్దరు ధారులము—అని చెబితే తాధములేదు. కుండచిల్లిపడింది. ఆ చిల్లులన్నింటిని మూసివేయాలి లేదా కొత్తకుండపైనా చేయాలి. అంటేకాని చిల్లిపడ్డ కుండను ఎంతటి ప్రజ్ఞావంతుడైనా నింప లేడు. కాని ఈ ప్రభుత్వనికి చుట్టము మీద ఆశ, బియ్యము మీద ఆశవుంది. జమీందారులు జాగీర్దారులు వుండాలి, డబ్బు కావాలి, బీదలకు సహాయము చేయాలి, ఆ విధంగా చుట్టము మీద ఆశ, బియ్యము మీద ఆశ కూడా వుండాలంటే దానివలనతాధములేదు. ఇక్కడ మూడు పంపత్తరముల నుంచి చూస్తున్నాము. ఈ శాసన సభలో కనీసము అర్థభాగము అంగ్రేజీ రాని వారున్నారు. అటువంటి వాళ్లకు ఈ బడ్జెటు వుస్తకాలు ప్రాంతీయభాషలలోనికి తర్జుమాచేసి యివ్వమని కోరితే యివ్వలేదు. శక్తిలేదు అంటారు. కాని ౧౬ మంత్రిలను పెట్టడానికి డబ్బు వున్నది. తర్జుమాచేయించి యివ్వడానికి డబ్బులేదంటారు. ఈ బడ్జెటులో ఖర్చుచూస్తే నూటికి ౬౦ వంతులు డెడ్రోగల డెడర పోషనానికే వున్నది. కాని దేశము ఎట్లాబాగు పడుతుంది, దానికి ఏ విధముగా బడ్జెటు తయారుచేయాలి అనే విషయం ఆలోచించుటలేదు. డెడ్రోగలకు ధనికులకు సౌకర్యాల తక్కువని చూస్తున్నారు. ధనవంతుల విస్తారాలలో అంచున నంచుకునే కారులు తక్కువప్రతాయని చూస్తున్నారు. కుండలో బియ్యము కుండలో వుండాలి, చుట్టాలు కడుపునిండాతిని విస్తళ్లు బయటపారేయాలంటే ఎట్లా కదురుతుంది? ముందు మేముకూడా కాంగ్రెసులో వున్నప్పుడు, అప్పుడు మీరు చెప్పిన నీతులు, చేసిన వాగ్దానాలు, అవి అన్నీకూడా మరచిపోయినారు.

అల్పుడైనవాని కధికభాగ్యముగల్గి దొడ్డవారిసెల్లదొంగ గొట్టు,
చెప్పలేన్న కుక్క చెరుకు తీపెరుగునా,
విశ్వధాభీరామ వినురవేము.

అని యీమోస్తరుగా ఈ పద్ధతిలో చెప్పబడిన లోకోక్తి అబద్ధముకాదు. ఇదీవరకుండే ప్రభుత్వములో జరిగిన పరిపాలన మనకందరకు తెలుసును. ప్రపంచములోపల వున్నదొంగతనాలు లంజరికాలు, లంచగొండితనాలు యివన్నీ పోవాలంటే, కావాలని మధ్యము తయారుచేసి, వాటి నన్నింటినీ అణచాలంటే ఎట్లా? మధ్యపానము వున్నందువలన మనము ఫలితములు చూస్తున్నాము. ఖరీదే చేసేవారు నూటికి ౯౦ వంతుల సారా, కల్లు త్రాగనిదీ వుండరు. దాని ఫలితకు దొంగతనాలు మొదలైనవి. ఈ విధముగా వుంటే మనదేశము ఏ విధముగా బాగు పడుతుంది? గాంధీ మహాత్ముడు ఏమి చెప్పినాడు? మనకు రామరాజ్యము కావాలంటే యిటువంటిదొంగ లక్ష్యాలు వుండకూడదు. ఏదైతే తమరు అబ్బారీ శాఖ అంటున్నారో, దానిని నేను అవకారీశాఖ అని అంటాను. దానివలన ప్రజలకు మేలులేదు. ఈ విధముగా వుంటే లోక కల్యాణము

ఎట్లాజరుగుతుంది? ఇక్కడ ఏదైనా బిల్లు తెచ్చినప్పుడు బొంబాయిలో అట్లావున్నదీ, మద్రాసు లో యిట్లా వున్నదీ అని చెబుతారు. కాని ఈ మధ్యము విషయములో అక్కడనేషేధము వున్నట్లు ఇక్కడ ఎందుకు చేయరు? ఏదైనా యితర రాష్ట్రములనుంచి ఉదహరణ తీసుకుంటే మంచి విషయాలు తీసుకోవాలిగాని చెడ్డవిషయాలు తీసుకోరాదు. దానివలన లాభములేదు. దేశము బాగు పడాలంటే దానికి కష్టపడాలి. ఇదీవరకు ప్రభుత్వములోని ఉద్యోగులే యిప్పుడు వున్నారు. పోలీసుయాక్టును తరువాత ఏమైనా మార్పు వచ్చినదా? ఈ ప్రజాతంత్ర పరిపాలనలో ప్రజలకు సుఖము కలుగుతోందా అంటే ఏమిలేదు. దీనినిమనము మనము చూస్తున్నాము లంచగొండితనము మిక్కిలి అధికమౌతోంది. మేము పల్లెలలో చూస్తున్నాము. గిరిజార నడిగితే ఈ లంచగొండితనము మీదనుంచి వుందని చెబుతాడు. దీపము క్రింద చీకటి లేదు. దీపము పైన చీకటి వున్నదీ. మీద నుంచికూడా లంచగొండితనము వస్తోంది. పోలీసు యాజ్ఞకు ముందు మిర్చా ఇస్కాయల్ ముఖ్యమంత్రిగా వుండేవారు. ప్రతి పల్లెలోను పట్టణ పట్టణ రీలుకూడా భయపడేవారు. ఉద్యోగస్తులందరికీ తెలుసు. లంచము అంటే భయముగావుండేది ఇప్పుడు చూస్తున్నాము. ప్రజలచే ఎన్నుకొనబడివచ్చిన ఘన మంత్రులైనారు. కాని పరిపాలన ఏవిధముగా సాగుచున్నదీ? మా హాల్కూలో ఒక కేసు వున్నదీ. అక్కడ ముంతజం, ఎవరైతే చంపబడెనో వాని భార్యనుంచి పెయ్యి రూపాయలు లంచము తీసుకున్నాడు. అ కేసు ట్రిబునల్ మీదు బడి నడుస్తున్నదీ. ఇటువంటి లంచగొండితనం విషయమై గౌరవమంత్రిలందరికీ తెలుసు. ఇందులో ఎవరికీ తెలియనిది లేదు. లంచగొండి తనాన్ని నిజంగా అణచాలని మీరు తలచుకుంటే ఒక వారము లోపల అణిగి పోతుంది. కాని యిప్పుడు లేదు. నేను మువ్వాటికి చెబుతున్నాను. మీరూ యిప్పుడదరు. ఇక్కడ ౧౩ మంత్రులను ౧౦ చేసి, ౧౦ మందిని ౧౬ చేసి శక్తిమీకుంది. లంచ గొండితనమును కూడా ఆపివేయదలచుకుంటే ఒక వారము రోజులలోపల అగిపోతుంది. మీరు గట్టిగా గొంధిమహాత్ముని పేరుచెప్పి, ఘోరమీద చేయిపెసుకొని చెప్పండి. మీరు ఈ లంచ గొండితనాన్ని అణచదలచుకుంటే ఒక-వారము రోజులలో అణచివేయవచ్చును. కాని మీరు చేయదలచుకోలేదు. ప్రజలకు చెప్పినదంతా నీటుమీద వచ్చి కూర్చున్నతరువాత మరచిపోయారు. ఒకసారి పెనక్కు తిరిగి చూసుకోండి. ప్రజాపరిపాలన వచ్చి ఏమిమేలుచేసింది? దేశము బాగు పడాలంటే ఎన్నవసలు చేయవలసియున్నదీ. మంచి పరిపాలన, చేసే ప్రజలను చైతన్యవంతులను చేయవచ్చును. మిగతా రాష్ట్రములకు మనము మార్గదర్శకులము కావచ్చును. మనపేరు ఇతి హాసములో వుంటుంది. కాని అది చేయదలచుకో లేదు. ఇంకా ఇక్కడమీము చూస్తున్నాము, ఎటువంటి చిత్తమో అటువంటి లక్ష్యము వుంటుంది. ఎటువంటి లక్ష్యమో అటువంటి గుణము వుంటుంది. కాంగ్రెసువారికి మహాత్మాగాంధీ చెప్పినదేమిటి? వారినినాదాతేమిటి? దున్నే వానికే భూమి అని చెప్పి ఈనాడు వాళ్లకు శ్రేమకరంగా చేసిన దేమున్నదీ? ఏమిలేదు. వాళ్లకు భౌసా ఫారముల విషయములో ఏమౌతున్నదో చూడండి. గౌరవలీ కప్పుకుపోయి చూడండి. మనకు రామరాజ్యము కావాలంటాము. రామరాజ్యములో రాముడు ఏమిచేసినాడు? ప్రజల కష్టసుఖములు తెలుసుకొనేందుకు గొంగళికప్పుకొని వీధివీధి తిరిగేవారు. అన్నివిషయాలు తెలుసుకొనేవారు. ఈ మంత్రులు బోరాకు పోయేషుండు కలెక్టర్లకు తెలుపుతారు. ఫతాని లేవిన మంత్రులనున్నారు, ఫతాని చోట పర్యటనము చేస్తారు, ఫతాని చోట భోజనము చేస్తారు, ఫతాని చోట బహిర్దేశానికి వెళ్తారు అని తెలియ పరచడం జరుగుతోంది. కాని ఉద్యోగులకు తేలికపాటూ, కుటుంబకష్టం ఏమో చూడండి. భౌసాఫారము విషయములో లంచగొండి

తనము ఎంతజరుగుతున్నదో చూడండి. ఒక్క సర్వే సెంటరులో ౬౦ మందే పాతున్నవారున్నారు. వారందరికీ ఒకటి ఫారము. ౬౦ ఫారములులేవు. డబ్బులు యిస్తే రిజిస్టరు చేసి దానికన్న ఎక్కువ పిలువగా భర్తీ చేస్తున్నారు. ప్రజలకు తాదాము కలుగజేస్తున్నమనుకుంటున్నారు. కాని అక్కడ పరి పాలనలో ఆ విధముగా నడుస్తోంది. బస్సుల విషయములో చూడండి. అదీ కూడా చాలా అన్యాయముగా వున్నది. మేమందరము బస్సులలోనే పోతాము. ఇప్పుడున్న మంత్రిలు బస్సులు ఎక్కురు. మేము పూర్వము రీతిగానే ఎక్కుతున్నాము. కాని వాటిల్లో ఏమీ మార్పు రాలేదు. పూర్వము మాదిరిగానే పరిపాలన నడుస్తోంది. కాని మీరు చేయదలచుకుంటే మార్పు తీసుకురావచ్చును, కాని ఏమీ చేయుటలేదు, జంగ్లత్ విషయములో చూస్తున్నాము. కాగితాలమీద ఒకటి, అనుభవములో ఒకటి జరుగుచున్నది. అధికారము వున్నవారికి అనుభవములేదు. అనుభవమున్నవారికి అధికారములేదు. ఎద్దు వున్నవానికి బుద్ధిలేదు. బుద్ధి వున్న వానికి ఎద్దులేదు; అని లోకోక్తి వున్నది. జంగ్లత్ విషయములో చూస్తే, ఛోకిదార్లు విషయము చెబుతారు. ఒకపారి గౌరవనీయుమంత్రి గారు నిర్మల్ తాలూకాకు వచ్చినప్పుడు దాని ప్రక్కన ౬ మైళ్ల దూరములో వున్న ప్రాంతము చూద్దామంటే “లేదండీ, మాకు కమిటీ ఉన్నది” అన్నారు. అయితే జంగ్లత్ లోపల ఎన్ని చెట్లు వున్నవి? ఎన్ని కొట్టబడుచున్నవి, అక్కడ మేకలు అవ్వీ ఎక్కడ మేస్తున్నవి? మేము చూస్తున్నాము అక్కడ ఛోకిదారు పైన సహారాదారుంటారు, అమీన్ సాహేబ్ వుంటాడు, పైన మదద్ గార్ వుంటాడు, అక్కడ కిందనుంచి మీదాకా లంచగండితనంవుంది. అడవి ప్రాంతాల్లో, పక్కన వుండే గ్రామాల్లోని మేకలు ఎక్కడ మేస్తున్నాయి? ఆకాశములో మేస్తున్నాయా? మన వద్ద సి. ఐ. డి. గుప్త రహస్య భటులున్నారు, వారు ఏమిచేస్తున్నారు? ఎక్కడ మేస్తున్నారు? ఏమీ తెలియదు. మన చేతుల్లోకి ప్రజారాజ్యము రాక పూర్వము మనకున్న ఉల్లాసము, ఊహ గనుక యిప్పుడుంటే ఎంతో మేలు జరిగింది. కాని అదేమీ యిప్పుడు కనబడటం లేదు. అక్కడ ఒక్కొక్క మేకకు నాలుగు రూపాయల చొప్పున యిచ్చి అడవిలో మేపుకుంటున్నారు. ఇది మదద్ గారుకు తెలుసు. అక్కడ పిల్లలొకడారుంటారు. మేము ప్రశ్న చేస్తే “మాకు ఆర్డర్లు వున్నాయి” అని చెప్పారు. అక్కడ అందరికీ తెలుసు, అడివి అంతా సత్యానాశ్ అవుతోందని తెలుసు. కాని ఈ ప్రభుత్వము వచ్చిన తరువాత కూడా ఏమీ అక్కడమార్పులేదు. పూర్వపు రీతిగానే నడుస్తోంది. పూర్వము ప్రభుత్వములో వున్నవారు యిప్పుడు వున్నారు. వారి అధికారము పోయినదని చెప్పి వృద్ధయములోపల కపటములేకుండా ...

శ్రీ రామిరెడ్డి : అసలు విషయమును గురించి మాట్లాడండి.

శ్రీ గంగారెడ్డి :—జంగ్లత్ విషయం బడ్జెటులో వుంది. దానిని గురించి మాట్లాడుతున్నాను. పోలీసులు వున్న వారీపలన మేలు ఏమంటే యిప్పుడు చూస్తున్నాము, ఎన్ఫోర్స్ మెంట్లు అవుతున్నాయి. మేము ప్రభుత్వములో ఖరీదీలు కానివ్వకుండా చూడమని చెబుతున్నాము. మధ్యలో రాలాకాలో ౪౦ ఖరీదీలు అయినాయి. అవి ఎందుకు అవుతున్నాయి? గొడ్డలిపట్టి తోనుకొనే ఖరీదీ రోగము వుట్టిందా? ఆ వాళ్ళు, జాలుమ్ అవుతున్నామని దరఖాస్తులు పెడితే ఏమీ చర్య తీసుకోలేదు, మేము కూడా ఏమీగు చెందాము.

ఇప్పుడు ఏదైనామన గురించి చెబుతాను. దీనిని గురించి ఇదీనరకు అనేకసార్లు చెప్పాను. ఒక ఉపాధ్యాయుని ౨౦ ఏండ్లనుంచి ఒకవోటనే ఉంచుతున్నారు. ఇంకోచోట, పంతుళ్ళను రెండు మూడు మాసాల కొకసారి, అక్కడనుంచి ఇక్కడికి ఇక్కడినుంచి అక్కడికి పోస్తారు. దీనిని గురించి

నేను అనేకసార్లు ప్రశ్నలు పేశాను. ప్రభుత్వము బదనామీ కాకుండా డెండాలంటే మేం అడిగిన ప్రశ్నలన్నింటికీ సరైన సమాధానాలు ఇవ్వాలి. ఇప్పుడు ప్రభుత్వ పద్ధతి చూస్తే, “పిల్లి కళ్ళు మూసుకొని పాలు త్రాగుతు, తనను ఎవరూ చూడటం లేదని అనుకొన్నట్లు” ఉన్నది. పిల్లి కళ్ళు మూసుకొనే పాలు త్రాగుతుంది. కాని పాలన్నీ అయిపోతాయి. ఓరాయిల్ విషయం బీదల విషయం మన ప్రభుత్వము ఆలోచించడంలేదు. మనుష్యులకు పైద్యము చేసేటటువంటి వాళ్ళే తేరుగాని ఇక, పశువులకు చెట్లకు ఇంజక్షన్లు చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. పశువుల ఆరోగ్యం విషయం ఎవరు చూచున్నారు? కాని ఎలక్ష్‌స్ వచ్చినపుడు మాత్రం ఎద్దుబొమ్మ పెట్టుకొంటే సరిపోతుంది. లుతేగాని, పశువులకు పైద్యం చేసేందుకు పశువుల పైద్యశాలలుగాని, పశువులకు బలం శక్తి కలగజేసే విషయమైగాని అందుకొరకు ప్రభుత్వము ఏమీ ప్రయత్నించడం లేదు. పూర్వపు పరిపాలన ఎట్లా ఉన్నదో, ఇప్పుడు యీ కాంగ్రెసు పరిపాలన అలాగే ఉన్నది. పూర్వము రాజు వుంటే, ఇప్పుడు ఆ రాజు రాజప్రముఖ్ అయినాడు. అదే పాలము, అదే చెట్టు చెట్టు అదే వుంటే పండ్లు వేరే ఎట్లా వస్తాయి? అదే చెట్లకు మంచివిరువులు పేసినా వేరే మంచి పండ్లు ఎలా పండుతాయి? పూర్వం ప్రభుత్వము ఎవరి క్రిందనైతే ఉన్నదో, ఇప్పుడు వారిక్రిందనే ఉన్నది. పూర్వము రాజు క్రిందనే యీ ప్రభుత్వము ఉండబట్టి దీని నీతి కూడ అలాగే ఉన్నది.

ఇక, కొవ్వధార విషయం చూస్తే, పైద్యులకు సనదు ఉంటాయి. సనదు లేనివారు కూడా పైద్యము నేర్చుకొని చేస్తున్నారు. పోలీసుశాఖను చూస్తున్నాము. ఈ శాఖ కానూన్‌లను ఎలా అమలు జరుపుతాందో చూడవలసిఉన్నది. బాల్యవివాహ నిషేధము కానూన్ మన స్టేటు లోపలగూడ పెట్టారు. ఇప్పుడు యీ బాల్య వివాహ నిషేధము కానూన్ ప్రకారము యీ స్టేటు లోని ఎన్ని కేసులను పట్టుకొన్నారు?—అనేది చూస్తే ప్రభుత్వము ఏమీ కేసులను పట్టుకోలేదు. కాని గ్రామాలలోపల ఎన్నో కేసులు జరుగుతున్నాయి. గ్రామాలలోపల కాన్ని వేల బాల్యవివాహాలు జరుగు తున్నాయి. వీటిని గురించి ప్రభుత్వము ఏమి చేసింది? ఈ స్టేటులో కూడా ఆ కానూన్ పెట్టించాము, కాని తాళం ఏమిటి? మనం ఏన్నో కానూన్‌లు తొచ్చాం, అవి ఏమీ సరిగా అమలు జరగడంలేదు. అవన్నీ పూర్వం లాగానే ఉన్నవి. కానూన్‌లను సక్రమంగా అమలుపరచడం కోసం ప్రశాస్వామ్య ప్రభుత్వం వచ్చింది. కాని యీ ప్రభుత్వములో కూడా కానూన్‌ల సరిగా అమలుజరగడంలేదు. అట్లాగే బాల్యవివాహనిషేధం కానూన్ అమలు జరగడం లేదు. ఈ కానూన్ గురించి గ్రామాలలో దండోరా వేస్తే అందరికీ దీనినిగురించి తెలుస్తుంది.

హరిజనుల విషయమై మేలు చేశామని చెప్పారు, హరిజనులకు ఏమీ మేలు చేశారు? బ్రాహ్మనుడు బయటి స్టేటునుంచి వచ్చి, తాను హరిజనుడనని చెప్పకొంటే, ఆ బ్రాహ్మడికి హరి జనుడని చెప్పి ఒక పదవి కట్టుబెడుతోంది. అంతేగాని అసత్యైన మాలవానికి ఏమీ చేసింది? మాలవాదిగలకు సర్కార్‌వాతీ ఏమీ సౌకర్యాలు చేయడంలేదు. ఖారీజ్ కాలా భూములు, పోరంబోకు భూములను ఎంతో కాలం జాగీరుదార్లు పీల్చిపిప్పిచేసిన భూములను హరిజనులకు కట్టబెట్టారు. ఖారీజ్ కాలా భూములలోని సారము అంతా పీల్చేసిన తరువాత సారము లేని భూమిని తీసి పారేసిన విస్తరి ఇచ్చినట్లుగా హరిజనులకు ఇచ్చారు. ఇప్పుడు చూస్తున్నాము. దేశంలో ధనవంతులు ఒక కన్ను, బీదవాళ్ళు ఒక కన్ను, ఈ రెండు కళ్ళను సమానంగా చూడాలి.

“हिंदू मुस्लीमों के लिये दोनों मेरी” आखें एक है।

అన్నట్లుగా ఉంది. ఈ విధముగా హరిజనులకు తిని పారేసిన విస్తరి తాంటి భూములు ఇచ్చినందున, ఆ తిని పారేసిన విస్తరిలోని పుల్లలు వారి వోట్ల గుచ్చికాని ఎంతోమంది మరణించారు. ఈ విధముగా ఉన్నది. ఖరీజ్ కాలా భూములను హరిజనులకు ఇవ్వడంలో ఆలస్యం అవుతోంది, వీరికి భూములు ఇవ్వడంలో చివరకు, రెవిన్యూబోర్డుదాకా పోవాలి. ౪౦ ఎకరాల భూమిని ఒక గ్రామంలోని మాలమాదీగలు చేసుకొంటే, ఆ గ్రామంలోని కాపు వారీనుంచి భూమిని తాక్కిని ఆ భూమినుంచి పెళ్లగొట్టటానికి గుంజాయిమ్ లేకుండా ఉంది. ప్రభుత్వం చెప్పేది ఒకటి; చేసేది ఒకటి. ఈ విధముగా ఉంది. ఎలక్షన్ అప్పుడు ఏ విధముగా పోయి ప్రజలకు చెప్పివచ్చాము?—అనేది చూడాలి.

[Mr. Deputy Speaker in the chair]

ఇక, విద్యావిషయం చూస్తే చదువు విషయమై ప్రభుత్వమువారు చాలా శ్రమపడుతున్నారని అంటున్నారు. ఒక సంగతి చెబుతాను. మా గ్రామం సంగతి చూస్తే విచిత్రంగా ఉంది. మా ఊళ్లో బడి నిర్మాణం చేస్తున్నారు. కట్టడానికి కంట్రీబ్యూషన్ ఇచ్చారు. కొన్నిచోట్ల రూపాయ పావతా, రూపాయకి ఎనిమిది గంటలు కంట్రీబ్యూషన్ చేయమనిచెప్పారు. మా గ్రామానికి చదువుకొనేందుకు ౪౦ మంది పిల్లలు వస్తున్నారు. కానీ, వారికి చదువు చెప్పడానికి ౫ మాసాల నుంచి పంతుళ్లు లేరు. పెహజరు పెట్టుకొంటే ఇద్దరు పంతుళ్లును తోతారు. వారికి వుండటానికి ఇళ్లు లేవు. వారికి ఏమి సౌకర్యాలు లేవు.

ఆహారం విషయం చూడండి. అన్నంతినేచోట జొన్నలు పంపుతున్నారు. జొన్నలు తినేచోట బియ్యం పంపుతున్నారు. విద్యావిషయంలోగాని, సౌకర్యాల దౌరా విషయంలోగాని మార్పు రావాలి.

ఈ గ్రెయిన్ బ్యాంక్ రజాకార్లు ప్రభుత్వములో ఎలా ఉందో యీ ప్రభుత్వములోనూ అలాగే ఉంది. దీని విషయం ఆలోచించడములేదు. మన ప్రజాప్రతినిధులు వచ్చినాక కూడా.....

مسٹر ڈپٹی اسپیکر - آپ اور کتنا وقت لیتے ؟

مسٹر ڈپٹی اسپیکر مجھے اب کچھ اناؤنس (Announce) کرنا ہے - کس منسٹر کے ڈیمانڈس فار گرانٹس (Demands for grants) کس تاریخ کو پیش کئے جائیں گے ؟
میں سلسلہ وار سناتا چاہتا ہوں -

श्री. गोपिबि गंगा रेडी : —मैतो और दो चार विषयों पर बोलना चाहता हूँ । मुझको यदि एकमौका दिया जायेगा तो मैकल शुक्रमें बोलुंगा ।

[Statement.]

The order in which the Demands for Grants will be taken up for discussion.

DEMANDS FOR GRANTS FOR THE YEAR 1954-55.

Things of the House	Minister-in-charge	Demand Numbers	Day and date on which the Demands will be taken up for discussion	Date and time of giving notice of motion for reduction
1. 2-30 to 8 p.m.	.. Chief Minister	14, 47, 48, 54, 55, 56, 62, 68 and 74.	Thursday, the 11th and Friday, the 12th March 1954.	9th March, 1954 5 p.m.
2. 2-30 to 8 p.m.	.. Minister for Home, Law and Rehabilitation.	8, 16, 18, 19, 20, 61, 75, 79, 80, 81 and 93.	Monday, the 15th and Tuesday, the 16th March 1954.	13th March, 1954 4-30 p.m.
3. 2-30 to 8 p.m.	.. Minister for Agriculture, Supply, Development and Planning.	82, 44, 49, 70, 78, 88 and 95.	Monday, the 22nd March 1954.	17th March, 1954 4-30 p.m.
4. 2-30 to 8 p.m.	.. Minister for Public Health, Medical and Rural Reconstruction.	26, 27, 33, 34, 35 and 37.	Tuesday, the 23rd March, 1954.	17th March, 1954 4-30 p.m.
5. 2-30 to 8 p.m.	.. Minister for Education and Local Government.	15, 22, 24, 25, 30, 31, 41, 42, 53, 57, 69, 72, 85 and 90.	Wednesday, the 24th March, 1954.	22nd March, 1954 4-30 p.m.
6. 2-30 to 8 p.m.	.. Minister for Excise, Forests and Revenue.	2, 3, 4, 6, 7, 58, 71, 73 and 76.	Thursday, the 25th March, 1954.	23rd March, 1954 4-30 p.m.
7. 9 a.m. to 12 Noon & 4 p.m. to 8 p.m.	Minister for Public Works and Labour.	11, 12, 13, 23, 28, 29, 38, 39, 43, 46, 52, 59, 60, 67, 84, 86, 87, 88, 89, 91 and 92.	Friday, the 26th March, 1954.	24th March, 1954 4-30 p.m.
8. 9 a.m. to 12 Noon & 4 p.m. to 8 p.m.	Minister for Finance, Statistics, Customs, Commerce & Industries.	1, 5, 9, 10, 17, 21, 36, 40, 43, 50, 51, 63, 64, 65, 66, 77, 82, 84, 96 and 97.	Monday, the 29th March 1954.	26th March, 1954 4-30 p.m.

*The House then adjourned till Half Past Two of the Clock
on Tuesday, the 9th March, 1954.*
